वर्ष: 5 अंक:2 फरवरी, 2025 मूल्य: 60 रु.

राजस्थान टुडे

समावेशी व विकसित भारत को समर्पित बजट

पेज 5-7

चुनावी राजनीति पर

मुफ्त का मुल्लमा

पेज 15-16

आरएमजीबी RMGB

राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक

भारत सरकार का उपक्रम

प्रधान कार्यालय, तुलसी टॉवर, 9वी बी रोड़, सरदारपुरा, जोधपुर।

फोनः 029192593100 Mail: leads@rmgb.in

अपने घर को मुफ्त बिजली

और सौर ऊर्जा का उपहार दें

ब्याज दर 7%*
से प्रारंभ

₹
lrrr
तक की सब्सिडी
उपलब्ध*

RMGB सूर्य घर योजना

हर घर में सोलर ... हर घर में ऊर्जा ...

- ☑ 3 KW पर 2 लाख, 10 KW पर 6 लाख तक का लोन
- ☑ ब्याज दर 7%* से प्रारंभ
- ☑ 10% मार्जिन पर
- ☑ भुगतान 10 वर्ष तक
- ☑ शून्य प्रोसेसिंग शुल्क एवं पूर्व भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं

सोलर पैनल के विक्रेता/डीलर अपने व्यवसाय की वृद्धि के लिए RMGB के क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।

*नियम व शर्तें लागू

● सभी प्रकार के कृषि ऋण ● होम लोन ● पर्सनल ऋण ● मोरगेज लोन ● शिक्षा ऋण ● MSME ऋण

अधिक एवं विस्तृत जानकारी के लिए बैंक की निकटवर्ती शाखा में सम्पर्क करें अथवा www.rmgb.in पर विजिट करें

राजस्थान टुडे

n n

n otrtrossy

वर्ष 5, अंक 2, फरवरी, 2025

(प्रत्येक माह 15 तारीख को प्रकाशित)

सुर्खियां

केंद्रीय बजट

समावेशी व विकसित भारत को समर्पित बजट

कूटनीति

नए तरह के राष्ट्रवाद से साबका

राजनीति

SW

इंडिया गठबंधन की प्रासंगिकता पर सवाल

महाकुंभ

ty

संगम की डुबकी मोक्ष बनाम माया

t mvsn कामकाजः समय नहीं गुणवत्ता जरूरी

t s. साइबर क्राइमः साइबर अरेस्ट रोकथाम के लिए अब AI औजारों की दरकार

प्रदेश गौरव

पेज 33

शब्द-शब्द दरपण

शीन काफ़ निज़ाम

ssnst . राजनीतिः भाजपाः किसके सिर सजेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का ताज़?

s n3 . राजनीतिः हमार बांग्ला को अमार बांग्ला अभी दूर क्यों?

w| nw . भक्ति परंपराः राजस्थान की सगुण भक्ति परंपरा में एक अनमोल धरोहर मीराँबाई

प्रधान सम्पादक

दिनेश रामावत

संपादकीय कार्यालय

बी-4, फोर्थ फ्लोर, एम.आर. हाईट्स

महावीर कॉलोनी, भास्कर सर्किल,

रातानाड़ा, जोधपुर - 342011

व्हाट्सएप नंबर - 9828032424

ई-मेल - n

सभी विवादों का निपटारा जोधपुर की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों और फोरमों में किया जाएगा।

राजस्थान टुडे में प्रकाशित आलेख लेखकों की राय है। इसे राजस्थान टुडे की राय नहीं समझा जाए। राजस्थान टुडे के मुद्रक, प्रकाशक और सम्पादक इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। हमारी भावना किसी वर्ग या व्यक्ति को आहत करना नहीं है। विज्ञापनदाताओं के किसी भी दावे का उत्तरदायित्व राजस्थान टुडे का नहीं होगा।

• मारवाड़ मीडिया प्लस के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक पूनम अस्थाना द्वारा बी-4, फोर्थ फ्लोर, महावीर कॉलोनी, रातानाड़ा, जोधपुर-342011 से प्रकाशित और डी.बी. कॉर्प लिमिटेड, 01 पार्श्वनाथ इंडस्ट्रीयल एरिया, रिलायंस वेयर हाउस के पास, मोगरा कलां, जोधपुर-342802 में मुद्रित, संपादक: अजय अस्थाना।

सम्पादकीय

राहतों का अमृत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अपना लगातार आठवां बजट पेश करने के दौरान लम्बा और ऊबाऊ भाषण देने से परहेज किया, लेकिन इस बार के उनके बजट में छिपाते छिपाते भी चुनावी सियासत झलक ही गई। हालांकि उनकी सबसे बड़ी बजट घोषणाओं में सालाना 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर जीरो आयकर ही रहा। इसे मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों के लिए लाभकारी माना गया, लेकिन ये लाभ नौकरीपेशा को कब तक मिलेगा, इस पर उनकी नए आयकर कानून के निर्माण की घोषणा ने असमंजस भी खड़ी की है। वैसे अच्छे अच्छे आर्थिक पंडितों ने भी ये उम्मीद को नहीं की थी कि आयकर छूट की सीमा एकदम सात लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दी जाएगी और सरकारी कर्मचारियों को 75 हजार रुपए की अतिरिक्त छूट भी इसके साथ मिल जाएगी। आयकर में आठ या दस लाख की छूट तक का अंदाज तो लगाया जा रहा था, लेकिन एक साथ इतनी छलांग भले ही चौंकाए, लेकिन इसके पीछे कहीं न कहीं दिल्ली चुनाव भी एक अहम कारण है, इससे इनकार नहीं किया जाना चाहिए। इसका असर दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के उत्तरार्द्ध में नजर भी आया। ये अलग बात है कि इसका चुनाव में भाजपा को कितना फायदा होगा, लेकिन जिस ढंग से प्रधानमंत्री व भाजपा के अन्य नेताओं से इस बजट घोषणा को प्रचार अभियान में भुनाया, इससे साफ हो गया कि सरकार कोई भी हो सियासी फायदे लेने का मौका ढूंढती ही है।

आयकर छूट ही नहीं, बिहार के अगले साल होने वाले चुनावों की छाया भी मोदी-3 सरकार के पहले पूर्ण बजट में साफ नजर आई। मखाना बोर्ड का गठन हो या नए ग्रीन एयर फील्ड का निर्माण और पर्यटन, उच्च शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में बिहार पर मेहरबानी भी इसे ही साबित करती है।

कुल मिलाकर बजट मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। किसानों, एमएसएमई, युवाओं व निर्यातकों के लिए की गई बजट घोषणाएं देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने की सरकार की कोशिशों की ओर इशारा कर रही हैं। भारत कैसे कितना जल्दी दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बने, इस दिशा में प्रयास किए तो जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की रिपोर्ट्स पर भरोसा कर पीठ थपथपाने से कुछ नहीं होगा। ग्राउंड लेवल पर काफी कुछ किए जाने की जरूरत है। गरीबी-बेरोजगारी उन्मूलन के सब्जबाग तो निर्मला सीतारमण की ओर से पेश बजट दिखाता है, लेकिन सब कुछ बजट घोषणाओं का इस अमृत को अंत्योदय की तरह आखिरी आदमी तक पहुंचाने के ईमानदार प्रयासों पर निर्भर करेगा।

रक्षा बजट
थोड़ा है, थोड़े की जरूरत

सुरेश व्यास ✍ वरिष्ठ पत्रकार

देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2025-26 के लिए बजट पेश करते हुए हालांकि सबसे बड़ा हिस्सा रक्षा मंत्रालय को दिया है, लेकिन उनसे रक्षा के लिए इससे कहीं ज्यादा की उम्मीद की जा रही थी। इस साल के बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 6,81,210 करोड़ रुपए के प्रावधान की घोषणा की गई है। इसमें 4,88,822 करोड़ का राजस्व व्यय जिसमें से 1,60,795 करोड़ पेंशन के लिए आरक्षित हैं तथा पूंजीगत व्यय जिससे सेनाओं के लिए विमानों व उपकरणों की खरीद होती है, उस मद में 1,92,387 करोड़ रुपए ही रखे गए हैं। यह रक्षा बजट का मात्र 27.66 फीसदी है। बाकी राशि सैन्य कर्मियों के वेतन भत्तों व पेंशन पर खर्च हो जाएगी।

> अमरीका के बाद चीन रक्षा क्षेत्र में सर्वाधिक खर्च करने वाला देश है। हालांकि इसका रक्षा बजट कुल जीडीपी का लगभग दो प्रतिशत ही होता है, लेकिन उसका ध्यान स्वदेशी रक्षा उत्पादन और आधुनिक प्रोद्योगिकी हासिल करना पर ज्यादा रहता आया है। दक्षिण चीन सागर व ताइवान के आसपास सैन्य विस्तार की गरज से चीन के रक्षा बजट में सर्वाधिक बढ़ोतरी हो रही है।

हालांकि विमान और वैमानिकी इंजनों के लिए 48,614 करोड़ रुपए, अन्य उपकरणों के लिए 63,099 करोड़ और नौसेना बेड़े के लिए 24,390 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। इस साल का रक्षा बजट पिछले साल के बजट से 9.5 फीसदी ज्यादा भी है। लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, दुनिया में रूस-यूक्रेन व इस्त्रायल-फलीस्तीन युद्ध के साथ उथल पुथल के चलते सप्लाई चैन प्रभावित हुई है और भारत के समक्ष चीन व पाकिस्तान की दोहरी चुनौती बढ़ती जा रही है, उसे देखते हुए इस राशि से पार पड़ना मुश्किल ही नजर आता है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साल 2025 को रक्षा क्षेत्र में सुधार करने का साल घोषित किया है। इसके तहत एकीकृत थिएटर कमांड, साइबर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जरूरी क्षेत्रों, सरल और समयबद्ध अधिग्रहण, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में काम किए जाने है। साथ ही रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण व सशस्त्र बलों की क्षमता को मजबूत करने के लिए कई नई योजनाएं लाई जा रही है। इस हिसाब से रक्षा बजट और बढ़ाए जाने की उम्मीद की जा रही थी।

आज दुनिया भर में जगह-जगह युद्ध, गृह युद्ध और संघर्ष चल रहे हैं। वहीं भारत को चीन और पाकिस्तान जैसे अपने पड़ोसियों से भी चुनौतियां मिल रही हैं। चीन-पाकिस्तान के साथ इन दिनों बांग्लादेश के साथ भी संबंधों में उतार-चढ़ाव आ रहे हैं। इन हालात में रक्षा क्षमताओं को उच्चतम स्तर पर ले जाने की जरूरत के अनुरूप रक्षा बजट में बढ़ोतरी नहीं हुई।

रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि वैश्विक रक्षा खर्च में हालांकि भारत का हिस्सा बढ़कर चार प्रतिशत पहुंच गया है, लेकिन चीन और पाकिस्तान से मिल रही चुनौतियों के मुकाबले देखा जाए तो देश का रक्षा बजट अब भी जीडीपी का बमुश्किल दो फीसदी है। अमरीका अपनी जीडीपी का साढ़े तीन से चार प्रतिशत हिस्सा रक्षा बजट में खर्च करता है। इसका बड़ा हिस्सा नए हथियार, साइबर सुरक्षा, रणनीतिक सैन्य ठिकानों के रखरखाव व स्पेस डिफेंस प्रोग्राम में खर्च होता है। पिछले साल अमरीका का रक्षा बजट इस क्षेत्र में ज्यादा खर्च करने वाले नौ देशों के कुल खर्चे से भी ज्यादा था।

रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार भारत को कंपटीशन में बने रहने के लिए अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) पर खर्च बढ़ाने की दिशा में भी सोचना चाहिए। अमरीका आर एंड डी पर अपने रक्षा बजट का 13 फीसदी खर्च करता है। जानकार कहते हैं कि अमरीका आरएंडडी पर अपने रक्षा बजट का लगभग 13 प्रतिशत हिस्सा खर्च करता है और भारत के रक्षा बजट में इस मद के लिए मुश्किल से एक प्रतिशत हिस्से आता है। आर एंड डी पर बजट की कमी से हाइपरसोनिक हथियार, एआई और क्वांटम प्रौद्योगिकियों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रगति सीमित हो जाती है, जबकि भारत के सामने पाकिस्तान और चीन की चुनौतियां लगातार बढ़ रही है।

मौजूदा हालात को देखते हुए सेना की जरूरतें बढ़ रही है। थल सेना को अत्याधुनिक हथियार चाहिएं और वायुसेना पहले से ही लड़ाकू विमानों की कमी झेल रही है। वायुसेना के पास निर्धारित लड़ाकू विमानों की निर्धारित 42 स्क्वाड्रन के मुकाबले लगभग तीस स्क्वाड्रन की बची है। पुराने विमान फेज आउट होते जा रहे हैं और नए विमानों की खरीद को पर्याप्त वित्त पोषण नहीं मिल रहा। हालांकि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर पिछले पांच साल में काफी जोर दिया गया है, लेकिन स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस मार्क-2 और एडवांस मल्टीरोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे जरूरी प्रोजेक्ट्स को रफ्तार देने के लिए बजट में पूंजीगत व्यय बढ़ाने की उम्मीद भी पूरी होती नजर नहीं आई।

समावेशी व विकसित भारत को समर्पित बजट

प्रो. गौरव वल्लभ
प्रोफेसर (वित्त),
एक्सएलआरआई
जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट
और बीजेपी नेता

केंद्रीय बजट 2025-26 पेश हो चुका है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के अटूट दृष्टिकोण की पुष्टि करता है। पिछले दशक में, स्थिर लक्ष्य के साथ कृषि, एमएसएमई, युवा सशक्तिकरण, वैश्विक व्यापार और मध्यम वर्ग कल्याण में परिवर्तनकारी सुधारों ने भारत के आर्थिक प्रक्षेप पथ को फिर से परिभाषित किया है।

इस अशांत वैश्विक समय में, बजट आशा की किरण बनकर उभरता है। व्यावहारिक फिर भी साहसिक, दूरदर्शी फिर भी वास्तविकता में निहित, यह एक ऐसे भविष्य के निर्माण के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है जहां विकास समावेशी है, अवसर असीमित हैं, और वैश्विक मंच पर भारत का उदय अजेय बना हुआ है।

भारतीय मध्यम वर्ग अब मूक दर्शक नहीं है; यह देश के भविष्य को आकार देने वाली एक गतिशील शक्ति है। पिछले एक दशक में, 25 करोड़ से अधिक भारतीयों ने गरीबी से बाहर निकलकर खेल, स्टार्ट-अप, अंतरिक्ष अन्वेषण और तकनीकी प्रगति जैसे क्षेत्रों में आकांक्षाओं को बढ़ावा दिया है। यह बजट पिछली प्रतिबद्धताओं पर आधारित है, जो निरंतर वित्तीय राहत और सशक्तिकरण सुनिश्चित करता है

कर छूट सीमा में लगातार वृद्धि, अधिक वित्तीय राहत प्रदान करती है और लाखों करदाताओं को सशक्त बनाती है। 2014 में 2.5 लाख से 2019 में 5 लाख, फिर 2023 में 7 लाख, और अब 2025 में उल्लेखनीय 12 लाख - इस लगातार विस्तार ने, पहली बार, मध्यम वर्ग के एक विशाल बहुमत को व्यक्तिगत आयकर का भुगतान करने का बोझ से पूरी तरह से बाहर कर दिया है। नई कर व्यवस्था के तहत, 12 लाख कमाने वाले करदाता को 80,000 का पर्याप्त लाभ मिलेगा - जिससे मौजूदा दरों के तहत उनकी संपूर्ण कर देयता समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब है कि पिछले स्लैब के अनुसार देय कर का 100% अब बच गया है, जिससे व्यक्तियों को अपनी मेहनत से अर्जित आय का अधिक हिस्सा बनाए रखने की अनुमति मिलेगी। और यह ऐसे समय में आया है जब कुल सरकारी प्राप्तियों में आयकर का हिस्सा वास्तव में 19% से बढ़कर 22% हो गया है। यह इसे और भी प्रभावशाली बनाता है - मजबूत कर अनुपालन और तेजी से बढ़ती औपचारिक अर्थव्यवस्था ने यह सुनिश्चित किया है कि व्यापक कर राहत के बावजूद, राजस्व मजबूत और टिकाऊ बना रहे।

एक गहन विचारशील कदम में, सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर कटौती की सीमा को 50,000 से दोगुना करके 1 लाख कर दिया है, उनकी बढ़ती वित्तीय जरूरतों को पहचानते हुए और एक सम्मानजनक, सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित किया है। फिर भी, भले ही कर राहत लाखों लोगों तक बढ़ा दी गई है, राजकोषीय समझदारी सर्वोपरि बनी हुई है। राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी के 4.4% पर निर्धारित किया गया है, जो जिम्मेदार आर्थिक प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

> इसके अतिरिक्त, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर विशेष ध्यान देने के साथ, 5 लाख पहली बार उद्यमियों के लिए 2 करोड़ तक का सावधि ऋण प्रदान करने के लिए एक विशेष योजना शुरू की गई है। ये परिवर्तनकारी उपाय न केवल विकास को बढ़ावा देंगे बल्कि पूरे क्षेत्र में औपचारिकता और रोजगार सृजन को भी बढ़ावा देंगे।

भारत के आर्थिक ताने-बाने के केंद्र में कृषि है - जो लाखों लोगों की जीवनधारा है। यह बजट परिवर्तनकारी पहलों के साथ हमारे किसानों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है: किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से बढ़े हुए ऋण से 7.7 करोड़ किसानों को लाभ होगा, जिससे उन्हें अधिक वित्तीय स्थिरता मिलेगी। कपास उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए एक दूरदर्शी 5-वर्षीय मिशन भारत की कपड़ा प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा, जबकि बिहार में एक समर्पित मखाना बोर्ड की स्थापना विशिष्ट कृषि-उत्पादों में लगे किसानों को महत्वपूर्ण संस्थागत सहायता प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त, दालों में आत्मनिर्भरता के लिए छह साल का रोडमैप आयात निर्भरता को कम करेगा, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और ग्रामीण आय में सुधार करेगा।

भारत में, एमएसएमई अक्सर न केवल परिस्थिति के कारण, बल्कि कभी-कभी इच्छानुसार भी छोटे बने रहते हैं - नियामक जटिलताओं और अनुपालन बोझ से बचने के लिए। हालाँकि, यह सरकार एमएसएमई को छोटी बनी रहने वाली संस्थाओं के रूप में नहीं देखती है; यह उन्हें विकास के गतिशील इंजन के रूप में देखती है, जो आर्थिक परिवर्तन को बढ़ाने, नवाचार करने और चलाने में सक्षम है। इस दृष्टिकोण के अनुरूप, बजट एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए संरचित हस्तक्षेप पेश करता है ताकि वे न केवल जीवित रहें बल्कि फल-फूल सकें, और भारत के औद्योगिक और आर्थिक परिदृश्य में अधिक महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।

एक महत्वपूर्ण कदम में, एमएसएमई वर्गीकरण मानदंडों को संशोधित किया गया है, जिसमें टर्नओवर और निवेश सीमा दोगुनी से अधिक है - नियामक बाधाओं को कम करना और अधिक व्यवसायों को पनपने में सक्षम बनाना। सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को दोगुना कर 10 करोड़ और स्टार्ट-अप के लिए 20 करोड़ कर दिया गया है, जिससे अधिक वित्तीय सुरक्षा और पूंजी तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। वित्तीय समावेशन को सुविधाजनक बनाने के लिए, सूक्ष्म उद्यमों को 5 लाख की सीमा वाले 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे, जिससे वे आसानी से परिचालन का विस्तार कर सकेंगे।

भारत के युवाओं को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हुए, यह बजट शिक्षा, अनुसंधान और कौशल विकास को प्राथमिकता देता है, जो एक गतिशील और समृद्ध भविष्य की नींव रखता है। मुख्य पहलें इस प्रकार हैं

उच्च शिक्षा को मजबूत बनाना

आईआईटी की क्षमताओं का विस्तार और भारतीय भाषा पुस्तक योजना की शुरुआत न केवल उच्च शिक्षा के अवसरों को बढ़ाएगी बल्कि क्षेत्रीय भाषाओं में सीखने को भी बढ़ावा देगी, जिससे शिक्षा अधिक सुलभ और समावेशी बनेगी।

जमीनी स्तर पर नवाचार को बढ़ावा

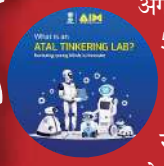

अगले पांच वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना युवा दिमागों को हाथों-हाथ वैज्ञानिक सीखने के साथ सशक्त बनाएगी, बचपन से ही नवाचार की संस्कृति का पोषण करेगी। यह निवेश वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और नवोन्मेषकों की अगली पीढ़ी का विकास करेगा।

स्वास्थ्य सेवा मांगों को पूरा करना

चिकित्सा शिक्षा में बढ़ा हुआ निवेश इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में एक कुशल कार्यबल सुनिश्चित करके राष्ट्र की बढ़ती स्वास्थ्य सेवा जरूरतों को पूरा करेगा। इससे सभी नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार होगा।

डिजिटल डिवाइड को पाटना

सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना डिजिटल डिवाइड को पाटेगा, जिससे स्थान की परवाह किए बिना ज्ञान और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित होगी। यह अधिक डिजिटल रूप से समावेशी भारत की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना

निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान, विकास और नवाचार पहलों के लिए 20,000 करोड़ का पर्याप्त आवंटन भारत की तकनीकी प्रगति को गति देगा और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा। यह निवेश नवाचार को प्रोत्साहित करेगा और आर्थिक विकास को गति देगा।

सरकार की बुनियादी ढांचा विकास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता इस बजट का एक परिभाषित स्तंभ बनी हुई है, जो भारत की आर्थिक परिवर्तन की यात्रा को और मजबूत करती है। पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ—संरचनात्मक सुधारों के लिए प्रोत्साहन से जुड़ा—ध्यान सतत और समावेशी विकास पर दृढ़ता से केंद्रित है। परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना 2025-30, नई परियोजनाओं के लिए 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखते हुए, मौजूदा संपत्तियों से मूल्य अनलॉक करेगी, जबकि नए बुनियादी ढांचे के विस्तार को बढ़ावा देगी। इस बीच, जल जीवन मिशन का 2028 तक विस्तार यह सुनिश्चित करता है कि 100% सुरक्षित पेयजल कवरेज का सपना हर घर के लिए एक वास्तविकता बन जाए, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। ये रणनीतिक निवेश आर्थिक विस्तार को गति देंगे, रोजगार सृजित करेंगे और भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएंगे।

यह बजट प्रगतिशील नियामक सुधारों के माध्यम से भारत को एक अधिक आकर्षक कारोबारी गंतव्य बनाने को प्राथमिकता देता है। एक प्रमुख घटक विश्वास और सिद्धांतों पर आधारित एक नियामक ढांचा स्थापित करना है, जिसे उत्पादकता को बढ़ावा देने और अधिक नौकरियां पैदा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

नियामक सुधारों के लिए उच्च-स्तरीय समिति

यह समिति नियमों को सुव्यवस्थित करने और व्यवसायों, विशेष रूप से छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) के लिए अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए काम करेगी। इससे व्यवसायों को जटिल नौकरशाही प्रक्रियाओं को नेविगेट करने के बजाय विकास और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने की स्वतंत्रता मिलेगी।

जन विश्वास विधेयक 2.0

इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न कानूनों में 100 से अधिक छोटे अपराधों को गैर-अपराधीकरण करना है। इससे छोटे उल्लंघनों के लिए अनावश्यक कानूनी कार्रवाई के डर को कम किया जाएगा और व्यवसायों के लिए अधिक भरोसे का माहौल बनेगा। गैर-अपराधीकरण में अक्सर संभावित जेल की सजा को जुर्माना या अन्य कम गंभीर दंडों से बदलना शामिल होता है, जिससे अधिक संतुलित नियामक दृष्टिकोण बनता है।

इन सुधारों से भारत की कारोबार सुगमता रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है, जिससे अधिक घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित होगा। एक सरल, अधिक पारदर्शी और कम दंडात्मक नियामक वातावरण उद्यमिता, नवाचार और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करेगा, जो भारत के समग्र आर्थिक विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता में योगदान देगा।

वैश्विक नेतृत्व के स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ, सरकार ने भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में निर्बाध रूप से एकीकृत करने के लिए प्रमुख पहलें शुरू की हैं। ये पहलें घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने और भारत की व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

भारत ट्रेड नेट (बी.टी.एन.)

यह एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा मंच अंतरराष्ट्रीय व्यापार दस्तावेज़ीकरण और वित्तपोषण को सुव्यवस्थित करेगा, नौकरशाही बाधाओं को कम करेगा और भारतीय व्यवसायों के लिए सीमा पार व्यापार को आसान और अधिक कुशल बना देगा। इससे निर्यातकों और आयातकों के लिए लेनदेन लागत में उल्लेखनीय कमी और टर्नअराउंड समय में सुधार होने की उम्मीद है।

वैश्विक क्षमता केंद्रों (जी.सी.सी.) के लिए राष्ट्रीय ढांचा

इस ढांचे का उद्देश्य उभरते टियर-2 शहरों को जीसीसी के लिए आकर्षक निवेश केंद्र के रूप में बढ़ावा देना है। इन केंद्रों को आकर्षित करके, भारत वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने के लिए अपने कुशल कार्यबल और रणनीतिक स्थान का लाभ उठा सकता है। इससे उच्च-कुशल नौकरियां भी पैदा होंगी और इन टियर-2 शहरों की स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा मिलेगा।

लक्षित आयात छूट... ताकि भारत विश्व स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बने

बजट में प्रमुख आयातों पर छूट शामिल है, जिनमें 36 जीवन रक्षक दवाएं, एलईडी/एलसीडी टीवी घटक, ईवी बैटरी निर्माण के लिए 35 पूंजीगत वस्तुएं और मोबाइल फोन बैटरी निर्माण के लिए 28 पूंजीगत वस्तुएं शामिल हैं। ये लक्षित छूट रणनीतिक क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और सामर्थ्य में सुधार करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, जिससे भारतीय उद्योग विश्व स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकें।

सीमा शुल्क टैरिफ का युक्तिकरण

सीमा शुल्क टैरिफ संरचना को सरल बनाकर, टैरिफ दरों की संख्या को कम करके, व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता को और बढ़ाया जाएगा। यह युक्तिकरण अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लगे व्यवसायों के लिए जटिलताओं को कम करेगा और भारत के व्यापार व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और अनुमानित बना देगा।

2025-26 का बजट केवल एक बजट नहीं है, बल्कि एक दूरदर्शी बयान है, जो आत्मनिर्भरता, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और साझा समृद्धि की ओर भारत के मार्ग को परिभाषित करता है। किसानों, एमएसएमई, बुनियादी ढांचे और अनुपालन में आसानी पर तीक्ष्ण ध्यान देने के साथ, यह दीर्घकालिक विकास के लिए एक मजबूत मंच तैयार करता है और इस बात को ध्यान में रखता है कि भारत में हर किसी को फलने-फूलने का अवसर मिलना चाहिए। बजटीय समेकन के बावजूद, सरकार ने नागरिक-प्रथम, प्रगतिशील बजट दिया है—एक ऐसा बजट जो उम्मीद जगाता है, निवेश को प्रेरित करता है और राष्ट्रीय विकास को गति देता है।

वो दिन गए जब भारत को नाजुक पांच देशों में गिना जाता था। आज, हम महानता के कगार पर खड़े हैं—जल्द ही दुनिया की सबसे प्रमुख आर्थिक शक्तियों में से एक, व्यवसाय, लचीलापन और वैश्विक प्रभाव में अग्रणी के रूप में पहचाने जाने वाले हैं। संरचनात्मक सुधारों, रणनीतिक निवेशों और भविष्य के लिए तैयार दृष्टिकोण के साथ, भारत न केवल परिवर्तन को नेविगेट कर रहा है बल्कि इसे आकार भी दे रहा है।

विकसित भारत की ओर यात्रा अच्छी तरह से चल रही है, और यह बजट सुनिश्चित करता है कि कोई भी भारतीय पीछे न छूटे। हमारे किसानों के खेतों से लेकर हमारे उद्यमियों की महत्वाकांक्षाओं तक, हमारे युवाओं की आकांक्षाओं से लेकर हमारे वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण तक—यह एक ऐसा बजट है जो सशक्त बनाता है, उत्थान करता है और प्रेरित करता है। भविष्य भारत का है, और अटूट संकल्प के साथ, हम एक ऐसा राष्ट्र बना रहे हैं जो मजबूत, आत्मनिर्भर और अजेय है।

आयकर छूट बढ़ाकर मध्यमवर्ग को रिझाया, हर क्षेत्र में विकास के नए द्वार खोलने के प्रयास

राजस्थान के ऊर्जा, हस्तशिल्प, पर्यटन और एक्सपोर्ट क्षेत्र में संभावनाएं बढ़ी

सीए योगेश बिड़ला
निदेशक, बिरला डब्लूपी
मैनेजमेंट कंपनी, मुंबई

केन्द्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामण द्वारा प्रस्तुत बजट को राष्ट्र के विकास के अनुकूल बनाने का प्रयास किया गया है, ताकि हर क्षेत्र का समूचित विकास संभव हो। यह बजट मध्यम वर्ग को कर राहत, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, और विभिन्न क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाता है।

राजस्थान की समृद्धि का एक नया इतिहास पिछले 12 वर्षों से धीरे- धीरे लिखा जाने लगा है। जब से पश्चिमी राजस्थान में पहली बार क्रूड मिला, पवन चक्कियों से ऊर्जा बननी शुरू हुई, सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट लगने लगे और अन्ततः करीब एक लाख करोड़ के निवेश वाली रिफाइनरी भी अब मूर्त रूप लेने लगी है। राजस्थान के दूसरे हिस्सों में उदयपुर में विदेशी एवं देशी पर्यटन बहुत बढ़ रहा है, डेस्टिनेशन विवाह प्रोजेक्ट आ रहे हैं, कोटा एक बड़ा एजुकेशन हब बन चुका है, बीकानेर बहुत बड़े फूड इंडस्ट्री के रूप में उभर रहा है, जयपुर राजधानी होने के साथ-साथ हर तरह की गतिविधियों का बड़ा केंद्र बन गया है और जोधपुर भी बड़ा एक्सपोर्ट हब, टेक्सटाइल हब आदि के रूप में जाना जाने लगा है। ऐसे में प्रश्न ये उभरकर आता है कि क्या केंद्र सरकार का बजट इन सभी व्यवसायों एवं उद्योगों को इनके विकास के लिए सब आशाएं पूरी कर पा रहा है?

अभी जिस गति से राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट हुआ, लाखों करोड़ के एग्रीमेंट हुए है तो, इस बार बजट 2025 के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालने के साथ ही हम देखेंगे कि हमारे राजस्थान के भविष्य पर इस बजट का क्या असर पड़ेगा ।

वित्तीय बजट 2025 पेश कर दिया गया है एवं सरकार के विजन के अनुरूप इसमें सभी वर्गों एवं सेक्टर्स के लिए रिफॉर्म्स का मिश्रण देखने को मिला है। सरकार ने उद्योगों के इनोवेशन को बढ़ाने के लिए 10,000 करोड़ का बजट दिया है। एमएसएमई उद्योगों के वर्गीकरण की लिमिट को बढ़ाया है। स्टार्टअप एवं सूक्ष्म उद्योगों को क्रेडिट गारंटी लिमिट को बढ़ाया है। मेडिकल शिक्षा के लिए 10,000 नई सीटों की घोषणा की है। पावर सेक्टर एवं माइनिंग सेक्टर में मेजर रिफॉर्म्स की घोषणा की है। व्यक्तिगत कर ढांचे में बहुत परिवर्तन किया है। वरिष्ठ नागरिकों को काफी राहत देने के साथ ही बहुत से परिवर्तन किए गए है।

यदि हम अपना फोकस राजस्थान के उद्योग एवं व्यवसाय पर रखकर इस बजट का विश्लेषण करें तो हमें महसूस होगा कि महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स माइनिंग एवं रिन्यूएबल पावर एवं एक्सपोर्ट में हुए हैं, जो सीधे ही राजस्थान के औद्योगिक गतिविधियों से जुड़े

हुए हैं।

पावर रिफॉर्म्स में अभी तक राजस्थान में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी आदि के प्रोजेक्ट लगाकर बिजली का उत्पादन हो रहा है। लेकिन इस बिजली के वितरण के लिए पावर ट्रांसमिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी सदैव महसूस होती थी। ऐसे में बजट 2025 में इस पर ध्यान देकर इंटर स्टेट पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करने पर बहुत जोर दिया है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को 50 वर्ष के लिए बिना ब्याज पर 1.5 लाख करोड़ के ऋण उपलब्ध करवाने का भरोसा दिया है, जिससे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा एवं राज्य में नए पावर प्रोजेक्ट्स से सस्ती बिजली का उत्पादन एवं वितरण का माहौल बनेगा। सोलर एवं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जब भी नए प्रोजेक्ट लगते हैं तो वो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार को आने वाले 25 वर्षों के लिए बहुत बड़ा देते हैं। सोलर एवं विंडमिल के उपकरण बनाने को प्रोत्साहन की घोषणाएं राजस्थान के सोलर एनर्जी क्षेत्र में बड़े निवेश को आमंत्रित करेगी। अतः सरकारी बजट का यह प्रावधान प्रशंसनीय समझा जा सकता है।

अगला रिफॉर्म माइनिंग सेक्टर के डेवलपमेंट का है, जो राजस्थान के लिए बहुत मोटिवेशनल है। चूंकि राजस्थान में सभी तरह का खनन होता है, एवं माइनिंग से प्रोडक्ट्स बनाने के बड़े बड़े उद्योग लगे हुए हैं, तो माइनिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स से राजस्थान में लंबी अवधि के निवेश के नए रस्ते खुलेंगे।

इसके अलावा यहां से हैंडीक्राफ्ट, स्टोन, मार्बल, इंजीनियरिंग, एग्रो प्रॉडक्टस का काफी एक्सपोर्ट होता है। ऐसे में सरकार द्वारा बजट में भारत ट्रेड नेट इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की घोषणा प्रोत्साहन देने वाली है। इससे सभी एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स विश्व की बेहतरीन तकनीक से जुड़ जाएंगे। इससे शिपमेन्ट की लेटेस्ट रिपोर्ट, एक्सपोर्टर, बैंक एवं बायर्स तक रियल टाइम में दिखेगी। अब एक्सपोर्टर अपने शिपमेंट डॉक्यूमेंट पर बैंक से आसानी से फंडिंग रेगुलेट करवा सकेंगे एवं विश्वभर के बायर्स को सही समय पर सेवाएं दे सकेंगे। इस तरह के सुधारों को भविष्य के विकास के लिए अग्रिम तकनीकी कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। सरकार ने टीयर- 2 शहरों में ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स स्थापित करने की घोषणा की है, ताकि विश्व की लेटेस्ट ट्रेंड के अनुसार उत्पादों की गुणवत्ता एवं क्षमता विकसित की जा सकें। खराब होने वाले नाशवान उत्पादों के लिए वेयरहाउसिंग की घोषणा की गई है। फुटवियर एवं लेदर सेक्टर के लिए अच्छी घोषणाओं से भी राजस्थान को लाभ मिलेगा।

राजस्थान का बहुत बड़ा तबका सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों पर निर्भर है। बजट ने उनके वर्गीकरण की लिमिट को हर क्षेत्र में बढ़ाया है। उनके लिए क्रेडिट गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ा कर 10 करोड़ एवं स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ से बढ़ा कर 20 करोड़ कर दिया है।

यहां पर्यटन भी एक बड़ा व्यवसाय बन चुका है। ऐसे में बजट में 50 टॉप पर्यटन की जगहों को विशेष तौर पर विकसित करने के लिए योजना बनाने की घोषणा की है। इससे राजस्थान के पर्यटन को बढ़ाने के नए रस्ते खुलेंगे। इसके साथ ही उड़ान योजना के अंतर्गत छोटे- छोटे जगहों तक भी फ्लाइट की सुविधा का भी लाभ इस व्यवसाय को मिलेगा। होमस्टे मालिकों के लिए भी मुद्रा योजना की घोषणा की गई है।

टैक्स रिफॉर्म्स के तहत भी काफी बदलाव किए हैं। पर्सनल इनकम टैक्स में बड़ा सुधार करते हुए अब 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा एवं वेतन से होने वाली 12.75 लाख की आय तक कोई कर नहीं लगेगा। इससे लोगों के कर की बचत होगी।

स्टॉक मार्केट पर इस बजट का प्रभाव देखें तो लगता है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर व पावर सेक्टर, कंज्यूमर सेक्टर आदि में बढ़ोतरी होगी। टेक्नोलॉजी शेयर्स में अच्छी गतिविधियों की भी खबर मिलने की संभावना है। वित्त बजट का करदाताओं, उद्योगों एवं आमजनों के लिए सकारात्मक आना, भारतवर्ष के भविष्य के लिए बहुत ही उत्तम दिशा निर्देश है कि हम वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने की सही दिशा की ओर अग्रसर है ।

डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल

नए तरह के राष्ट्रवाद से साबका

दीपक कुमार
वरिष्ठ पत्रकार

ट्रंप अपने कदमों से भले ही दुनिया को हैरान कर रहे हैं, पर उनके फैसलों में व्यापक नीतिगत रूपरेखा मौजूद है, जिस पर नीति-निर्माता चलेंगे। 'अमेरिका फर्स्ट' के नारे में समाहित नए तरह के राष्ट्रवाद के नायक के रूप में वे खुद को प्रतिष्ठित करने को व्याकुल हैं।

डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू हो गया है और हर कोई यह समझने की कोशिश में मसरूफ है कि उन्होंने अपने तरकश से जो तीर छोड़े हैं, उनके मायने क्या हैं। चाहे ट्रंप प्रशासन में नियुक्त किए गए लोग हों, उनके खुद के बयान हों और सोशल मीडिया पर किए जा रहे एलान हों या फिर उनके कार्यकारी निर्देश। अगर इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति है, तो किसी को पक्के तौर पर इसका अंदाजा नहीं है। फिर भी, यह तय है कि उनके फैसलों में व्यापक नीतिगत रूपरेखा मौजूद है, जिस पर उनके नीति-निर्माता चलेंगे और विश्व के तमाम देशों की नीतियों को बुरी तरह प्रभावित करेंगे। ट्रंप ने 'अमेरिका फर्स्ट' का जो नारा दिया है, उसका आधारभूत उद्देश्य नए तरह के एक राष्ट्रवाद की स्थापना है, जिसके नायक के रूप में खुद को प्रतिष्ठित करने को व्याकुल हैं।

इसमें अमेरिका किस दिशा में जाएगा, यह भविष्य के गर्भ में है। लेकिन, विश्व के तमाम नीति निर्माता जो पहले से ही वैश्विक राजनीति में मची उथल-पुथल से जूझ रहे हैं, ट्रंप के उठा-पटक भरे फैसलों से जूझने की चुनौती से दो-चार हो रहे हैं। ट्रंप की अहम सार्वजनिक घोषणाओं में है विदेश नीति के एजंडे का ऐलान। उन्होंने दूसरे देशों पर कब्जा करने और प्रभाव क्षेत्र कायम करने के युग में वापसी की बात की है और साथ ही साथ साझीदारों के साथ भागीदारी और आर्थिक रूप से एक दूसरे के पूरक बनने की पाबंदियों को भी खारिज कर दिया है। ट्रंप ने सैन्य ताकत के दम पर पनामा नहर और ग्रीनलैड पर कब्जा करने की ओर कदम बढ़ाया है। अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर जिस तरह से आपातकाल लगाया गया, सेना भेजी गई और आप्रवासियों को लेकर ताबड़तोड़ निर्देश जारी किए गए, उसे कूटनीति के गलियारे में हैरान करने वाला माना जा रहा है। क्योंकि अगर कोई और देश इसी तरह की घोषणाएं करता, तो अब तक खुद अमेरिका ही उसे 'अराजक' और दुनिया के लिए खतरा घोषित कर चुका होता।

अमेरिका से भारत के संबंध दो दशक में तेजी से मजबूत हुए हैं, लेकिन ट्रंप की 'अमेरिका फर्स्ट' नीति से परेशानी बढ़ सकती है। ट्रंप अपनी इस नीति नीति को लेकर आक्रामक हैं। एच1बी वीजा के मुद्दे पर ट्रंप को अपने साथी उद्योगपति इलन मस्क का साथ नहीं मिला है। भारत को आप्रवासन और व्यापार के मसले पर ट्रंप प्रशासन से चुनौती मिलेगी। अमेरिकी थिंक टैंक 'रैंड कारपोरेशन' में हिंद-प्रशांत क्षेत्र के विश्लेषक डेरेक ग्रासमैन ने लिखा है कि ट्रंप की हिंद-प्रशांत नीति बाइडेन से बिलकुल अलग होगी। ट्रंप ने जेडी वांस को उपराष्ट्रपति बनाया है और वांस चीन को लेकर काफी आक्रामक रहते हैं। हालांकि, ट्रंप कुछ भी ऐसा करने से बचेंगे, जो अमेरिका के फायदे में नहीं होगा। ट्रंप ने कहा है कि वह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के संबंध गहरा करना चाहते हैं। नवंबर में चुनाव जीतने के बाद ट्रंप ने शी जिनपिंग से बात की थी और कहा था कि दोनों देश साथ मिलकर कई समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं। ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में शी जिनपिंग को आमंत्रित किया था। माना जा रहा है कि चीन के तानाशाह के प्रति ट्रंप की बढ़ती उदारता का असर अमेरिका से भारत और जापान के संबंधों पर पड़ेगा।

ट्रंप अतीत में भारत की कई बार आलोचना कर चुके हैं। खास कर अमेरिका में बेरोजगारी को लेकर। पूर्व कूटनीतिज्ञ जयंत प्रसाद के मुताबिक, 'ट्रंप की यह प्रवृत्ति रही है कि दुश्मनों की खुशामद करो और दोस्तों को बेचैन।' यूनिवर्सिटी आफ अल्बनी में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर क्रिस्टोफर क्लैरी ने एक टीवी चैनल पर कहा, 'दूसरे कार्यकाल में ट्रंप भारत के लिए दो तरह से खतरा हैं। ट्रंप और उनकी टीम भारत को लेकर ज्यादा आक्रामक रहेंगे- खास कर कारोबार और निवेश के मसले पर।' वर्ष 2022 में भारत और अमेरिका का द्विपक्षीय व्यापार 191.8 अरब डालर का था। भारत ने 118 अरब डालर का निर्यात किया था और आयात 73 अरब डालर का था।

लेकिन ट्रंप ने अपनी नीति के तहत भारत के खिलाफ शुल्क लगाया तो चीजें बदलेंगी। ट्रंप चाहते हैं कि व्यापार लाभ का आंकड़ा अमेरिका के पक्ष में रहे न कि भारत के पक्ष में। सवाल उठता है कि भारत इस स्थिति को कूटनीतिक तरीके से कैसे संभालेगा। पिछली बार भी ट्रंप ने भारत के स्टील और एल्युमिनियम पर शुल्क लगाए थे। देखना होगा कि भारत सरकार अमेरिका के साथ समझौते को लेकर क्या रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाती है, जो न केवल भारत के लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी लाभकारी हो।

दरअसल, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संतुलन बनाना अमेरिकी रणनीति के लिए अहम है। इन तीनों देशों का अपने-अपने संदर्भ में अमेरिका के साथ गहरा संबंध है और दक्षिण एशिया की अमेरिकी रणनीति में इन देशों की भूमिका बहुत अहम रहेगी। दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव आते हैं। विश्व बैंक का अनुमान है कि इस इलाके में 1.94 अरब लोग रहते हैं। दक्षिण एशिया में भारत तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है। इन देशों में भारत ने कुछ सालों में अपनी स्थिति मजबूत बनाई है। सवाल उठता है कि क्या ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत की स्थिति वैसे ही रहेगी?

ट्रंप की 'अमेरिका फर्स्ट' आर्थिक नीतियां, भारत के साथ व्यापार संबंधों को प्रभावित कर सकती हैं। आयात पर शुल्क बढ़ाने जैसी उनकी संरक्षणवादी नीतियां आइटी, फार्मास्युटिकल्स और वस्त्र जैसे क्षेत्रों में भारतीय निर्यातकों के लिए चुनौतियां प्रस्तुत करती हैं। अमेरिका में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के प्रयास भारत पर अपने व्यापार अवरोधों को कम करने का दबाव डाल सकते हैं, जो घरेलू उद्योगों को प्रभावित कर सकता है। भारतीय आइटी और सेवा क्षेत्र अमेरिकी ग्राहकों पर ज्यादा निर्भर हैं। ये क्षेत्र ट्रंप की व्यापार युद्ध नीतियों के कारण अमेरिकी उपभोक्ता खर्च में कमी आने पर प्रभावित हो सकते हैं। ट्रंप की वापसी पारंपरिक ऊर्जा नीतियों में बदलाव का संकेत देती है, जिसमें तेल, गैस और कोयले के नियमन को कम करने पर जोर दिया जाएगा। यह दृष्टिकोण जो बाइडेन प्रशासन द्वारा अपनाई गई अक्षय ऊर्जा साझेदारी के विपरीत है, जो भारत के जलवायु लक्ष्यों के साथ मेल खाती थी।

ट्रंप पहले भी भारत समेत कई ऐसे देशों की आलोचना कर चुके हैं जो अमेरिकी सामान पर भारी शुल्क लगा रहे हैं। ट्रंप चेतावनी दे चुके हैं कि अगर भारत जैसे देश अमेरिकी सामान पर भारी शुल्क लगाएंगे तो अमेरिका भी उनके साथ बिल्कुल ऐसी ही नीति अपनाएगा। अक्सर भारत को कारोबार में अपना बड़ा सहयोगी बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, अगर भारत हमारे सामान पर 100 फीसद शुल्क लगाएगा तो क्या हमें इसके बदले कुछ नहीं करना चाहिए? ट्रंप का भारत समेत अन्य देशों के लिए यह नजरिया उनकी 'अमेरिका फर्स्ट' ट्रेड नीति से जुड़ा है। अगर ऐसा होता है तो इसका भारी असर भारत के निर्यात क्षेत्र पर देखने को मिल सकता है। खासतौर पर इसका असर उन चीजों पर देखने को ज्यादा मिलेगा जो मुख्य रूप से अमेरिकी बाजार पर निर्भर हैं।

हालांकि, ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी में विशेष रूप से रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में निरंतर वृद्धि की संभावना है। चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर साझा चिंता दोनों देशों के लिए मजबूत एकीकृत कारक बनी हुई है। ट्रंप का क्वाड को मजबूत करने पर जोर भारत के हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण के साथ मेल खाता है। भारत को संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और खुफिया जानकारी साझा करने में अमेरिका से और अधिक समर्थन मिलने की उम्मीद है, जो भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाएगा। ट्रंप की 'शक्ति के माध्यम से शांति' की नीति हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक अधिक मुखर अमेरिकी रुख में परिवर्तित हो सकती है, जो भारत की रणनीतिक प्राथमिकताओं के साथ मेल खाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा संकटों के दौरान दोनों देशों के बीच विश्वास और तालमेल मजबूत रहेगा, जो रक्षा और खुफिया साझेदारी को और मजबूती देगा।

दक्षिण एशिया में ट्रंप की विदेश नीति क्षेत्रीय गतिशीलता को प्रभावित कर सकती है। आतंकवाद-रोधी प्रयासों पर पाकिस्तान के साथ जुड़ाव रखने की उनकी इच्छा, साथ ही अधिक जवाबदेही की मांग, क्षेत्रीय स्थिरता में भारत की रुचि के अनुरूप है। चीन के खिलाफ उनकी मजबूत नीति-शुल्क, प्रतिबंध और कूटनीतिक दबाव के माध्यम से- भारत के प्रयासों का समर्थन करती है, जो क्षेत्र में चीनी प्रभाव का मुकाबला करना चाहता है। व्यापक भू-राजनीतिक क्षेत्र में, बाइडेन की तुलना में रूस के प्रति ट्रंप का कम टकराव वाला दृष्टिकोण भारत के लिए जटिलताओं को कम कर सकता है।

ट्रंप के अब तक के एलानों के पीछे बहुत सोचे समझे भू-राजनीतिक समीकरण नजर आते हैं। अब ट्रंप और उनकी टीम इनको कैसे लागू करती है, उसी से उनकी विदेश नीति की विरासत निर्धारित होगी। लेकिन, दुनिया को चौंकाने का ट्रंप का अंदाज उनके काम करने का असली तरीका है। ट्रंप की विश्व दृष्टि की सबसे अच्छी परिभाषा शायद, 2020 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए गए उनके भाषण में दिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि, 'राष्ट्रपति के तौर पर मैंने पुराने और नाकाम हो चुके तौर-तरीकों को खारिज कर दिया है और मैं गर्व से अमेरिका को पहली पायदान पर रख रहा हूं। ये बिल्कुल ठीक है।' जाहिर है, अब भारत और दुनिया के तमाम देशों को अमेरिकी प्रशासन के बारे में नए दृष्टिकोण से सोचना होगा।

भाजपा: किसके सिर सजेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का ताज़?

संतोष प्रजापत
राजनीतिक विश्लेषक

बक़ौल भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। ऐसे में जाहिर सा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का महत्व और उसका ओज। वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा स्थापित है। पार्टी के 'एक व्यक्ति-एक पद' के पार्टी संविधान पर जाए तो अब देशभर में हरेक के मन में ये सवाल उठ रहा है कि अब भाजपा अपने 'संचालन' की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसे सौंपेगी?

मोदी सरकार 3.0 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को 'गुजरात' से राज्यसभा स्वास्थ्य मंत्रालय संभालने का काम दिया गया। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह (पार्टी में नंबर 1 एवं नंबर 2 की पदवी प्राप्त), दोनों ही गुजरात से हैं। अब ऐसे में तय सा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम बाद 2025 के फरवरी माह में बीजेपी में नया राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इस सवाल को लेकर कयासबाजी तेज है। इसे लेकर कई नाम सामने आ रहे हैं लेकिन ये तय तब होगा जब पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी। नामों पर मंथन से पहले बीजेपी में अध्यक्ष पद की योग्यता और चुनाव पर प्रकाश ड़ालते हैं।

अध्यक्ष बनने की क्या है योग्यता

बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए सबसे जरूरी है कि इसके लिए होने वाले चुनाव के लिए नामांकन दर्ज करने वाला व्यक्ति कम से कम 15 साल तक पार्टी का प्राथमिक सदस्य रहा हो। इसके साथ ही प्रदेश या राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कम से कम 20 सदस्य अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए किसी व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव पेश कर सकते हैं और इस प्रस्ताव पर कम से कम 5 प्रदेशों के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों की सहमति होनी चाहिए। सबसे जरूरी बात कि अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए प्रस्ताव पर उम्मीदवार का दस्तखत होना चाहिए।

कैसे होता है भाजपा के अध्यक्ष पद का चुनाव

वर्ष 2023 में 18 फरवरी को दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर एक प्रस्ताव पास हुआ। इसके मुताबिक पद खाली होने पर पार्लियामेंट्री बोर्ड अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकेगा। भाजपा के अपने संविधान की धारा-19 में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं। इस नियम के मुताबिक पार्टी के राष्ट्रीय परिषद और प्रदेश परिषदों के सदस्य मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अध्यक्ष पद का चुनाव पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बनाए गए नियमों के मुताबिक ही होता है।

पार्टी के संविधान के अनुसार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। वैसे पाठकों को बता दें कि भाजपा अध्यक्ष पार्टी का सर्वोच्च पद होता है और उस पर पूरी पार्टी की अहम जिम्मेदारी होती है। लेकिन...जाहिर सा है, निर्णय की बानगी में एकाधिकार, पार्टी के नेता प्रधानमंत्री के साथ-साथ पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष (वर्तमान राजनीति के परिदृश्य में 'चाणक्य' से सुशोभित) गृह मंत्री अमित शाह का प्रभाव परिलक्षित होता रहा हैं।

चलिए, अब इस पद के मजबूत एवं अप्रत्याशित चेहरों पर प्रकाश ड़ालते हैं...

2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान, ''अब बीजेपी बड़ी हो गई हैं, उन्हें आरएसएस की जरूरत नहीं हैं'' से संघ नाराज हुआ। नाराजगी का परिणाम बीजेपी को मिली सीटों में स्पष्ट दिखा और 240 सीटों से संतुष्ट होना पड़ा। संघ के केरल अधिवेशन में आपसी नाराजगी का निपटारा हुआ और भाजपा ने हरियाणा व महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में अप्रत्याशित जीत के साथ ही उपचुनावों में बेहतर प्रदर्शन किया। ऐसे में पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव में संघ की इच्छा का पूरा सम्मान दिया जाना तय है। राजनीतिक हलकों में कुछ नामों की चर्चाएं हैं। लेकिन मोदी-शाह की जोड़ी हमेशा चौंकाने वाले निर्णय लेती है। ऐसे में कुछ मजबूत एवं अप्रत्याशित चेहरों की संभावनाओं को खंगालते हैं।

बिप्लब कुमार देब

बिप्लब कुमार देब एक ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री है, जिनके पास फिलहाल कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रहे देब आरएसएस के पूर्व स्वयंसेवक रहे चुके हैं। पार्टी ने 2015 में त्रिपुरा राज्य में महासंपर्क अभियान के प्रदेश संयोजक की जिम्मेदारी देकर भेजा। अपनी सक्रियता से 2016 में ही स्थानीय इकाई का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उनके नेतृत्व में भाजपा ने 15 साल बाद वापसी कर 2018 में सरकार बनाई। जीत के सूत्रधार रहे देब को सीएम पद का इनाम भी मिला। वर्तमान में वे वेस्ट त्रिपुरा से लोकसभा सांसद है। उनकी संगठन क्षमता का इस्तेमाल पार्टी ने गत हरियाणा विधानसभा चुनाव में कर चुकी है। देब वर्तमान दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी अहम भूमिका निभा रहे है। युवा के साथ ही, संघ की पृष्ठभूमि और लो-प्रोफाइल रहने की प्रवृत्ति से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के ''अंडरडॉग'' उम्मीदवार हो सकते हैं।

डी पुरंदेश्वरी

प्रधानमंत्री मोदी के महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दूसरा अप्रत्याशित चेहरा डी पुरंदेश्वरी है। आंध्रप्रेदश की पूर्व मुंख्यमंत्री और प्रसिद्ध अभिनेता एनटी रामाराव की बेटी और टीडीपी दल के नेता एवं मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की साली पुरंदेश्वरी 2014 से भारतीय जनता पार्टी में है। पूर्व में भाजपा महिला मोर्चा प्रभारी के रूप में अपनी संगठात्मक कौशल का प्रदर्शन कर चुकी वे वर्तमान में स्थानीय संगठन की प्रदेश अध्यक्ष है। अपनी वाकपटुता, स्पष्टता और भावपूर्ण भाषणों से उन्हें 'दक्षिण की सुषमा स्वराज' की उपाधि भी मिली हुई है। लोकसभा में सीटों की संख्या और सहयोगी दलों को साथ में लाने के लिए पुरंदेश्वरी लोकसभा अध्यक्ष पद की प्रबल दावेदार थी। भाजपा संगठन द्वारा दक्षिण में अपनी स्थिति को मजबूत करने के साथ ही राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति पदों पर दक्षिण से कोई काबिज न होने पर वे अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की सशक्त उम्मीदवार भी दिखाई दे रही हैं। विदित है कि वैंकेया नायडू के बाद पार्टी ने दक्षिण से कोई भाजता नेता को प्रमुख पदों पर जिम्मेदारी दी नहीं है।

वसुंधरा राजे

राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की सशक्त दावेदारी थी। पार्टी की ओर से सबसे अधिक जनसभाएं भी की। लेकिन मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में नए चेहरों को मुख्यमंत्री बनाने की कड़ी में राजस्थान में भजनलाल शर्मा के रूप में एक नए चेहरे को राजस्थान की कमान दी गई। घोषणा के समय मुख्यमंत्री न बनने का दर्द भी आंखों से छलका। बाद में राजे ने कुछ समय तक पार्टी और सार्वजनिक कार्यक्रमों में सीधे तौर पर न सही लेकिन तीखे शब्दों के बाणों से फैसले की अंर्तःमन की पीड़ा को बताया भी। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात, संघ से नजदीकियां और अब पार्टी के संगठन कार्यक्रमों में उनकी सक्रियता ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अप्रत्याशित उम्मीदवार बना दिया है। उनके पास पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद लंबे समय से है। वहीं मुख्यमंत्री पद का बलिदान दे चुके शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल खट्टर को पार्टी ने केन्द्रीय मंत्री बनाकर सम्मान दिया है। इस परिदृश्य में भी केवल राजे ही पार्टी की बड़ी नेता है, जिन्हें बलिदान का ''इनाम'' नहीं मिला है। हां, जरूर पार्टी का असल संचालन कर रहे पुरानों से उनकी पुरानी कड़वी यादें रोडा बन सकती है।

वहीं आम्बेडकर मुद्दे पर घिरी भाजपा इस पद पर किसी दलित चेहरे को भी मौका दे सकती है। लेकिन संगठन में मजबूत आधार रखने के साथ ही संघ के समर्थन वाले दलित नेताओं के विकल्प गिने-चुने हैं। इसमें केन्द्रीय मंत्री अर्जुनलाल मेघवाल, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बेबी रानी मौर्य शामिल है। वहीं मीडिया में जिनकी चर्चा आए दिन होती है, उनमें- केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, भूपेन्द्र यादव, महासचिव विनोद तावड़े का नाम शामिल है। खैर... आपके हाथों में जब तक पत्रिका पहुंचेगी, तब तक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताजपोशी होना संभावित है।

इंडिया गठबंधन की प्रासंगिकता पर सवाल

विपक्ष में विपक्ष

सुरेश व्यास ✍ वरिष्ठ पत्रकार

इंडिया गठबंधन ने पिछले साल मई में हुए आम चुनावों में मोदी सरकार को कड़ी टक्कर दी। हालांकि कांग्रेस की अगुवाई वाला गठबंधन सरकार तो नहीं बना सका। फिर देश को लगा कि कम से कम सशक्त विपक्ष के आगे सरकार की कथित मनमानियों पर अंकुश तो लगेगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, वैसे वैसे इंडिया गठबंधन की प्रासंगिकता पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं।

पिछले साल हुए आम चुनाव के पहले हर आदमी के जेहन में एक ही बात दबी थी कि कि मोदी सरकार से भले ही कई लोग संतुष्ट नहीं हो और दस साल के इस शासन से ऊबकर परिवर्तन करना चाह रहे हों, लेकिन कोई बेहतर विकल्प है ही नहीं कि बदलाव कैसे लाया जाए। इसी सवाल के जवाब में 23 जून 2023 को 26 गैर भाजपाई दल एक मंच पर जुटे और चुनाव से लगभग एक साल पहले ही इंडियन नेशनल डवलपमेंटल इन्क्लुसिव एलायंस (इंडिया) का गठन कर खुद को विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने की शुरुआत की। हालांकि नेता और नीति के मामले में गठबंधन बैठकों से ज्यादा कुछ कर नहीं पाया, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार के वापस भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में जा घुसने के बावजूद इंडिया गठबंधन ने पिछले साल मई में हुए आम चुनावों में मोदी सरकार को कड़ी टक्कर दी। हालांकि कांग्रेस की अगुवाई वाला गठबंधन सरकार तो नहीं बना सका, लेकिन मोदी, भाजपा व एनडीए के सामने चुनौती जरूर खड़ी कर दी। फिर देश को लगा कि कम से कम सशक्त विपक्ष के आगे सरकार की कथित मनमानियों पर अंकुश तो लगेगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, वैसे वैसे इंडिया गठबंधन की प्रासंगिकता पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं।

जिस सशक्त विपक्ष की कल्पना की गई थी, उसमें ही दरारें नजर आने लगी है और विपक्षी पार्टियां खुद ही एक दूसरे का विपक्ष बनती दिख रही है। इसकी एक तस्वीर संसद के शीतकालीन सत्र में दिखाई दी, जब इंडिया गठबंधन की दूसरी बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी और तीसरे नम्बर की तृणमूल कांग्रेस ही प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस से अलग नजर आई। उद्योगपति अडानी के मामले पर कांग्रेस ने विपक्ष की ताकत के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन गठबंधन की दोनों ही पार्टियां भी साथ खड़ी नहीं रह सकी और दोनों ने इंडिया गठबंधन के सांसदों के संसद परिसर में प्रदर्शन से खुद को दूर रखा। अब संसद का जब बजट सत्र चल रहा है तो इसमें भी कांग्रेस और गठबंधन की अन्य पार्टियों का रुख कई मुद्दों पर अलग अलग ही रहने वाला है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन की गांठ उलझ चुकी है। खुद कांग्रेस अपने गठबंधन की सहयोगी रही आम आदमी पार्टी (आप) के सामने खड़ी है और राजनीतिक विश्लेषक कयास लगा रहे हैं कि इससे कांग्रेस को हो या नहीं, आप को जरूर नुकसान उठाना पड़ सकता है और भाजपा, जिसके पास खोने को कुछ नहीं है, उसे फायदा होने के साथ उसके सत्ताधारी राज्यों की सूची में एक अंक और बढ़ जाएगा।

जाहिर है, इससे ही गठबंधन के खत्म होने की शुरुआत के कयास भी लगने लगे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या भाजपानीत एनडीए से अलग जाने वाले जनसमूह की भावनाएं विपक्षी दल केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनने के एक साल बाद ही दबती नजर आएंगी और एक बार फिर उसे विकल्प की तलाश में चार साल और इंतजार करना पड़ेगा। इस सवाल के जवाब में यदि कोई है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस।

वैसे तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की प्रासंगिकता पर सवाल हरियाणा व महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद कुछ ज्यादा ही मुखर हो चुके हैं, लेकिन माना जा रहा है कि दिल्ली चुनाव के नतीजे इस दिशा में काफी अहम साबित होंगे। राजनीतिक विश्लेषक संतोष कुमार का कहना है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में मिली सफलता को सहयोगी दलों के साथ भुना नहीं सकी और उसे राज्यों में खुद का फायदा ही नजर आया, इससे इंडिया गठबंधन की अहमियत पर भी सवाल खड़े होने लगे। वे कहते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस थोड़ा त्याग करती तो स्थिति अलग होती। उसने आम आदमी पार्टी जैसे सहयोग से हाथ मिलाना उचित नहीं समझा और हाथ में आती दिख रही बाजी पलट गई। नतीजे आए तो भाजपा 70 में से 48 सीटें जीतकर फिर सत्ता पर काबिज हो गई और कांग्रेस को महज 37 सीटों पर संतोष करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में भाजपा को सकते में डालने वाले गठबंधन सहयोगी सपा को महाराष्ट्र में सीटें नहीं दी गई। इसका असर यूपी विधानसभा की 10 सीटों के उपचुनावों में दिखा। कांग्रेस चुनाव से दूर रही और सपा संसदीय चुनावों वाली सफलता कायम नहीं रख सकी।

तब से कांग्रेस सहयोगी दलों से ही घिर रही है। शिवसेना (उद्धव) के नेता संजय राउत ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस जहां कमजोर होती है, वहां क्षेत्रीय दलों का सहारा लेती है और जहां वह मजबूत दिखती है वहां इन दलों को भाव ही नहीं देती। हरियाणा चुनाव नतीजों के बहाने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी यह कहते हुए कांग्रेस को आइना दिखा दिया कि किसी को भी 'ओवर कॉन्फिडेंट' नहीं रहना चाहिए और यहीं से चलकर दिल्ली चुनाव तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के रास्ते न सिर्फ अलग अलग हो गए, बल्कि रिश्तों में खटास ऐसी आई है कि केजरीवाल ने साफ कहा है कि वे गठबंधन से कांग्रेस को निकलवा कर रहेंगे।

गठबंधन की एक और अहम घटक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस भी खरगे-राहुल के नेतृत्व वाली कांग्रेस पर लगातार सवाल उठा रही है। ममता ने तो इंडिया गठबंधन पर कांग्रेस के नेतृत्व पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने गठबंधन की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। जिम्मेदारी मिलती है तो वे नेतृत्व सम्भालने को तैयार है। उनके बयानों का समर्थन हाथों हाथ एनसीपी नेता शरद पवार और राजद सुप्रीमो लालू यादव तक ने कर दिया और

आम चुनाव में एनडीए बनाम इंडिया

एनडीए		इंडिया	
भाजपा	tyr	कांग्रेस	
टीडीपी	s	सपा	w
जदयू	st	डीएमके	tt
शिवसेना (शिंदे)	r	तृणमूल	t
एनसीपी (अजीत)	rs	एनसीपी (शरद)	r
जनसेना	rt	शिवसेना (उद्धव)	r
एलजेपी	r|	माकपा	ry
आरएलडी	rt	राजद	ry
जेडीएस	rt	भाकपा	rt
अन्य	r	अन्य	tr
कुल	tw		twy

लोकसभा में कांग्रेस

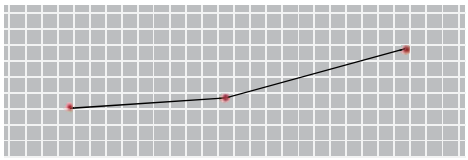

कहा कि ममता में नेतृत्व सम्भालने की क्षमता है। सपा और नेशनल कांफ्रेंस ने भी ममता के प्रस्ताव पर चर्चा करवाने की बात कहकर कांग्रेस को चौंका दिया, लेकिन कांग्रेस ने इसे गम्भीरता से लेने की बजाय उदित राज जैसे नेताओं के मुंह से कहलवा दिया कि टीएमसी अभी नेतृत्व करने जैसी बड़ी पार्टी नहीं है। वह बंगाल के बाहर तक नहीं निकल पा रही। इधर, ममता बनर्जी ने हाल ही बांग्ला में लिखी अपनी किताब में कांग्रेस पर तीखा हमला किया और कहा कि भाजपा कांग्रेस के कारण जीतती है।

कांग्रेस की कार्यशैली पर भी सहयोगी दल सवाल उठा रहे हैं। इनमें प्रमुख है चुनावी हार के बाद ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने की कांग्रेस की आदत। भाजपा को तो जाहिर है इसे खारिज करना ही था, लेकिन प्रमुखता से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता व जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुला ने भी कह दिया कि अगर हम जीतने के बाद जश्न मनाते हैं तो कुछ महीनों बाद हार पर ईवीएम को खारिज नहीं किया जा सकता। ऐसे ही स्वर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के मुंह से भी निकले कि हकीकत है तो साबित कीजिए, वरना ईवीएम पर बयान देने का कोई औचित्य नहीं है।

और भी कई मुद्दे हैं, जो संकेत कर रहे हैं कि आपसी मनमुटाव के चलते कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की दूरियां बढ़ती जाएंगी और लगातार हार की हताशा अंततः एनडीए और मोदी के लिए रास्ता बनाती जाएगी। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप राणा कहते हैं कि इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन ने जो उम्मीद दिखाई थी, वह खत्म हो चुकी है। बिना मजबूत नेतृत्व औप ठोस नीति के एनडीए व मोदी को टक्कर नहीं दी जा सकती और ये दोनों ही चीजें न कांग्रेस के नेतृत्व में दिख रही है और न ही इस दिशा में कोई कोशिश हो रही है। उल्टे गठबंधन में शामिल दलों का टकराव बढ़ता ही जा रही है। कांग्रेस न तो इंडिया गठबंधन को मजबूत नेतृत्व दे सकी और न ही क्षेत्रीय दलों व सहयोगियों को पचा सकी। हालत यह है कि राज्यों के चुनाव तो क्या राष्ट्रीय परिदृश्य में भी इन दलों में एकता नहीं दिख रही।

राणा कहते हैं कि कांग्रेस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी बनने के नाते अधिकारपूर्वक इंडिया गठबंधन का नेतृत्व अपने हाथों में लेकर राष्ट्रीय मुद्दों पर आंदोलनों की अगुवाई करते हुए इसकी प्रासंगिकता को बरकरार रख सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने ऐसी कोई पहल की नहीं। वह अब भी संविधान व आरक्षण बचाने, जातिगत जनगणना, अम्बेडकर के मान-अपमान, आरएसएस की आलोचना और अडानी-अम्बानी के मुद्दों तक ही खुद को सीमित रख रही है। जबकि गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर सहानुभूति के जरिए विपक्ष को धार दी जा सकती थी। इस पर शायद कांग्रेस के नेता भाषणों में ही बात करते हैं, जमीन पर करने के लिए उनके पास जैसे कोई नीति ही नहीं है। धर्मनिरपेक्षता जैसे मुद्दे पर कांग्रेस के पास भाजपा-संघ को गाली देने के अलावा कुछ है नहीं और वह सॉफ्ट हिन्दुत्व के नाम पर बहुसंख्यक लोगों से अलग होती जा रही है।

कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि मौजूदा राजनीतिक हालात में कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए। सबसे पुराने वामपंथी दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता डी. राजा ने तो कहा भी है कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, उसे मौजूदा केंद्र सरकार और भाजपा की नीतियों से मुकाबले के लिए खुद के अंदर झांककर देखना होगा। वरिष्ठ पत्रकार अजय बुआ कहते हैं कि अब चूंकि लोकसभा के चुनाव साढ़े चार साल बाद ही होंगे, जब तक भाजपा के सामने डटे रहने के लिए नेता से ज्यादा नीति जरूरी है। कांग्रेस को सभी सहयोगी दलों को एक समान नीति पर राजी करने की पहल करनी होगी। देश को भी एक सशक्त विपक्ष की उम्मीद है और यदि गैर एनडीए पार्टियां इस उम्मीद पर खरी नहीं उतरती है तो जनता किससे उम्मीद लगाएगी।

चुनावी राजनीति पर मुफ्त का मुल्लमा

दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों में मुफ्त सुविधाओं (फ्रीबीज) की घोषणाओं की होड़ मच गई ! आम आदमी पार्टी (आप) तो इस खेल की सिरमोर थी ही, मजे की बात यह है कि 2022 तक "रेवड़ी संस्कृति" की धुर विरोधी रही भारतीय जनता पार्टी भी अब इस होड़ में शामिल हो गई है।

डॉ. त्रिलोक शर्मा
पत्रकार-राजनीतिक विश्लेषक विजिटिंग प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, निरमा यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद

चुनावों के संदर्भ में, विभिन्न राजनीतिक दल मुफ्त सुविधाएं देते हैं। वे सार्वजनिक धन से वस्तुएं और सेवाएं देकर मतदाताओं को लुभाने का प्रयास करते हैं। यह प्रश्न उठता है कि क्या राजनीतिक दल कंपनियां हैं, जो मुफ्त सुविधाओं के माध्यम से खुद को विज्ञापित कर रहे हैं? या क्या चुनाव एक सुपर मार्केट हैं, जहां मतदाताओं को मुफ्त वस्तुएं देकर उन्हें प्रभावित किया जाता है?

दिल्ली के चुनाव प्रचार अभियान ने राजनीतिक विश्लेषकों, बुद्धिजीवियों और आम लोगों के मन में 'मुफ़्त सुविधाओं' को लेकर अनेक सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। मुफ्त सुविधाओं को उन वस्तुओं और सेवाओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो बिना किसी शुल्क के दी जाती हैं। जब हम किसी सुपर मार्केट से कुछ खरीदते हैं, तो कई बार हमें कोई वस्तु मुफ्त में या बहुत कम कीमत पर मिल जाती है। यह एक सामान्य विपणन तकनीक (मार्केटिंग टेक्निक) है जिससे उपभोक्ताओं को आकर्षित किया जाता है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि गरीब वर्गों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है। लेकिन चुनावों में अतार्किक मुफ्त सुविधाओं का प्रयोग जनता को लुभाने के लिए किया जाता है, जिससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की अवधारणा कमजोर होती है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विचार कर रहा है, और इसका निर्णय इस विषय पर एक महत्वपूर्ण दिशा निर्धारित करेगा।

चुनावों के संदर्भ में, विभिन्न राजनीतिक दल मुफ्त सुविधाएं देते हैं। वे सार्वजनिक धन से वस्तुएं और सेवाएं देकर मतदाताओं को लुभाने का प्रयास करते हैं। यह प्रश्न उठता है कि क्या राजनीतिक दल कंपनियां हैं, जो मुफ्त सुविधाओं के माध्यम से खुद को विज्ञापित कर रहे हैं? या क्या चुनाव एक सुपर मार्केट हैं, जहां मतदाताओं को मुफ्त वस्तुएं देकर उन्हें प्रभावित किया जाता है? क्या यह उचित है कि राजनीतिक दल केवल सत्ता में बने रहने के लिए सार्वजनिक धन से मुफ्त सुविधाएं प्रदान करें?

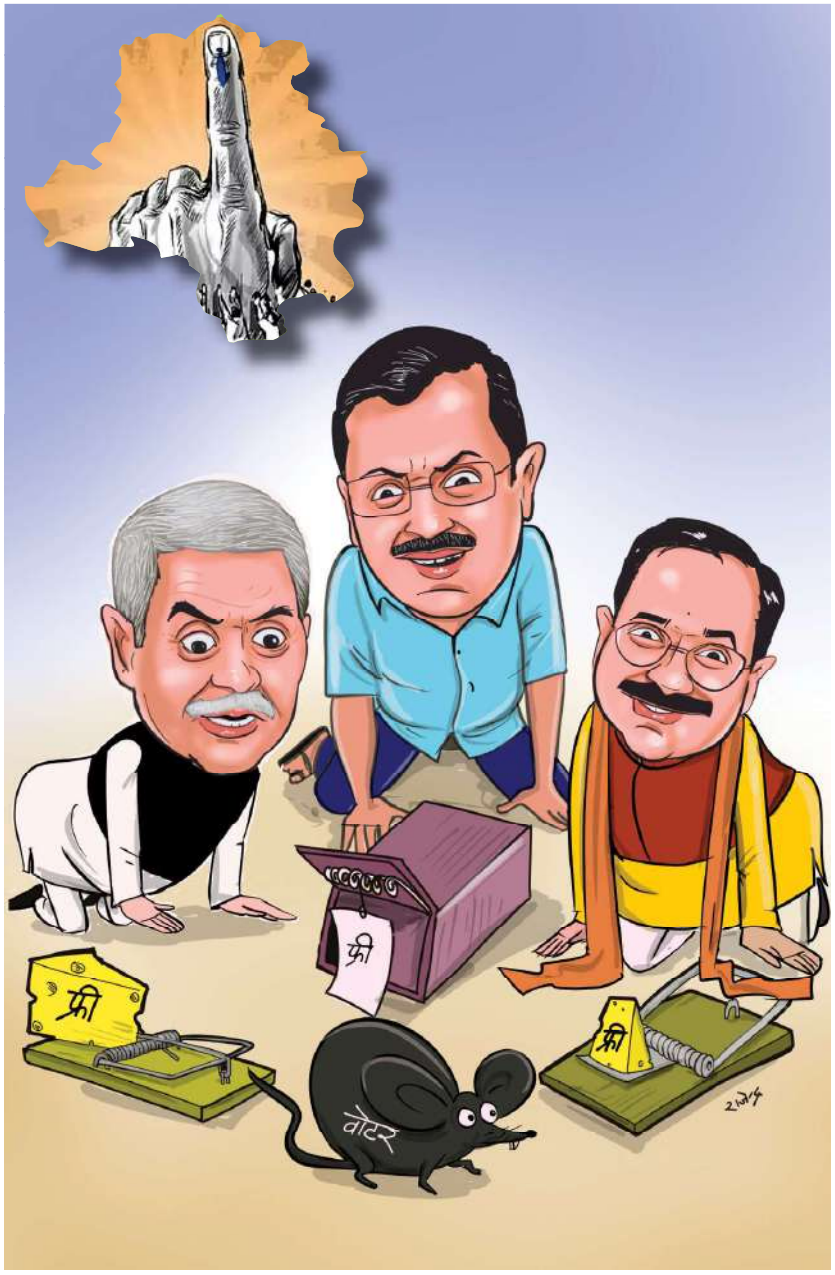

कुछ बुद्धिजीवियों की राय में इस विषय के दूसरे पक्ष को भी पूरी तरह से अनदेखा नहीं किया सकता कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। आज भी बहुत से लोग हैं जिन्हें मुफ्त सुविधाओं की आवश्यकता है। हालांकि, ऐसे भी कई लोग भी हैं जो मुफ्त सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं, जबकि उन्हें उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ सरकारी योजनाएं जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) आज भी प्रभावी हैं। PDS खाद्य, पानी, और वस्त्र जैसी बुनियादी आवश्यकताएं प्रदान करता है। 1992 में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (RPDS) शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य PDS को और मजबूत बनाना था। 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) शुरू की गई, जिसका उद्देश्य गरीबों की स्थिति में सुधार करना था। हालांकि, PDS में भ्रष्टाचार की समस्या भी रही है। आज भी केंद्र सरकार 80 करोड़ जरूरतमंदों को प्रतिमाह मुफ्त राशन दे ही रही है। 2013 में शुरू किए गए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) ने भी गरीबों को राहत प्रदान की है। इस अधिनियम के तहत, 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को सब्सिडी वाले खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाते हैं। यह योजना अभी भी प्रभावी है

2025 के चुनाव प्रचार के आरम्भ में ही आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक दलों को आईना दिखाने के साथ सवाल उठाया है कि जनता के पैसे का इस्तेमाल जनता को लाभ पहुंचाने के लिए क्यों नहीं किया जा सकता, क्यों दिल्ली की तरह पूरे देश में फ्री बिजली नहीं दी जा सकती ?

भाजपा का यू-टर्न

दिलचस्प बात यह है कि 2022 के पंजाब और गुजरात विधानसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी (आप) और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 'रेवड़ी संस्कृति' पर खुलकर हमला बोलते हुए इसे देश की अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र के लिए घातक बताते हुए कहा था कि लोग रेवड़ी बांटकर दोस्त बनाते हैं और बाद में करों से बचने के लिए इसका उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा था कहा था – "राजनीतिक दल वोट पाने के लिए मुफ्त सुविधाएं वितरित करते हैं। मुफ्त सुविधाएं देना जनता को लुभाने और वोट पाने की एक अनैतिक राजनीति है।" इस बयान का आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने विरोध किया और तब यह टिप्पणी बड़े विवाद का विषय बन गई थी और प्रबुद्ध वर्ग से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा में रही। लेकिन अब 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में वही बीजेपी भी इस रेवड़ी संस्कृति का हिस्सा बन गई है।

दिल्ली सरकार घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी वाली बिजली प्रदान करती है लेकिन इसका भार उद्योगों पर अतिरिक्त कर लगाकर डाला जाता है। इस प्रकार, मुफ्त बिजली की सुविधा देने से पूंजीगत खर्चों में कमी आई है, जिससे स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, सड़कों, मेट्रो, और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

ज्ञात रहे, दिल्ली में महिलाओं के लिए दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की बसों में मुफ्त पास की सुविधा दी जाती है। दिल्ली सरकार ने 2017-18 में इस योजना के तहत 70.18 करोड़ की सब्सिडी दी थी, लेकिन दिल्ली आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार, DTC का घाटा 1750.38 करोड़ तक पहुंच गया।

कांग्रेस भी इस होड़ में पीछे नहीं है। यह बदलाव दर्शाता है कि राजनीति में सिद्धांतों से ज्यादा प्राथमिकता चुनावी जीत को दी जाती है।

गुजरात के मतदाताओं की नाराजगी: *दिल्ली चुनावों के दौरान पीएम मोदी द्वारा मुफ्त योजनाओं की घोषणा करने पर गुजरात के लोगों में गहरी निराशा देखी जा रही है। गुजरात पिछले तीन दशकों से बीजेपी के प्रति वफादार रहा है, लेकिन वहां के लोगों को इस तरह की मुफ्त योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। अब गुजरात के मतदाता यह सवाल कर रहे हैं कि जब दिल्ली और अन्य राज्यों के लिए यह संभव है, तो गुजरात को इससे वंचित क्यों रखा गया है? यह सवाल बीजेपी के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर सकता है।*

क्या फ्रीबी (रेवड़ी) संस्कृति लोकतंत्र के लिए सही है?

लोकतंत्र का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना और उनकी क्षमताओं को बढ़ाना होता है। लेकिन जब राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए मुफ्त योजनाओं का सहारा लेते हैं, तो यह दीर्घकालिक विकास की जगह अल्पकालिक लाभ देने का काम करता है। यह रणनीति न केवल कर दाताओं के पैसे की बर्बादी करती है, बल्कि इससे सरकारी संसाधनों का भी दुरुपयोग होता है।

कर दाताओं के पैसे का दुरुपयोग

राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त सुविधाओं की होड़ में कर दाताओं का पैसा इस्तेमाल

किया जा रहा है, जिससे विकास परियोजनाओं और बुनियादी ढांचे पर असर पड़ता है। यह कर दाताओं के पैसे का राजनीतिक फायदा उठाने जैसा है, जिससे सरकारी योजनाओं में असमानता बढ़ रही है। क्या यह उचित है कि मेहनतकश कर दाताओं का पैसा सिर्फ राजनीतिक दलों के वोट बैंक मजबूत करने के लिए खर्च किया जाए?

क्या फ्रीबी एक चुनावी लालच है?

यदि मुफ्त सुविधाओं को चुनावी लालच के रूप में देखा जाए, तो

यह स्पष्ट है कि राजनीतिक दल इसके बिना चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं हैं। यह सवाल उठता है कि क्या राजनीतिक दलों के पास मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई और नीति या योजना नहीं है? क्या जनता को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, और बुनियादी ढांचे के वादों के बजाय मुफ्त सुविधाओं का लालच देना उचित है?

विकसित देशों में मुफ्त योजनाएं

दुनिया के कई विकसित देशों में मुफ्त सेवाओं का प्रावधान किया जाता है,

लेकिन उनका तरीका अलग होता है। स्कैंडिनेवियाई देश जैसे नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क में मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं, लेकिन इसकी भरपाई उच्च कराधान से की जाती है। भारत में, मुफ्त योजनाओं की कोई स्पष्ट वित्तीय योजना नहीं होती, जिससे सरकारों को कर्ज लेना पड़ता है या करदाताओं पर बोझ बढ़ता है।

सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग का नजरिया... सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ने कई बार मुफ्त योजनाओं की वैधता पर सवाल उठाए हैं। 2013 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनावों के दौरान मुफ्त सुविधाओं के वादे चुनावी अनियमितता हो सकते हैं। हाल ही में, भारत के चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि वे मुफ्त योजनाओं के लिए वित्तीय प्रबंधन का स्पष्ट विवरण दें। फिर भी, इस पर कोई ठोस कानून नहीं बना है।

कुल मिला कर दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 ने यह दिखा दिया है कि अब सभी राजनीतिक दल मुफ्त योजनाओं को चुनावी सफलता की कुंजी मानने लगे हैं। जो नेता कभी मुफ्त योजनाओं का विरोध करते थे, वे अब इन्हें चुनावी हथियार बना रहे हैं। इससे यह सवाल उठता है कि क्या भारतीय लोकतंत्र में चुनावी जीत के लिए केवल मुफ्त योजनाओं का ही सहारा रह गया है? यह विचारणीय है कि अगर यही रवैया जारी रहा, तो भविष्य में सरकारें वास्तविक विकास से ज्यादा तात्कालिक लोकप्रियता पर ध्यान केंद्रित करेंगी।

हमार बांग्ला को अमार बांग्ला अभी दूर क्यों?

राजीव हर्ष वरिष्ठ पत्रकार

देश के राजनीतिक हालात कुछ ऐसे हैं कि सभी राजनीतिक दल भाजपा के समक्ष संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। कुछ दल अपनी खोई हुई जमीन हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो कुछ राजनीतिक दलों को भाजपा से कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल वह राज्य है जहां भाजपा अपनी जमीन बनाने के लिए संघर्ष कर रही है।

पश्चिम बंगाल का राजनीतिक परिदृश्य कुछ ऐसा है कि एक बार जो दल सत्ता में आ जाता है फिर उसे सत्ता से बेदखल करना मुश्किल हो जाता है। इस राज्य में वामदल लगातार 34 साल सत्ता में रहे।

एक समय पश्चिम बंगाल भारत की औद्योगिक राजधानी कहलाता था। वाममोर्चा के शासनकाल में पश्चिम बंगाल का औघेगिक विकास रुक सा गया, उद्योग धंधे बंद होने लगे, उद्योगपति विस्थापित होने लगे। मजदूर गरीब और बेहाल थे। उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती थी। इस दौर में भी वाममोर्चा ने अपने वोट बैंक मजदूर और किसान वर्ग पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी। राज्य में तमाम तरह की असुविधाओं और अभाव अभियोगों के बावजूद बुद्धिजीवियों, किसानों और मजदूरों के बल पर वामदलों का शासन निर्विघ्न चलता रहा।

ज्योति बसु के बाद मुख्यमंत्री बने बुद्धदेव भट्टाचार्य भट्टाचार्य ने औद्योगिक वातावरण को बदलने का प्रयास किया। राज्य में बढ़ती बेरोजगारी से निपटने के लिए निवेश को आमंत्रित किया। सरकार ने जिन उद्योगों को आमंत्रित किया नैनो कार परियोजना उनमें से एक थी। बुद्धदेव की इन योजनाओं को नकारात्मक रूप से देखा गया। नैनो और अन्य परियोजनाओं के लिए किए गए भूमि अधिग्रहण ने राज्य में व्यापक आंदोलन को जन्म दिया। वाममोर्चा का वोटबैंक उसके हाथ से निकल गया। नतीजा यह हुआ कि सत्ता वाम मोर्चा के हाथ से निकल गई।

कार्यकर्ताओं की भूमिका

पश्चिम बंगाल में वामदल पूरी तरह तो नहीं, मगर कुछ कुछ एक दलीय लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लेनिन के सिद्धातों पर चल रहे थे। वामदलों के अतिरिक्त अन्य राजनीतिक दलों के उभार को वे सहन नहीं कर पाते थे। अपने जमीनी कार्यकर्ताओं की मदद से दूसरे दलों के उभार को रोकते थे और समाज पर अपनी पकड़ बनाए रखते थे।

वामदलों के शासन काल में जमीनी स्तर के कार्यकर्ता समाज में अहम स्थान रखते थे। हर छोटे मोटे विवाद में, मोहल्ले से लेकर पारिवारिक विवाद तक में उनकी भूमिका अहम होती थी। लोग उनसे परेशान भी होते थे,मगर पुलिस और राजनेताओं के संरक्षण के चलते उनका विरोध करने का साहस नहीं कर पाते थे। बहुत से कार्यकर्ता अपनी इस ताकत के बूते पर सिंडीकेट भी चलाते थे।

इन कार्यकर्ताओं को पता रहता था कि कौन व्यक्ति उनकी पार्टी का समर्थक है और कौन नहीं। चुनाव के दौरान वे पूरा प्रयास करते थे कि विरोधी दलों के समर्थकों मतदान केंद्रों तक पहुंचने ही नहीं दिया जाय। ऐसे कार्यकर्ताओं की बदौलत वामदलों ने बंगाल में 34 साल तक शासन किया।

ममता का उद्भव

वामदलों के शासन के खिलाफ लम्बे समय से संघर्षरत ममता बनर्जी ने भूमि अधिग्रहण से उपजे आंदोलन का नेतृत्व किया, वामदलों से छिटके वोट बैंक को अपने पक्ष में कर अगले चुनाव में उहोंने सत्ता की बागडोर संभाल ली, वे मुख्यमंत्री बनी। वामदलों के बहुत से कार्यकर्ता तृणमूल में शामिल हो गए। तृणमूल ने इन कार्यकर्ताओं के बूते समाज पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली।

संगठन के जरिये सत्ता पर पकड़...

पश्चिम बंगाल में शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का हाल बेहाल है। कानून एवं व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। सड़के दुर्दशाग्रस्त है। रोजगार के अवसरों का अभाव है। राज्य की वित्तीय हालत ठीक नहीं है। मगर तृणमूल कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा बहुत मजबूत है। कार्यकर्ताओं का जाल निचले सत्ता तक फैला हुआ है। संगठन में विरोध के सुरों की कोई जगह नहीं है। ममता बनर्जी सुप्रीमो है। उनके खिलाफ या पार्टी के खिलाफ कोई आवाज उठना संभव नहीं है।

ये हैं भाजपा की राह में रोड़े

भारतीय जनता पार्टी लम्बे समय से सत्ता में आने का प्रयास कर रही है, लेकिन उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है। भाजपा का मुकाबला तृणमूल कांग्रेस से है जिसका संगठनात्मक ढांचा बहुत मजबूत है। उसकी पहुंच बूथ स्तर तक बहुत मजबूत है। वहीं भाजपा संगठनात्मक रूप से उतनी मजबूत नहीं है। संगठन की पहुंच बूथ स्तर तक न होना भाजपा की विफलता का एक बड़ा कारण है। तृणमूल कांग्रेस अपने मजबूत संगठनात्मक ढांचे की बदौलत भाजपा के प्रयासें को सफल नहीं होने दे रही है।

मुस्लिम मतदाता निर्णायक

- पश्चिम बंगाल में भाजपा को अपेक्षित सफलता न मिलने का एक कारण मुस्लिम आबादी भी है। 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी 27.1 प्रतिशत है। लोकसभा की 42 में से 13 और विधानसभा की 294 सीटों में से करीब सौ सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं।
- मुस्लिम मतदाता आमतौर पर भाजपा के खिलाफ मतदान करते हैं। तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी मुस्लिम मतदाताओं को सहेजकर रखने में कोई कसर नहीं छोड़ती।
- भाजपा के खिलाफ लामबंद मुस्लिम मतदाता अपने वोटों का विभाजन भी होने नहीं दे सकते।
- तृणमूल की जीत का आधा सफर तो मुस्लिम मतदाताओं का तृणमूल की तरफ रुझान से ही तय हो जाता है।

अल्पसंख्यक इनसे भी निराश

तृणमूल और भाजपा की प्रतिद्वंद्विता और अपने लगातार खराब प्रदर्शन के चलते कांग्रेस और वामदल उत्साह हीन नजर आते हैं। वे अपने परंपरागत वोट बैंक को भी अपनी ओर खींच नहीं पा रहे हैं। मुस्लिम मतदाता इन दलों से निराश हो चुके हैं और उनके पास तृणमूल को समर्थन देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बच गया है।

यूं चला भाजपा का सियासी सफ़र

s t — भारतीय जनता पार्टी ने ममता को चुनौती देने का प्रयास किया है। भाजपा 1982 में पहली बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव मैदान में उतरी । कुल 52 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। इस चुनाव में भाजपा के महज 129994 वोट हासिल हुए।

s — भाजपा हर लोकसभा और विधान सभा चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करती रही। पहली सफलता उसे 1998 के लोकसभा चुनाव में मिली। इस चुनाव में भाजपा ने 14 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे। इनमें से एक दमदम निर्वाचन क्षेत्र से तपन सिकदर ही जीत पाए।

s — वर्ष 1999 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन कर राज्य में 13 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए और 2 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की।

trrs — भाजपा ने 2001 में हुए विधानसभा चुनाव में 266 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए और पूरे राज्य में कुल 5.68 फीसदी मत हासिल किए।

trry — लोकसभा चुनाव में भाजपा बंगाल से एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन उसका वोट प्रतिशत बढ़ कर 8.06 फीसदी हो गया। उस समय भाजपा की सहयोगी रहीं तृणमूल कांग्रेस को सिर्फ़ 1 लोकसभा सीट पर जीत हासिल हो पाई।

trr — विधानसभा चुनाव में भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और 29 निर्वाचन क्षेत्रों पर चुनाव लड़ा। इन निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 9.89 फीसदी मत हासिल हुए।

trr — लोकसभा चुनाव में भाजपा ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के समर्थन से दार्जिलिंग लोकसभा सीट पर जीत हासिल की। इस चुनाव में भाजपा को पूरे राज्य में 6.14 फीसदी मत मिले।

trsy — लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 2 सीटें जीतीं। इस चुनाव में 3 सीटों पर भाजपा उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे। पूरे राज्य में भाजपा को 17.2 फीसदी मत हासिल हुए।

trs — विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 291 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए 3 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की।

trs — लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 42 निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार खड़े किए और 18 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की।

trty — लोकसभा चुनावों में भाजपा 12 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बीजेपी के सभी आला नेताओं ने पश्चिम बंगाल में 25 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया था, मगर वह 12 सीटों पर सिमट कर रह गई।

कोटा में बढ़ती आत्महत्याएं
बच्चों का 'फंदा' कौन

अजय अस्थाना ✍ वरिष्ठ पत्रकार

हाईकोर्ट ने इन आत्महत्याओं को लेकर ज्यादा गंभीरता दिखाई हैं। स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेकर कोर्ट ने सरकार से साफ शब्दों में कहा है कि सुसाइड रोकने के लिए कानून बनाने का कहा है। नहीं तो दस फरवरी के बाद कोर्ट ही गाइड लाइन जारी करेगा। लेकिन वो कानून या गाइड लाइन अब तक के उपायों से कितनी अलग ओर असरदार होगी? जो यह झकझोर देने वाली घटनाएं रोक पाए।

जिला मजिस्ट्रेट कोचिंग संस्थान के विद्यार्थियों से संवाद करते हैं।

इस वर्ष जनवरी माह में ही कोचिंग सिटी कोटा में छह बच्चों द्वारा की गई सुसाइड से हर कोई स्तबध है। क्या इस सिलसिले का कोई अंत होगा? कब टीनएज पूरी करते मासूम फंदों से लटकना छोड़ेंगे? ऐसे कई सवाल हैं जो शायद हर किसी के दिमाग में नहीं आते हैं, लेकिन कोटा के लोगों के जरूर आते हैं। क्योंकि लगातार बढते हादसे इस तेजी से बढते शहर के लिए चिंता का विषय हैं। आखिरकार कोचिंग सेंटर, पेरेंट्स और सरकार स्टूडेंट्स को आत्महत्या करने से क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? हालांकि इसको लेकर कई कोशिशें कोटा जिला प्रशासन कर चुका है, यह सिलसिला भी जारी हैं। लेकिन महज एक माह में छह आत्महत्या ने सबको झकझोर कर रख दिया है। जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी ने सीधे बच्चों से जुड़कर उनका मानसिक दबाव कम करने के लिए 'कामयाब कोटा' कार्यक्रम शुरू कर 'डिनर विद कलेक्टर' की पहल की हैं। जिसमें बच्चों के साथ बैठकर उनको मोटिवेट कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई कदम उठाए गए हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने इन आत्म हत्याओं को लेकर ज्यादा गंभीरता दिखाई है। स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेकर कोर्ट ने सरकार से साफ शब्दों में सुसाइड रोकने के लिए कानून बनाने के लिए कहा है। नहीं तो दस फरवरी के बाद कोर्ट ही इस संबंध में गाइडलाइन जारी करेगा।

आखिर वजह क्या है?

कोटा में पिछले तीन सालों में जिस गति से छात्रों की संख्या बढी है, उसके अनुरूप् ही आत्महत्याओं का सिलसिला बढा है। आत्महत्या की सबसे बड़ी वजह जो सामने आती है वह बच्चों का पढाई नहीं कर पाना। पुलिस को कई सुसाइड नोट भी मिले हैं, ज्यादातर में स्टूडेंट सफलता नहीं मिलने से परेशान होकर अपने परिजनों के सपने पूरे नहीं करना का मलाल लेकर फंदे को गले लगा लेते हैं। इसके अलावा कुछ मामलो में यह भी सामने आया कि कोई एवरज स्टूडेंट कोचिंग सेंटर में 200-300 बच्चों की क्लास में इतना प्रेशराइज हो जाता है कि उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। ऐसे में बच्चों के एडमिशन से पहले यह जानना जरूरी है कि वह वाकई डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहता है? एडमिशन के बाद भी अगर उसमें पोटेंशियल नजर नहीं आता है तो पेरेंटस को बताना चाहिए। जिससे वह बाद में डिप्रेशन में जाकर कोई गलत कदम नहीं उठाए।

टीन एज में सपोर्टिव सिस्टम महत्वपूर्ण

कोटा में कोचिंग लेने आने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स की उम्र 15 और 17 के बीच में होती है। इस उम्र में जहां शारीरिक और मानसिक विकास का क्रम जारी रहता है वहीं कोमल मन के इन बच्चों के लिए घरों से सैंकड़ों किलोमीटर दूर इस शहर में अकेले रहना आसान नहीं होता है। इसके साथ उन पर परिवारों की उम्मीदें पूरी करने का बोझ भी होता हैं। स्कूली शिक्षा पूरी कर आए इन बच्चों के लिए हर दिन 13-14 घंटों की पढ़ाई, टॉपर्स के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा के दबाव के साथ रहना आसान नहीं होता है। ऐसे में बच्चों को इमोशनल सपोर्ट चाहिए।

अब तक यह हुआ, तो आगे क्या?

सरकारी स्तर पर प्रशासन और पुलिस ने आत्महत्याएं रोकने के लिए प्रयास किए हैं। इनमें पढाई नहीं कर पाने पर कोचिंग और हॉस्टल से फीस रिफंड तक करने की बाध्यता रखी गई, जिससे स्टूडेंट परिजन के दबाव में जबरदस्ती पढाई नहीं करें। इतना ही नहीं कोचिंग व हॉस्टल से जुड़े लोग बच्चों में सुसाइड की प्रवृति व डिप्रेशन की पहचान कर सकें, इसके लिए फैकल्टी, गार्ड से लेकर कुक तक को ट्रेनिंग करवाई गई है। शहर के हर हॉस्टल के पंखों में एंटी सुसाइड रॉड लगवाई गई है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत 16 से कम उम्र के बच्चों को प्रवेश देने पर भी रोक है। हर 3 महीने में पेरेंट्स-टीचर मीटिंग व इनहाउस टेस्ट की मार्कशीट सार्वजनिक नहीं करना भी शामिल है। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि आगे क्या होगा? क्या कानून बनेगा जो आत्महत्याएं रोक पाए?

इस तरह से बदल रहा है ट्रेंड

कोटा में आत्महत्या करने वाले बच्चों में ज्यादातर अन्य प्रदेशों के होते हैं। राजस्थान के बच्चों की संख्या बहुत कम हैं। राजस्थान में कोटा की तरह ही सीकर शहर भी तेजी से कोचिंग सिटी के रूप् में विकसित हो रहा हैं। यहां राजस्थान के बच्चे ज्यादा आते हैं। यहां भी सैंकड़ों हॉस्टल हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त नया ट्रेंड धीरे-धीरे विकसित हो रहा है। एक ही शहर, कस्बे या मिलने वाले बच्चे एक साथ यहां आते हैं तो वे हॉस्टल के बजाय छोटा फ्लेट लेकर रहना पसंद करते हैं। जहां चार बच्चे एक साथ रहते हैं। उनके साथ किसी एक के परिवार का कोई न कोई सदस्य होता हैं। यह सदस्य बारी-बारी बदलते हैं। नवलगढ़ रोड़ पर रहने वाले सुमित के घर में दो फ्लेट हैं। सुमित कहते हैं कि हमारे यहां नौ बच्चे रहते हैं। उनके साथ दो अभिभावक रहते हैं। वे खुद पूरा ध्यान रखते हैं। कोटा में भी ऐसा हो रहा है लेकिन बहुत कम। इसकी वजह है यहां दूर दराज से स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ऐसे में अभिभावकों के लिए साथ रहना संभव नहीं होता है।

कोटा में वर्ष 2014 से 2024 के बीच 143 आत्महत्या

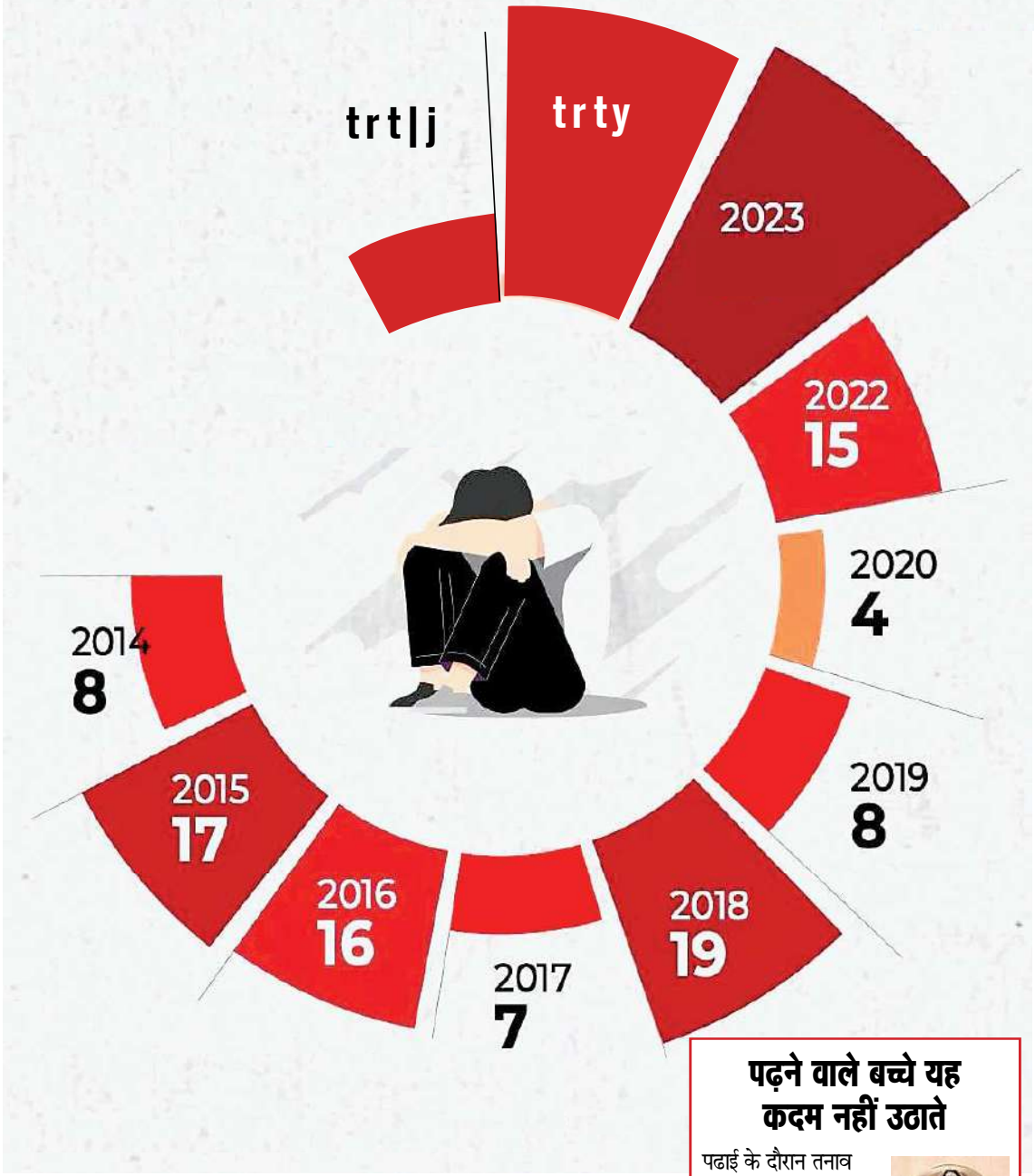

कोटा कोचिंग स्टूडेंट सुसाइड केस साल 2025

पहला मामला • 8 जनवरी, हरियाणा के महेंद्रगढ़ निवासी छात्र नीरज
दूसरा मामला • 9 जनवरी, मध्य प्रदेश के गुना जिले का निवासी अभिषेक लोधा
तीसरा मामला • 15 जनवरी, ओड़िशा का अभिजीत गिरी
चौथा मामला • 18 जनवरी, राजस्थान के बूंदी जिले का निवासी मनन जैन
पांचवा मामला • 22 जनवरी, गुजरात की अहमदाबाद निवासी छात्रा अफ्शा शेख
छठा मामला • 22 जनवरी, असम के नागांव निवासी छात्र पराग

पढ़ने वाले बच्चे यह कदम नहीं उठाते

पढाई के दौरान तनाव वही बच्चे महसूस करते हैं जो तैयारी कर नहीं पाते या फिर उन्हें जबरदस्ती यहां भेज दिया गया है। जो पढ़ने वाले होते है वे तनाव ग्रसित नहीं होते हैं। ऐसे में एडमिशन से पहले कोचिंग सेंटर बच्चे का पोटेंशियल देखें, उससे पूछे वह यह चाहता या नहीं। एडमिशन के बाद भी समय रहते पेरेंटस से उसके स्टेटस के बारे में बताएं जिससे समय रहते सही निर्णय लें और बच्चे गलत कदम नहीं उठाए।
-रविदत्त गौड़, आईजी पुलिस कोटा रेंज

साइबर अरेस्ट रोकथाम के लिए अब AI औजारों की दरकार

प्रो. (डॉ.) सचिन बत्रा
सलाहकार,
मीडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया, दिल्ली

आज के नए दौर में साइबर अपराधी भी नए नए पैंतरे अपनाकर अनूठे तरीके से जुर्म कर रहे हैं। इसमें सबसे सनसनीखेज वारदात हैं साइबर अरेस्ट की। उदाहरण के लिए नोएडा के सेक्टर 128 की ही घटना में पीड़िता चांद गांधी को 48 घंटे फोन पर ही यह कहते नजरबंद कर दिया गया है कि उन्होंने जो पार्सल भेजा था उसमें नकली पासपोर्ट और ड्रग्स पाई गई है। शातिर साइबर अपराधियों ने उनपर इतना मनोवैज्ञानिक दबाव डाला कि उन्हें दो किश्तों में 65 लाख रूपए देने ही पड़े। ऐसे नए मामले तो अब पुलिस ही नहीं जांच एजेंसियों को भी चौंकाने लगे हैं। इसका कारण यह है कि साइबर अरेस्ट ऐसी मनोवैज्ञानिक प्रताड़ना है जिसमें व्यक्ति औचक आरोपों और कार्रवाई की घंटो लंबी कवायद के चलते अपने मोबाइल पर आई वीडियो काल से बरी ही नहीं हो पाता। आखिरकार विवश होकर अपनी लाखों की धन संपदा को अपराधियों के हवाले करने को मजबूर हो जाता है। अचूक मनोवैज्ञानिक दबाव और कानूनी कार्रवाई के भय से की जाने वाली डिजिटल गिरफ्तारी के मामले अभी इतने नए हैं कि इससे निपटने की समझ अभी समाज में विकसित ही नहीं हुई है। क्योंकि डिजिटल अरेस्ट एक अचानक होने वाली ऐसी कार्रवाई है जो किसी एक व्यक्ति पर मनी लॉन्ड्रिंग, आय से अधिक संपत्ति, पार्सल में ड्रग्स, भ्रष्टाचार, अवैध धन, विदेश से प्राप्त धन या हवाला का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई और जेल की धमकी से भ्रमित कर देती है। लिहाजा अब ऐसे मामलों से सावधान और बचाव करने के लिए एआइ औजारों सहित डिजिटल एलर्ट सिस्टम तैयार करना आवश्यक हो गया है।

भारत में साइबर अपराध के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हालिया मामले इसका जीता-जागता उदाहरण हैं, जैसे कि लुधियाना के 82 वर्षीय व्यवसायी को मनी लॉन्ड्रिंग के फर्जी आरोप में फंसाने की धमकी देकर 7 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी या फिर दिल्ली की एक महिला वकील से नशीले पदार्थों की तस्करी के झूठे आरोप में 14 लाख रुपये ठग लेना। इन घटनाओं ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर एक वकील जैसे कानून के पेशेवर भी साइबर अपराधियों के सम्मोहन और मनोवैज्ञानिक दबाव के आगे लाचार हो सकते हैं, तो आम आदमी इन खतरों से कैसे बचेगा? वहीं पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए यह मामले इतने नए है कि बचाव व रोकथाम के लिए उपायों पर मंथन किया जा रहा है। परेशानी यह है कि साइबर अपराधी पहले किसी शिकार के व्यक्तिगत आंकड़ों को हासिल करते हैं, फिर उसे डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर फर्जी अधिकारियों के रूप में मानसिक प्रताड़ना देते हैं।

यह केवल भारत की समस्या नहीं है; अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसे विकसित देशों में भी साइबर धोखाधड़ी ने विकट समस्या का रूप ले लिया है। FBI की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका में साइबर अपराध से एक साल में 2.4 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। हालांकि कुछ एआइ टूल्स साइबर अपराधियों के खिलाफ कारगर साबित हुए हैं। मसलन, क्राउडस्ट्राइक एक उन्नत सुरक्षा टूल है, जो डेटा पर हमले या सेंधमारी की पहचान करते हुए रोकथाम में मददगार माना जाता है। यह डिजिटल शोषण और अनाधिकृत हस्तक्षेप पर नकेल कसने के लिए उपयुक्त है। इसी प्रकार, जीरोफॉक्स सोशल मीडिया और डिजिटल चैनलों की निगरानी में दक्ष है, जो ऑनलाइन फ्रॉड, इनफॉर्मेशन लीक और फिशिंग के मामलों को रोकने में सहायक है। देखा जाए तो आम तौर पर एआइ टूल्स व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, बैंकों और सरकारी एजेंसियों को तो सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं, पर आम नागरिक को डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन एक्सटॉर्शन जैसी घटनाओं से बचने के लिए कोई ठोस सुरक्षा उपाय उपलब्ध नहीं है। इसके चलते आज साइबर अपराधियों का सबसे आसान शिकार आम आदमी बनता जा रहा है, जिसके पास इन अपराधों से बचने के लिए न कोई समझ है और न ही साधन।

वैसे तो भारत सरकार ने भी साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आई4सी (इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर) और 1930 हेल्पलाइन जैसी पहल की हैं, जो साइबर अपराध के मामलों में तत्काल सहायता प्रदान करती है। फिर भी डिजिटल अरेस्ट और साइबर एक्सटॉर्शन के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस क्षेत्र में और अधिक ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। साथ ही डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए एआइ औजार विकसित कर एक संगठित और समर्पित तंत्र बनाया जाए, जो आम नागरिक को साइबर अपराधियों से सुरक्षित रख सके।

अब वक्त आ गया है कि मोबाइल निर्माता कंपनियां, बैंक और सरकार मिलकर एआइ आधारित सुरक्षा तंत्र विकसित करें। यह तंत्र लोगों के मोबाइल, टैब या कंप्यूटर पर पहले चरण में ही अलार्म या चेतावनी देने में सक्षम होना चाहिए, ताकि उन्हें किसी भी डिजिटल धोखाधड़ी से सचेत किया जा सके। साथ ही, ऐसे एआइ एप्लिकेशन विकसित किए जा सकते हैं, जो साइबर अपराधियों की गतिविधियों के एल्गोरिदम पर आधारित हों। जब कोई अपराधी फर्जी अधिकारी बनकर किसी व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट करता है, तो वह व्यक्ति त्वरित रूप से खतरे की चेतावनी पा सके। हालांकि जागरूकता को साइबर सुरक्षा का पहला कदम माना जाता है, लेकिन आज के डिजिटल युग में केवल चेतना से ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। आम नागरिकों को साइबर अपराधियों के सम्मोहन और मनोवैज्ञानिक हमलों से बचाने के लिए एआइ आधारित सुरक्षा ही कारगर साबित होगी।

संगठन की बागडोर युवाओं के हाथ

जोधपुर में राजेंद्र पालीवाल बने भाजपा शहर

भारतीय जनता पार्टी युवाओं के हाथ कमान सौंपने की ओर कदम बढ़ा चुकी है। सत्ता और संगठन मिलकर प्रदेश के विकास की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके मद्देनजर प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व युवा कार्यकर्ताओं को फ्रंटलाइन में ला रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब भाजपा का चेहरा यूथ ओरिएंटेड होगा। राजस्थान सहित पूरे प्रदेश में भाजपा के संगठनात्मक चुनाव अभी चल रहे हैं। इसे पार्टी ने संगठन पर्व नाम दिया है यानी चुनाव को भी पर्व के रूप में लिया जा रहा है। देशभर में संगठनात्मक चुनाव के साथ राजस्थान में भी संगठन पर्व के तहत अधिकांश जिलों में संगठनात्मक चुनाव हो चुके हैं। प्रदेश के दूसरे बड़े शहर जोधपुर में भी युवा चेहरों को बागडौर सौंपी गई है। जोधपुर शहर और जोधपुर देहात में लम्बे अर्से बाद संगठन का नेतृत्व युवाशक्ति को सौंपा गया है। जोधपुर शहर के सभी बारह मण्डलों में युवाओं को ही चुना गया है। जोधपुर भाजपा शहरं जिलाध्यक्ष पद पर इस बार युवा कार्यकर्ता तेजतर्रार राजेन्द्र कुमार पालीवाल को अध्यक्ष चुना गया है। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन राठौड़ ने सर्वसम्मति चुनाव के बाद राजेन्द्र कुमार पालीवाल के नाम की घोषणा की। वहीं जोधपुर देहात दक्षिण में युवा नेता त्रिभुवन सिंह भाटी को अध्यक्ष चुना गया।

मान-सम्मान के साथ कार्यकर्ताओं का काम पहली प्राथमिकता: पालीवाल

संगठन में नई जिम्मेदारी मिलने पर भाजपा शहर जिलाध्यक्ष राजेन्द्र कुमार पालीवाल ने कहा कि संकल्प के साथ संगठन का काम प्राथमिकता के साथ करना पहला दायित्व है। केन्द्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है। प्रयास रहेगा कि जोधपुर में जनप्रतिनिधियों और भाजपा के वरिष्ठजनों के मार्गदर्शन में अधिक से अधिक विकास कार्य करवाया जाए। संगठन में कार्यकर्ता ही सर्वोपरि है। कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रहे, इसी उद्देश्य के साथ कम करेंगे।

जिलाध्यक्ष

35 वर्षों से संगठन में सक्रिय हैं राजेन्द्र पालीवाल

सूरसागर विधानसभा क्षेत्र में चौपासनी हाउसिंग बोर्ड निवासी राजेन्द्र कुमार पालीवाल का परिवार आरंभ से ही विचार परिवार और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है। राजेन्द्र कुमार पालीवाल करीब 35 वर्षों से भी अधिक समय से संगठन में सक्रियता से काम कर रहे हैं। उन्होंने वर्ष 2009 में वार्ड संख्या 6 से पार्षद का चुनाव लड़ा और बड़े अन्तर के साथ चुनाव जीता। वर्ष 2009 से 2014 तक पार्षद के रूप में क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण कराया और विकास कार्य करवाए। बाद में भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी में कोषाध्यक्ष रहे। संगठन में लगातार काम करने पर उन्हें जोधपुर शहर जिला कार्यकारिणी में जिला मंत्री और फिर जिला उपाध्यक्ष पद पर काम करने का मौका मिला। इस दौरान पालीवाल ने संगठन में सक्रियता से काम किया। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों में पूरे जोश के साथ किया और चुनाव में अहम भागीदारी निभाई। स्वर्गीय श्री गोपीकिशन पालीवाल के पुत्र राजेन्द्र कुमार पालीवाल ने जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से स्नातक किया। 10 सितम्बर 1971 को जन्मे राजेन्द्र पालीवाल बिल्डिंग डेवलपर हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं।

संगम की डुबकी
मोक्ष बनाम माया

प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू सनातन धर्म का महापर्व महाकुंभ की छटा पूरे शबाब पर है। रिपोर्ट लिखे जाने तक अमेरिका समेत कई देशों की पूरी आबादी से ज्यादा लोगों ने पवित्र संगम में डुबकी लगा ली थी। प्रतिदिन 30 से 50 लाख की संख्या में श्रद्धालु संगम में मोक्ष प्राप्ति की मंशा से डुबकी लगा रहे हैं। अवकाश के दिनों और शाही अथवा अमृत स्नान के दिन इनकी संख्या बढ़ जाती है। अकेले मौनी अमावस्या के दिन 8 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में डुबकी लगाई। हालांकि तीन जगहों पर मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ भी मची जिसमें कुछ लोगों को जान गंवानी पड़ी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगदड़ की घटना की न्यायिक जांच और मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिये हैं। गाहे-बगाहे मेला क्षेत्र में आगजनी की घटनाएं भी हुई लेकिन प्रशासन की चाक-चौबंद व्यवस्था के कारण काबू पा लिया गया।

राधा रमण
वरिष्ठ पत्रकार

महाकुंभ की भव्यता देखते ही बनती है। समूचा मेला क्षेत्र लगभग 40 किलोमीटर के दायरे में समाया हुआ है। वैसे तो हर कुंभ-महाकुंभ में कुछ साधु-महात्मा को महामण्डलेश्वर की उपाधि प्रदान करने की परंपरा रही है, तो कुछ लोग सनसनी बनते रहते हैं। इस बार इनकी संख्या बहुतायत है।

मॉडल हर्षा रिछारिया का शाही रथ पर बैठना बना विवाद

महाकुंभ के पहले अमृत स्नान के दिन शाही रथ पर बैठने के कारण मॉडल और एंकर हर्षा रिछारिया को संतों के भारी विरोध को झेलना पड़ा था। कई संतों ने तो इसे सनातन धर्म के अपमान से जोड़ दिया था। नतीजतन, हर्षा का एक भावुक वीडियो वायरल होने लगा था जिसमें वह रोते-रोते महाकुंभ छोड़कर जाने की बात कहने लगी थीं। हालाँकि अखाड़ा परिषद् के अध्यक्ष महंत रवीन्द्र पुरी से मिलने के बाद हर्षा ने अपना मन बदल लिया है। उन्होंने कहा है कि उनके जीवन का लक्ष्य सनातन धर्म की ध्वजा फहराना है। इसलिए वह अब कुंभ छोड़ कर कहीं नहीं जाएँगी। उधर, महंत रवीन्द्र पुरी ने भी हर्षा को अपनी धर्मपुत्री बताते हुए कहा है कि हर्षा को फिर से शाही रथ पर बिठाया जाएगा और अमृत स्नान कराया जाएगा। उत्तराखंड की मूल निवासी और झांसी- भोपाल मे पली-बढ़ी हर्षा रिछारिया ने अपने इन्स्टाग्राम पर खुद को मेकअप आर्टिस्ट, सोशल एक्टीविस्ट, ट्रेवल ब्लॉगर और एंकर बताया है। उनका कहना है कि अब वह सबकुछ छोड़कर संन्यास के मार्ग की और बढ़ रही हैं। हालाँकि अभी उन्हें साध्वी कहना ठीक नहीं है। उन्होंने अभी तक दीक्षा नहीं ली है। सिर्फ निरंजनी अखाड़ा के महंत महामण्डलेश्वर कैलाशानंद जी से गुरुमंत्र लिया है। हर्षा रिछारिया के सोशल मीडिया पर 18 लाख फालोवर हैं।

विवाद होने के बाद पद से हटा दिया गया

पूर्व फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी की इन दिनों काफी चर्चा हो रही है. कुछ दिन पहले उन्हें किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया, लेकिन विवाद होने के बाद उन्हें इस पद से हटा दिया गया। उन्हें महामंडलेश्व बनाए जाने पर कई साधु संतों ने विरोध किया था, जिसमें बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेंद्र शास्त्री और योग गुरु बाबा रामदेव भी शामिल थे।

ममता कुलकर्णी ने ये भी कहा कि वो महामंडलेश्वर नहीं बनना चाहती थीं, लेकिन किन्नर अखाड़े की आचार्य रहीं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने उन्हें इसके लिए मजबूर किया। वो तो बनने के लिए तैयार भी नहीं थीं।
ममता का कहना है कि इसके लिए उन्होंने 23 वर्ष तक तपस्या की है। यह अलग बात है कि 90 के दशक में कई हॉट फिल्मों की हीरोइन रहीं ममता का नाम ड्रग तस्करी से भी जुड़ा रहा है। ममता की ड्रग तस्कर विक्की गोस्वामी से दोस्ती की चर्चा सरेआम रही है। वह करीब 24 वर्षों तक भारत से दूर केन्या में रहीं और बाम्बे हाईकोर्ट से बरी होने के बाद भारत लौटी हैं। ममता का विरोध करने वालों में बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री भी शामिल हैं। उनका कहना है कि किसी को उसके प्रभाव में आकर महंत या महामण्डलेश्वर नहीं कह सकते, जब तक कि उसके अंदर साधुत्व का भाव न प्रस्फुटित हो जाए।

मोनालिसा की नीली आंखों के फैन यूट्यूबरों की लगी लाइन

महाकुंभ में मध्यप्रदेश के महेश्वर से माला बेचने आईं मोनालिसा की भी जबरदस्त चर्चा रही। मोनालिसा ने एक दिन अपना वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड क्या कर दिया, वह उनके गले की फांस बन गई। लोग उनकी नीली आंखों के इतने फैन हो गए कि दूसरे दिन से उनके यहाँ यूट्यूबरों की लाइन लगने लगी। उनका रहना-खाना-सोना तक दुश्वार हो गया। दिन हो या रात उनके ठिकाने पर यूट्यूबरों की भीड़ जुटने लगी। माला बिकना बंद हो गया। इससे वह रोने लगी। आखिर में उनके पिता को उन्हें वापस घर भेजना पड़ा।

विवादास्पद हरकतों के कारण आईआईटी बाबा चर्चा में बने

महाकुंभ में आजकल आईआईटी बाबा के नाम से मशहूर हरियाणा के अभय सिंह की चर्चा भी जोरों पर है। उनका दावा है कि 'मुझे अपने पिछले जन्म का सबकुछ पता है और मुझ में भगवान दिखते हैं। और तो और, अभय सिंह श्मशान में हड्डियां खाने का भी दावा करते हैं। कभी लंबी दाढ़ी और बिखरे बाल रखनेवाले अभय सिंह कभी क्लीन सेव भी हो जाते हैं। वह कहते हैं कि भगवान शिव भी रूप बदलते रहते थे। इसीलिए मैं भी रूप बदलते रहता हूँ। हालाँकि अभय सिंह की बातों से न तो उनके परिवार के लोग इत्तेफाक रखते हैं न ही महाकुंभ में आये अनेक साधु-संतों को उनकी बातों पर भरोसा है। वह कभी फूट-फूटकर रोने लगते हैं तो कभी ठहाका लगाकर हँसने लगते हैं। इसीलिए कुछ लोग उन्हें पागल तक करार देते हैं। अभय सिंह के पिता कर्ण सिंह वकील हैं और माता गृहिणी। पिता बताते हैं कि वह पढने में मेधावी था। आईआईटी मुंबई से एयरोस्पेस में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद उसने कनाडा में नौकरी भी की थी। कोरोना के बाद भारत लौटने पर कुछ दिन यहाँ ठीक रहा। हम उसका घर बसाने की तैयारी में थे। लेकिन पिछले 11 माह से बिना बताये घर से चला गया। पिछले छह माह से तो उसके बारे में कुछ पता भी नहीं था। उसने हम घरवालों का फोन नंबर ब्लॉक कर रखा है। महाकुंभ में अभय की जानकारी मिलने के बाद माता-पिता अभय को मनाने महाकुंभ भी गए थे लेकिन अभय सिंह ने उनसे मुलाक़ात करना गंवारा नहीं समझा। अभय सिंह ने कहा कि छह महीने से काशी में था तब क्यों नहीं मिलने आये, अब क्यों आये हैं ? अभय सिंह महाकुंभ की शुरुआत में जूना अखाड़े में रहे लेकिन उनके संदिग्ध चरित्र और विवादास्पद हरकतों के कारण उन्हें अखाड़े वालों ने निकाल दिया। जूना अखाड़े के संतों ने अभय पर अपने गुरु को गाली देने और हर समय नशे में रहने का आरोप लगाया। अब वह मेले में रोज नये-नये ठिकानों में दिखाई देते हैं।

बालक नागा संन्यासी को देखने को कम भीड़ नहीं जुटती

महाकुंभ में 8 साल के नागा संन्यासी गोपाल गिरी की भी खूब चर्चा है। वह जूना अखाड़े से जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा के रहनेवाले गोपाल गिरी को उनके माता-पिता ने 3 वर्ष की कच्ची उम्र में जूना अखाड़े को सौंप दिया था। बाद में अखाड़े ने उन्हें शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा देकर दीक्षित किया। अब उनका परिवार से कोई नाता नहीं रह गया है। गोपाल गिरी कहते हैं कि उनका मन न तो खिलौनों से खेलने में लगता है न ही सांसारिक दुनिया में वापस जाना चाहते हैं। वह शास्त्रार्थ करते रहते हैं और भजन गुनगुनाते रहते हैं। भीषण सर्दी में गोपाल गिरी भभूत लगाये और रुद्राक्ष की माला पहने अखाड़े के बाहर बैठे रहते हैं। उनको देखनेवालों की भीड़ लगी रहती है।

स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल भी खूब चर्चा में रहीं

महाकुंभ के शुरुआती दिनों में एपल कंपनी के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल भी खूब चर्चा में रहीं। वह 11 जनवरी को ही मेला क्षेत्र में महंत कैलाशानंद गिरी के आश्रम में कल्पवास करने के इरादे से आ गई थीं। लेकिन तबियत खराब हो जाने के कारण उन्हें चौथे दिन ही वापस लौटना पड़ा। लॉरेन पावेल ने कहा था कि वह अपने दिवंगत पति की अधूरी इच्छा को पूरी करने के इरादे से महाकुंभ में आई हैं। उनके पति का वर्ष 2011 में बीमारी से निधन हो गया था। लॉरेन स्वयं इमर्सन कलेक्टिव नामक संस्था की फाउंडर अध्यक्ष हैं। यह संस्था समाज कल्याण, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और विस्थापन के क्षेत्र में सक्रिय है। लॉरेन की कुल संपत्ति जानी-मानी पत्रिका फ़ोर्ब्स के मुताबिक़ 15.2 बिलियन डॉलर है। महामण्डलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने उन्हें गुरुमंत्र और कमला नाम दिया है।

बॉडी बिल्डर बाबा ने हिन्दू धर्म को अपनाया, उसी में मग्न हो गए

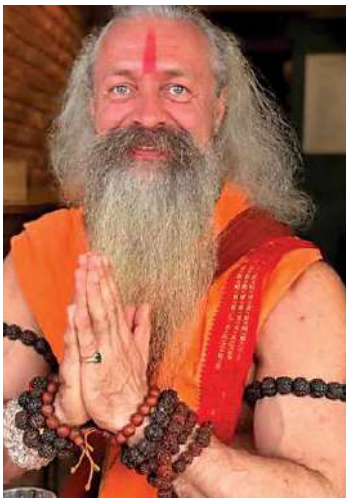

महाकुंभ में सात फीट लंबे बॉडी बिल्डर बाबा उर्फ़ आत्म प्रेम गिरी महाराज भी खूब आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं। बॉडी बिल्डर बाबा सोवियत रूस के नागरिक हैं। वह पहले स्कूल टीचर थे। करीब 30 साल पहले भारत घूमने आये थे। यहाँ इनका मन अध्यात्म और भारत की सनातन परंपरा में इस कदर रम गया कि यहीं के होकर रह गए। उनकी हिन्दू धर्म में आस्था है। उन्होंने न सिर्फ हिन्दू धर्म को अपना लिया बल्कि उसी में मग्न हो गए। गले में रुद्राक्ष की माला, शरीर पर पीला वस्त्र और गले में टंगा थैला - यही इनकी पहचान बन गई। लोग इनकी लंबी कद काठी के कारण इन्हें भगवान परशुराम का अवतार मानने लगे।

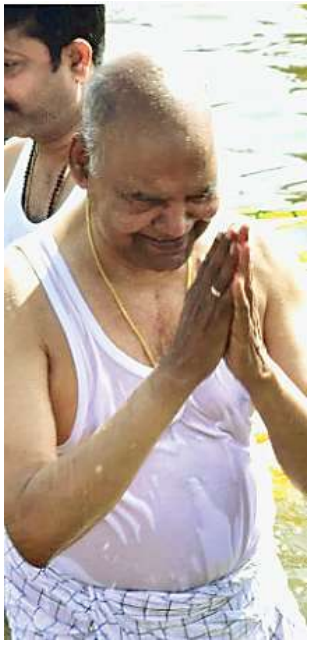

उल्लेखनीय है कि प्रयागराज महाकुंभ में अबतक 73 देशों के लोग डुबकी लगा चुके हैं। देश-विदेश से लोगों का आना लगातार जारी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव समेत कई राजनेता, लोकप्रिय नृत्यांगना सपना चौधरी, कई फ़िल्मी हस्तियाँ और उद्योगपति गौतम अडाणी और अनिल अंबानी सहित अनेक नामचीन लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। दिन हो या रात, संडे हो या मंडे, मेले की छटा देखते ही बनती है। तो देर किस बात की, आप भी आइए और पवित्र संगम में अपने परिजनों समेत डुबकी लगाइए, क्योंकि मान्यता है कि कुंभ में डुबकी लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है।

ब्यूरोक्रेसी में तालमेल की कमी

विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं पर संकट

विवेक श्रीवास्तव
वरिष्ठ पत्रकार

राज्य में सुचारू शासन और विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नौकरशाही (ब्यूरोक्रेसी) और सरकार के बीच बेहतर तालमेल आवश्यक होता है। लेकिन हाल ही में राजस्थान में प्रशासनिक समन्वय की कमी स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है, जिससे न केवल सरकारी योजनाएँ अधर में लटकी हुई हैं, बल्कि जनप्रतिनिधियों और आम जनता में भी असंतोष बढ़ रहा है।

सरकार की नीतियों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए प्रशासनिक मशीनरी का सुचारू रूप से कार्य करना आवश्यक है। लेकिन जब शीर्ष स्तर पर समन्वय की कमी हो, तो न केवल निर्णय लेने की प्रक्रिया बाधित होती है, बल्कि विकास कार्यों की गति भी धीमी पड़ जाती है। राजस्थान में हाल ही में ट्रांसफर प्रक्रिया से लेकर निवेशकों को राहत देने तक के मामलों में यह असंतुलन साफ झलक रहा है।

ट्रांसफर प्रक्रिया में देरी से विधायकों की बढ़ी नाराजगी

राजस्थान में ट्रांसफर बैन हटाए जाने और इसे पाँच दिन के लिए बढ़ाए जाने के बावजूद कई विभागों में तबादले अब तक लंबित हैं। इस देरी ने विधायकों और मंत्रियों की परेशानी बढ़ा दी है। खासकर राजस्व विभाग में राजस्व मंत्रालय और राजस्व बोर्ड के बीच की खींचतान के चलते अब तक एक भी ट्रांसफर नहीं हो पाया है।

विधायकों में तहसीलदारों और पटवारियों के तबादले न होने को लेकर भारी असंतोष देखने को मिल रहा है। कई विधायकों ने मंत्रियों से खुलकर असहमति जताई है और अपनी चिंता व्यक्त की है कि यदि प्रशासनिक पदों पर इच्छित अधिकारियों की नियुक्ति नहीं होती, तो विकास कार्यों की गति धीमी हो जाएगी। कई स्थानों पर पुराने अधिकारियों के बने रहने से जनता और सरकार के बीच संवाद की समस्या उत्पन्न हो रही है।

कार्यशैली पर उठते सवाल

राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। उन पर प्रशासनिक समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब तक वे इसमें सफल नहीं हो पाए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की अपेक्षाओं के बावजूद कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक फैसले अब भी लंबित हैं।

आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की आधी-अधूरी सूची ही जारी हो पाई है, जिससे नौकरशाही में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हाल ही में मुख्य सचिव ने बाड़मेर और जैसलमेर का दौरा किया और जिला प्रशासन के साथ बैठक की, लेकिन सोलर कंपनियों के निवेशकों को प्रशासन से कोई राहत नहीं मिली। इससे हताश होकर भारतीय सोलर संघ ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई है।

अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव

प्रशासनिक समन्वय की कमी का प्रभाव केवल राजनीतिक प्रतिनिधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर राज्य की आर्थिक वृद्धि और निवेश के माहौल पर भी पड़ रहा है।

राजस्थान सरकार की ओर से निजी और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन यदि निवेशकों को अनुकूल वातावरण प्रदान करने में असमर्थ रहता है, तो यह प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक साबित हो सकता है।

बाड़मेर और जैसलमेर में सोलर कंपनियों के निवेशक सरकार से आवश्यक सहायता की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन प्रशासनिक अड़चनों के कारण वे असमंजस में हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी मुख्य सचिव की निष्क्रियता पर नाराजगी जाहिर की है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि ब्यूरोक्रेसी को सही दिशा में नहीं लाया गया, तो यह सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है।

समन्वय और पारदर्शिता बढ़ाने की आवश्यकता

सरकारी नीतियों और निर्णयों का प्रभावी क्रियान्वयन तभी संभव हो सकता है, जब ब्यूरोक्रेसी और सरकार के बीच मजबूत तालमेल हो। इसके लिए आवश्यक है कि—

1. ट्रांसफर प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए, ताकि राजनीतिक दबाव के बजाय योग्यता के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति हो।
2. प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए, ताकि वे योजनाओं को समय पर लागू कर सकें।
3. निवेशकों को आवश्यक सरकारी सहायता मिले, ताकि वे बिना किसी अनावश्यक देरी के अपने प्रोजेक्ट पूरे कर सकें।

अधिकारियों का 'रील प्रेम' भी बन रहा संकट

हाल ही में राजस्थान के कई जिलों में अधिकारियों के सोशल मीडिया पर अधिक सक्रिय रहने की प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। कई अधिकारी अपने कर्तव्यों को निभाने की बजाय रील्स और वीडियो बनाने में व्यस्त नजर आ रहे हैं।

हाल ही में बाड़मेर के सेड़वा में एक एसडीएम का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वे एक चिकित्सक से दुर्व्यवहार कर रहे थे। यह दिखाता है कि प्रशासनिक अधिकारी प्रचार और प्रसिद्धि की ओर अधिक झुकाव रख रहे हैं, जबकि जनता की समस्याओं का समाधान करने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश को विकास की नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने की पूरी संभावनाएँ हैं। लेकिन यदि प्रशासनिक ढांचे में समुचित सुधार नहीं किए गए, तो यह संभावनाएँ सीमित हो सकती हैं।

AI की दुनिया में जबरदस्त हंगामा

अलीबाबा ने डीपसीक को भी पीछे छोड़ा

चीनी की बड़ी तकनीकी कंपनी और मार्केट प्लेस के रूप में मशहूर अलीबाबा ने क्यूवेन (Qwen) 2.5 आर्टिफिशल इंटेलीजेंस का नया मॉडल जारी किया है। अली बाबा का दावा है कि जिस डीपसीक की इतनी तारीफ की जा रही है, उसका क्वेन 2.5 मॉडल उससे भी आगे निकल गया है। क्यूवेन 2.5 मैक्स की रिलीज का समय असामान्य है। चीनी लोग चीनी नव वर्ष के पहले दिन काम नहीं करते हैं और अपने परिवारों के साथ समय गुजार रहे होते हैं। इसके बावजूद अली बाबा ने बुधवार (29 जनवरी) को अपना एआई मॉडल जारी कर दिया। यह घटनाक्रम बता रहा है कि एआई की दुनिया में किस कदर मुकाबला शुरू हो गया है। और इससे चीन की कंपनियों में जो होड़ मची है, उसका भी नोटिस लिया जाना चाहिए।

अलीबाबा के एआई मॉडल पर बात करने से पहले यह जान लीजिए कि भारत में एआई पर ताजा सूचना क्या है। भारत के आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार (30 जनवरी) को कहा कि भारत ने 10,370 करोड़ रुपये के इंडिया एआई मिशन (India AI Mission) शुरू करने और घरेलू भाषा में इसका मॉडल बनाने का फैसला किया है। सरकार ने 10 कंपनियों को भी चुना है जो 18,693 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट या जीपीयू की आपूर्ति करेंगी। इनसे मशीन लर्निंग टूल विकसित करने के लिए और अंत में मॉडल बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। इन कंपनियों में हीरानंदानी समूह समर्थित योट्टा, जियो प्लेटफॉर्म्स, टाटा कम्युनिकेशंस, ई2ई नेटवर्क्स, सीएमएस कंप्यूटर्स, Ctrls डेटासेंटर, लोकुज एंटरप्राइज सॉल्यूशंस, नेक्स्टजेन डेटासेंटर, ओरिएंट टेक्नोलॉजीज और वेन्सिस्को टेक्नोलॉजीज शामिल हैं।

अलीबाबा की क्लाउड यूनिट ने ओपनएआई और मेटा के सबसे उन्नत एआई का जिक्र करते हुए अपने आधिकारिक वीचैट अकाउंट पर सूचना जारी की है। अलीबाबा ने कहा- "क्यूवेन 2.5-मैक्स ने जीपीटी-4ओ, डीपसीक-वी3 और लामा-3.1-405 बी से बेहतर प्रदर्शन किया है।" डीपसीक-आर 1 एआई मॉडल 20 जनवरी को रिलीज हुआ था और आने के साथ ही उसने अमेरिका की सिलिकॉन वैली को झटका दे दिया है। डीपसीक और अलीबाबा एआई की कम लागत ने निवेशकों को अब अमेरिका की बड़ी एआई कंपनियों में किए गये भारी खर्च पर सवाल उठाने को मजबूर कर दिया है।

डीपसीक के वी3 मॉडल से पहले डीपसीक-वी2 मई में आया था। उसके बाद से ही चीन में एआई मॉडल के लागत को लेकर मूल्य युद्ध (प्राइस वॉर) शुरू हो गया था। लेकिन तब उन खबरों और डीपसीक को कोई तवज्जो नहीं मिली। यह हकीकत है कि डीपसीक-वी2 ओपन-सोर्स था और जरूरत से ज्यादा सस्ता था। इसके बाद चीनी कंपनियों ने अपने एआई मॉडल के रेट घटा दिये। इसमें चीन सर्च इंजन कंपनी बैदू भी शामिल है।

डीपसीक के संस्थापक लियांग वेनफेंग ने जुलाई में एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारे स्टार्टअप को प्राइस वॉर की "परवाह नहीं थी।" हमारा मुख्य लक्ष्य एजीआई (कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता) प्राप्त करना है। एजीआई का मतलब यह है कि यह एआई सिस्टम अधिकांश आर्थिक रूप से महंगे कामों में मनुष्य से आगे निकल जाता है।

यह बताना जरूरी है कि अलीबाबा जैसी बड़ी चीनी तकनीकी कंपनी में सैकड़ों हजारों कर्मचारी हैं। जबकि डीपसीक एक रिसर्च लैब है। इसमें मुख्य रूप से शीर्ष चीनी विश्वविद्यालयों के युवा स्नातक और डॉक्टरेट छात्र कार्यरत हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अलीबाबा जैसी बड़ी कंपनियों का खर्च ज्यादा है। ऐसे में वे किस तरह सस्ता एआई मॉडल बेच सकते हैं। जबकि डीपसीक महज स्टॉर्टअप है और रिसर्च लैब की तरह काम कर रहा है। देखना है कि चीन में बड़ी कंपनियां किस तरह इससे मुकाबला कर सकती हैं।

समय नहीं गुणवत्ता जरूरी

जबरन अधिक काम कराना मानसिक व शारीरिक शोषण, देश में श्रम कानून को सख्ती से लागू करना जरूरी

श्रम घंटों पर सरकारी व निजी संस्थानों में एकरूपता के प्रयास हो

राकेश गांधी स्वतंत्र पत्रकार

'मुझे खेद है कि मैं आप लोगों से रविवार को काम नहीं करा सकता। आप घर बैठकर क्या करेंगे? आप अपनी पत्नी को कितनी देर तक निहार सकते हैं और आपकी पत्नी कितनी देर तक आपको देख सकती है।' एलएंडटी के चेयरमैन एसएन सुब्रमण्यन के इन शब्दों ने 90 घंटे के कार्य सप्ताह को लागू करने के बयान ने पूरे देश में आक्रोश फैला दिया सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट पड़ा, जिससे देश में शोषणकारी काम के घंटों के महिमामंडन को लेकर चल रही चर्चा तेज हो गई।

एल एंड टी के चेयरमैन एस.एन. सुब्रह्मण्यन की कर्मचारियों को सप्ताह में 90 घंटे काम करने और रविवार को भी कार्यालय आने की सलाह को देश भर में विभिन्न वर्गों के लोगों ने लगभग नकार ही दिया है। पिछले दिनों दिया गया ये बयान सही मायनों में कर्मचारियों के शोषण को प्रेरित करता है। वे यदि काम के घंटे बढ़ाने के बजाए काम की गुणवत्ता बढ़ाने की बात करते तो जरूर इस पर स्वस्थ व बेहतर चर्चाएं होती।

सुब्रह्मण्यन का यह बयान एक ऐसे दौर में आया है, जब भारत और अन्य देशों में कार्यकुशलता, उत्पादकता और श्रम की समर्पण की भावना पर काफी चर्चा हो रही है। उन्होंने चीन और अमेरिका के कामकाजी घंटे का उदाहरण देते हुए कहा था कि चीन जल्द ही अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है, क्योंकि चीनी कर्मचारी 90 घंटे काम करते हैं, जबकि अमेरिकी केवल 50 घंटे। हालांकि कंपनी की एचआर प्रमुख सोनिका मुरलीधरन ने बाद में कहा कि चेयरमैन ने बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में ये टिप्पणी की थी और उनका उद्देश्य किसी सख्त कार्य संस्कृति को बढ़ावा देना कतई नहीं था। उनका यह बयान संभवतः कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को मजबूत करने के संदर्भ में रहा होगा। वह यह समझते होंगे कि कार्यकुशलता और उत्पादन को बढ़ाने के लिए कर्मचारियों को अधिक घंटे समर्पित

करने की आवश्यकता है। विशेष रूप से, एक वैश्विक और तेजी से बदलती बाजार परिस्थितियों में, कंपनियों को अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता महसूस हो सकती है। एल एंड टी जैसे बड़े कॉर्पोरेशनों के लिए विकास और विस्तार के लिए उच्च स्तर की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है।

सुब्रह्मण्यन का बयान यह दर्शा सकता है कि वह अपने कर्मचारियों से अधिक समय और प्रयास की उम्मीद करते हैं, ताकि कंपनी और भी विस्तार कर सके, खासकर परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए। वैसे भारतीय संस्कृति में, काम के प्रति समर्पण और कड़ी मेहनत को महत्वपूर्ण माना जाता है। कई भारतीय उद्योगपतियों के लिए, लंबे कार्य घंटे काम के प्रति समर्पण और एक मजबूत कार्य नैतिकता को दर्शाते हैं। यह बयान भारतीय पेशेवरों से अधिक अपेक्षाओं को स्पष्ट करता है, जो एक व्यापक सांस्कृतिक दृष्टिकोण का हिस्सा हो सकता है।

विश्व भर में कई कंपनियों में कर्मचारियों से अधिक काम की उम्मीद की जाती है, खासकर उच्च-स्तरीय और विशेषज्ञ कार्यों में। सुब्रह्मण्यन ने शायद इस विचार को आगे बढ़ाया कि समय के साथ अधिक कार्य करने की जरूरत हो सकती है, विशेष रूप से तब जब कंपनी तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो। एल एंड टी जैसी कंपनियों के लिए बड़े निर्माण या इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए समय-संवेदनशील होते हैं, जिसमें प्रत्येक कर्मचारी का योगदान महत्वपूर्ण होता है।

ऐसे में कभी-कभी उच्च घंटे की आवश्यकता होती है। वे भले ही अपनी कंपनी के आगे बढ़ाने के लिए ऐसा कह गए, लेकिन उनके इस बयान ने विवाद को जन्म दिया है, क्योंकि ऐसे बयान से पहले उन्हें ये सोचना चाहिए था कि लंबे कार्य घंटे तक कार्य मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं, और इससे कर्मचारियों के कार्य-जीवन संतुलन में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

कई विशेषज्ञ और श्रमिक संगठन इसे अस्वस्थ और अव्यावसायिक मानते हैं, जिससे समाज में इसके खिलाफ राय बनती है। हां, उन्हें ऐसे बयान देने से पहले इतना उतावला नहीं होना चाहिए था, बल्कि उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिए था कि काम के घंटे को गुणवत्तापूर्ण कैसे बनाया जाए।

दूसरे कुछ बड़े उद्योगपतियों ने भी कार्य की गुणवत्ता पर ज्यादा देने की बात कही है। एक चेयरमैन होने के नाते उनमें इतना तो अनुभव होगा ही कि कम समय में अधिक गुणवत्ता का काम कैसा किया जा सकता है। उन्हें इतना भी पता होगा कि प्रत्येक व्यक्ति की काम करने की समझ व शक्ति अलग- अलग होती है। हां, यदि किसी कर्मचारी विशेष से उसकी शारीरिक व मानसिक क्षमता के अनुरूप उसके कार्य घंटे व उसी अनुरूप वेतन-भत्ते को लेकर आपसी सहमति हो तो ये अलग बात हो सकती है, लेकिन सामूहिक तौर पर ऐसा स्वीकार्य नहीं होगा। इसके अलावा सरकार को चाहिए कि श्रम कानून के जरिए सरकारी व निजी संस्थानों में श्रम के घंटों में एकरूपता रखी जाए।

भारत में औसतन कर्मचारी प्रति सप्ताह 46.7 घंटे काम करते हैं, और लगभग 51% कर्मचारी प्रति सप्ताह 9 घंटे या उससे अधिक कार्य करते हैं। भारत में अधिकतर श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं और यहां श्रम कानूनों का क्रियान्वयन भी कमजोर माना जा सकता है। यदि सरकार निजी क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों का सर्वे करवाए तो उन्हें पता चलेगा कि वहां सुब्रह्मण्यन के कल्पना से भी अधिक समय तक कर्मचारी काम करते हैं। कुछ संस्थानों में तो साप्ताहिक अवकाश तक नहीं मिलता होगा। ये ही नहीं, पहले की तरह अवकाश पर काम करने के ऐवज में अतिरिक्त भुगतान तक नहीं मिलता। एक तरह से ऐसे कर्मचारी न केवल शोषण के शिकार हैं, बल्कि वे शारीरिक व मानसिक तौर पर भी बीमार पाए जा सकते हैं। यदि दुनिया भर में नजर दौड़ाएं तो चीन के बाद भूटान के लोग औसतन साप्ताहिक 54 घंटे काम करते हैं। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात में 50.9 घंटे, लेसोथो में 50.4 घंटे, कांगो में लोग सप्ताह में 48.6 घंटे काम करते हैं। कई विकासशील देशों में लोग अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अधिक घंटे काम करते हैं। कुछ देशों में श्रम कानून इतने सख्त नहीं होते, जिससे नियोक्ता कर्मचारियों से अधिक घंटे काम करवाते हैं। कुछ संस्कृतियों में अधिक काम करना समर्पण और मेहनत का प्रतीक माना जाता है। कई देशों में अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों की संख्या अधिक होती है, जहां कार्य घंटे नियमित नहीं होते और अक्सर अधिक होते हैं।

सप्ताह में 40-45 घंटे कार्य करना सामान्य

मानसिक संतुलन और समग्र भलाई के लिए सप्ताह में 40 से 45 घंटे काम करने का आदर्श समय माना गया है। हालांकि ये व्यक्तिगत आवश्यकता, कार्य की प्रकृति और जीवन के अन्य पहलुओं पर निर्भर करता है। यह समय आमतौर पर 5 दिन के कार्य सप्ताह के लिए उपयुक्त होता है, जिसमें एक दिन का पर्याप्त आराम और व्यक्तिगत समय मिल पाता है। अन्यथा अधिक काम से मानसिक थकान हो सकती है, जिससे तनाव, चिंता, हृदय रोग, और अवसाद जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। सप्ताह में कम से कम 1-2 दिन का आराम अत्यंत आवश्यक है, जिसमें कर्मचारी अपनी पसंदीदा गतिविधियों में समय बिता सकें और परिवार या दोस्तों के साथ समय व्यतीत कर सकें। इसके अलावा भी दिन में कार्य के दौरान छोटे-छोटे ब्रेक लेने से मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। लगातार अत्यधिक काम करने से ध्यान की कमी, थकावट और तनाव हो सकता है। प्रतिदिन हल्का व्यायाम, ध्यान, या योग मानसिक ताजगी बनाए रखने में सहायक होते हैं। ऐसे में सप्ताह में 40-45 घंटे तक काम के साथ ही यदि व्यक्ति अन्य गतिविधियों, परिवार और विश्राम के लिए समय निकालता है, तो मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है।

सुब्रह्मण्यन के बयान के बाद प्रतिक्रियाएं

महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने इस बयान पर मजे लेते हुए कहा था, "मेरी पत्नी अद्भुत हैं, मुझे उन्हें निहारना पसंद है," और यह भी जोड़ा कि बहस काम के घंटों की संख्या पर नहीं, बल्कि काम की गुणवत्ता पर होनी चाहिए।

बजाज ऑटो के प्रबंध निदेशक राजीव बजाज ने भी ये ही कहा, "भारतीय कंपनियों को लंबे कार्य घंटों की पुरानी नीतियों से हटकर काम की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।"

आरपीजी समूह के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने कहा, "90 घंटे प्रति सप्ताह? क्यों न रविवार का नाम बदलकर 'सन-ड्यूटी' कर दें और 'डे ऑफ' को एक मिथक बना दें!"

प्रसिद्ध सिने अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने सुब्रह्मण्यन के बयान की आलोचना करते हुए इसे "चौंकाने वाला" बताया और कहा, "मेंटल हेल्थ मायने रखता है।"

शिवसेना (यूबीटी) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस बयान को "महिला विरोधी" और "भारत के नए युग के गुलाम बनाने वालों" जैसा करार दिया।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बयान पर व्यंग्य करते कहा, "कुछ बकाया बाकी है," और इसे श्रमिकों के अधिकारों के खिलाफ बताया।

इन्फोसिस के सह-संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति ने सुब्रह्मण्यन के बयान पर पहले लगभग सहमति पूर्ण टिप्पणी के बाद सफाई देते हुए कहा कि उनका मकसद किसी पर दबाव डालना नहीं था, बल्कि उनका कहना है कि हर व्यक्ति को अपनी स्थिति और जरूरतों के हिसाब से फैसला लेना चाहिए। उन्होंने खुद का उदाहरण देते हुए बताया कि उन्होंने इन्फोसिस में 40 साल तक हफ्ते में 70 घंटे से ज्यादा काम किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई ऐसा ही करे।

पौराणिक शास्त्र में भी समय के विवेकपूर्ण उपयोग पर जोर

आधुनिक काल में तो छोड़िए, भारतीय पौराणिक शास्त्र के अनुसार हमारे अतीत में भी कभी जीवन में कार्य करने के घंटों की स्पष्ट सीमा तय नहीं हुई। बल्कि हमेशा से संतुलित जीवन, कर्तव्य और आत्म-उन्नति के लिए समय के विवेकपूर्ण उपयोग पर जोर दिया जाता रहा है। इतना अधिक कार्य करने को भी अनुचित माना गया है, जिससे स्वास्थ्य और आत्म-कल्याण प्रभावित हो। गीता के अध्याय 6, श्लोक 16-17 में स्पष्ट लिखा है :

'नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः।
न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन।।

(अर्थातः योगी को न अधिक खाने वाला होना चाहिए, न ही अधिक उपवास करने वाला। न अधिक सोने वाला, न ही जागने वाला। जीवन में संतुलन ही योग है।)

- मनुस्मृति में जीवन को चार आश्रमों में विभाजित किया गया है—ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, और संन्यास। गृहस्थ आश्रम में कार्य (अर्थ और काम) को प्रमुखता दी गई है, लेकिन उसमें धर्म और कर्तव्य का पालन भी आवश्यक माना गया है।
- आयुर्वेदिक ग्रंथों में दिनचर्या और जीवनशैली पर चर्चा की गई है। इसमें व्यक्ति के लिए कार्य और विश्राम का समय संतुलित रखने की सलाह दी गई है।

मशीनरी युग में काम के घंटे क्यों गिनने

मशीनरी युग में अब काम के घंटे नहीं, गुणवत्ता पर ध्यान देना जरूरी है। जिन्होंने 90 घंटे का बयान दिया है वे साफ्टवेयर ट्रेड के हैं और उनकी अपनी दिक्कतें रही होंगी। और वैसे भी आज के जमाने में हर इंसान काम के साथ- साथ बेहतर जीवन जीना चाहता है। ऐसे में 90- 100 घंटे काम की बातें करना बेमानी है। वैसे मैं बता दूं कि कोई 20-25 साल पहले तक हैण्डीक्राफ्ट व्यवसाय में कर्मचारी अविश्वसनीय तरीके से घंटों काम करते थे और समय की परवाह कहां होती थी। उन्हीं की बदौलत आज ये व्यवसाय इतनी ऊंचाइयों पर है। आज मशीनरी युग है और हमें भी उसी अनुरूप बजाए घंटे गिनने के बेहतर काम की तरफ ध्यान देना होगा, ताकि कर्मचारियों को अपने लिए भी समय मिल सके।

-हंसराज बाहेती, सीओए मेम्बर ईपीसीएच व चेयरमैन उम्मेद क्लब

विकसित होना है तो काम करने में क्या बुराई

जब तक आप पूरी तरह विकसित नहीं हो जाते या अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते तो काम करने में क्या बुराई है? एल एण्ड टी के चेयरमैन के बयान को सकारात्मकता से लेने की जरूरत है। हम भी अपने युवा काल में काम सीखने जब इंडस्ट्रीज में आए थे तो सवेरे जल्दी ही काम पर पहुंच जाया करते थे। देश को विकसित देशों की श्रृंखला में खड़ा करना है तो काम के घंटे पर क्यों विचार करना? खूब काम पर ध्यान देना चाहिए। जब आप अपना व संस्थान का विकास कर लेते हैं तो फिर परिवार व खुद के लिए समय निकालना ज्यादा आसान हो जाता है। जब विकास करना है तो काम की समय सीमा नहीं देखनी चाहिए। हालांकि कोई भी संस्थान क्यों न हो, जबरन कोई काम नहीं करवाता। हर मालिक-कर्मचारी अपने परिवार के लिए ही अधिक काम करके आगे बढ़ना चाहता है। इसी में सभी का विकास भी है।

-अशोक संचेती, उद्यमी

कर्मचारी क्या कोल्हू का बैल है?

कर्मचारी को कोल्हू का बैल मत समझिए। संस्थान को कर्मचारी के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। सुब्रह्मण्यन का सप्ताह में 90 घंटे काम करने का बयान बेतुका है। हम जहां बैंक कर्मियों से पांच दिन के सप्ताह में अधिकतम 45 घंटे काम कराने की मांग कर रहे हैं, ये कर्मचारियों से दुगुना काम करवाने की फिराक में हैं और रविवार को भी घर का नहीं छोड़ने वाले। ये सिस्टम बिल्कुल गलत है। जहां तक बैंक कर्मियों का सवाल है, जिम्मेदार अधिकारी अभी भी क्षमता से अधिक काम कर रहे हैं और कम कर्मचारियों की संख्या के चलते काम के दबाव में अवसाद ग्रस्त हो रहे हैं। बैंकिंग संस्थान को तत्काल इस ओर ध्यान देना चाहिए, ताकि इन जिम्मेदार अधिकारियों को इतना समय तो मिले कि वे अपना व परिवार का ख्याल कर सकें।

- भवानी सिंह सोलंकी
उपाध्यक्ष- एसबीआईएसए, राजस्थान, जयपुर सर्किल

आजादी के 75 साल बाद भी काम का कल्चर नहीं बदला

देश को आजाद हुए सात दशक से अधिक समय हो गया है, लेकिन काम का कल्चर आज भी वहीं है। आज भी कमजोर सिस्टम के चलते रेलवे कर्मचारी 10 से 15 घंटे लगातार काम करते हैं। ये मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के लिहाज से बिल्कुल उचित नहीं है। काम की दृष्टि से कर्मचारी भी कम हैं, जिससे भी काम का भार अधिक रहता है। किसी भी कर्मचारी से लगातार 8 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाना चाहिए। हमारे रेलवे ट्रेक की देखरेख करने वाले कर्मचारियों व लोको पायलट की स्थिति इस मामले ज्यादा गंभीर हैं, जो क्षमता से अधिक समय तक लगातार काम करते हैं। इस वर्क कल्चर को तत्काल सही किया जाना जरूरी है।

- मनोज कुमार परिहार, मंडल सचिव, नार्थ-वेस्ट रेलवे एम्पलाइज यूनियन

कविता का सच

दिनेश सिंदल
कवि, लेखक

मेरा मानना है कि कविता का पहला अक्षर कवि लिखता है और उसका आखरी अक्षर कोई अदृश्य हाथ लिख रहा होता है। यह वह स्थिति है जब कवि और कविता एक हो जाते हैं। इस समय कवि अपनी चेतना और अपनी अतिचेतना के आगे समूह चेतना (कलेक्टिव कॉन्शसनेस) में विचरण कर रहा होता है। यहां उसका 'मैं' शेष नहीं रहता। वह 'हम' हो जाता है। कवि खो जाता है। उसे अपने होने का बोध भी नहीं रहता। इसे यूं कहूं कि कवि और कविता एक हो जाते हैं।

हमारे बहुत से शब्द हमारी कलेक्टिव कॉन्शसनेस से आए हैं। अतः उच्चारण की थोड़ी बहुत भिन्नता के साथ वे सभी संस्कृतियों में मिल जाएंगे। सभी भाषाओं में उन्हें देखा जा सकता है। हमारी बहुत सी कलाएं भी हमारी कलेक्टिव कॉन्शसनेस से आई है। जैसे चित्रकला। जैसे नृत्य। जैसे संगीत।

हमें पिकासो के चित्रों को समझने के लिए जर्मन जानना आवश्यक नहीं है। इसी तरह कोई भारतीय नर्तक अगर नृत्य कर रहा है तो पश्चिम का व्यक्ति भी उसे देख कर आनंदित होगा। उसे भारतीय भाषा जानने की आवश्यकता नहीं है। संगीत भी सभी को एक सा आनंद देता है।

जैसा की मैंने कहा कविता भी एक कला है। ये मुख्य रूप से भावों का खेल है। भावों से बनी कविता हृदय को संबोधित होती है। कविता के पास हम विचारों के लिए नहीं जाते। विचार तो दूसरी जगहों पर ज्यादा प्रभावशाली, ज्यादा स्पष्ट, ज्यादा तेज तर्रार तरीकों से मिल जाएंगे। कविता और कला में भाव ही प्रधान होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो सारे विचारक कवि हो जाते। भाव व्यक्ति के आंतरिक जीवन को या व्यक्तियों के परस्पर संबंधों को उद्घाटित करते हैं।

एक सामान्य मनुष्य अपने जगत को ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जानता है। किसी वस्तु के संपर्क में आने पर उसकी ज्ञानेंद्रियां प्रतिक्रिया व्यक्त करती हैं। संवेदित होती हैं और यह संवेदना उसे उद्वेलित करती है। जिससे वस्तु के प्रति उसके मन में एक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। या कहें कि भाव उत्पन्न होता है। यानी कि भाव इस भौतिक जगत के प्रति व्यक्ति की सबसे पहली प्रामाणिक प्रतिक्रिया है। जिसका कोई आकार नहीं होता। जिसका कोई रूप नहीं होता। कवि भाव की इस आरंभिक अवस्था को जानता है।

कविता में शब्द जब अपने भाषाई सिंहासन से उतरकर काव्य संवेदना का निर्माण करता है, तब वह सभी श्रोताओं को एक सा आनंद देता है। सभी पर एक सी रस- वर्षा करता है। वह ऊंच- नीच, क्रेता- विक्रेता, अमीर- गरीब, हिंदू- मुस्लिम में भेद नहीं करता। शब्द यहां पर तिरोहित हो जाता है। बस एक भाव बचा रहता है और श्रोता उस भाव के साथ बहने लगते हैं। कविता विचार का नहीं, भाव का संप्रेषण है। और रूपांतरण विचार की नहीं भाव की छलांग है।

कविता मनुष्य- मनुष्य के बीच खड़ी की गई इन दीवारों को गिरा कर मनुष्य को मनुष्य की तरह देखने का आग्रह करती है। वह मनुष्य को मनुष्य के करीब लाती है। जोड़ने का काम करती है। अतः कविता बाजार के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। वह राजनीति के रस्ते का रोड़ा बन जाती है। बाजार का लाभ इसी में है कि समाज में आर्थिक असमानता रहे, वर्ग भेद रहे। यही राजनीति के हित में भी है। आदमी जितना बंटा रहेगा, उस पर शासन करना उतना ही आसान रहेगा। अतः बाजार कविता पर अपना शिकंजा कसता है। वह उसके लिए प्रतिकूल वातावरण पैदा करता है।

यहां कविता विभिन्न विचारधाराओं के शिकंजे में कसती चली जाती है। एक कवि के लिए विचारधारा से बड़ा दर्शन होता है। और दर्शन से भी बड़ी उसकी जीवन दृष्टि, जो हर कवि को पैदा करनी पड़ती है। कविता के लिए विचारधारा और दर्शन बाह्य उपकरण है। अच्छी कविता सभी विचारधाराओं का अतिक्रमण करती है। जनवाद, पूंजीवाद, गांधीवाद, धर्म, जाति या नस्ल, वह किसी को नहीं मानती। वह सीधे जीवन से जुड़ती है। जीवन महत्वपूर्ण है, इसे नियंत्रित करने वाले नियम नहीं।

राजनीति कविता को विभिन्न विमर्शों के माध्यम से देखने का चश्मा देती है। स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श इत्यादि। यहां फिर मैं एक बात स्पष्ट कहूंगा की जीवन महत्वपूर्ण है। कवि कभी भी बांटने के पक्ष में नहीं रहेगा। वह हिंसा, नफरत या द्वेष का समर्थक नहीं होता।

मैं गजल का विद्यार्थी हूं। गजल का एक अर्थ एक यह भी बताया गया है कि गजल शब्द गज़ाला से बना है। गज़ाला का अर्थ है हिरण का बच्चा। हिरण के जब तीर लगता है और उसे निकालते समय उसकी जो कराह निकलती है वह गजल है। यानि कि कविता करुणा से पैदा हुई। कविता प्रेम से पैदा हुई। कविता हिंसा या नफरत का समर्थन नहीं करती है। कविता बहेलिए के पक्ष में खड़ी नहीं होती। वह उस क्रौंच पक्षी की पीड़ा को स्वर देती है, जिसको तीर लगा है और जिसका साथी अपने प्रेमी के लिए तड़प रहा है।

राजनीति कवि को सरकारी पुरस्कारों, अकादमियों के पदों का लालच दिखाती है। और उसे कविता के सिंहासन से नीचे उतारने का काम करती है। यहां कविता के लिए भटकाव की स्थिति बनती है। पर ये तात्कालिक प्रभाव है। सत्य स्थगित हो सकता है, खत्म नहीं। कुछ समय के लिए उस अंगारे पर राख की परत जम सकती है। किंतु, फिर कभी कोई कबीर आता है। इस धूनी में फूंक मारता है। कविता के अंगारे पर आई तात्कालिकता की राख उड़ती है और ये अंगारा भभक उठता है।

कविता मनुष्य- मनुष्य के बीच खड़ी की गई इन दीवारों को गिरा कर मनुष्य को मनुष्य की तरह देखने का आग्रह करती है। वह मनुष्य को मनुष्य के करीब लाती है। जोड़ने का काम करती है। अतः कविता बाजार के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। वह राजनीति के रस्ते का रोड़ा बन जाती है। बाजार का लाभ इसी में है कि समाज में आर्थिक असमानता रहे, वर्ग भेद रहे। यही राजनीति के हित में भी है।

पंछी के उड़ जाने में..

मैं क्या जानूं क्या रिश्ता है पिंजरे में औ' दाने में
मैंने साथ दिया है अक्सर पंछी के उड़ जाने में

कोयल के गीतों में या फिर फूलों के मुस्काने में
पकड़ा जाता हूं मैं अक्सर तेरा राज छिपाने में

जीवन भर मैं दूर रहा हूं ये खोने वो पाने में
मेरा सारा जीवन बीता फूलों- सा मुस्काने में

बात बिगड़ने में तो यारों पल भर लगता है, लेकिन
बरसों लग जाते हैं हमको बिगड़ी बात बनाने में

वो बाहर बाहर जलता है औ' मैं भीतर जलता हूं
तू बतला अब भेद रहा क्या मुझमें औ' परवाने में

कोई मेरे भीतर था जो दुनिया से लड़ लेता था
मैंने कितना कुछ खोया है इक बस तुमको पाने में

याद दिलाई बचपन की नादानी तो वो रूठ गया
उम्र लगेगी अब उस नादां को मुझको समझाने में

मेरे भीतर भी एक कबिरा बैठा कुछ- कुछ बुनता है
पर क्या जानू क्या बुनता वो अपने ताने- बाने में

पहले मुझको वो मारेगा सिंदल रिश्ते में अपने
फिर मुझको जिंदा कर देगा वो अपने अफसाने में

ध्यान में मेरे तू उतरा..

पोथी दुनिया भर की पढ़ ली, ज्ञान में मेरे तू उतरा
मंदिर में भी, मस्जिद में भी, ध्यान में मेरे तू उतरा

जब रेतीले धोरे सबके सब हरियल हो जाएंगे
तब मानूंगा सूखे रेगिस्तान में मेरे तू उतरा

मैंने तो रोटी ढूंढी थी छैनी और हथौड़े से
दुनिया ने मूरत पाई, पाषाण में मेरे तू उतरा

मेरा हर इक शब्द प्रार्थना बनकर होठों से निकला
मैंने तो खुद को गाया था गान में मेरे तू उतरा

सोने की चिड़िया था भारत, विश्व गुरु कहलाता था
वो भी क्या दिन थे जब हिंदुस्तान में मेरे तू उतरा

मौसम से तो हमने अक्सर धोखे ही खाए सिंदल
तब- तब फूल खिले, जब- जब उद्यान में मेरे तू उतरा

शब्द-शब्द दरपण
शीन काफ़ निज़ाम

डॉ. इश्राक़ुल इस्लाम माहिर

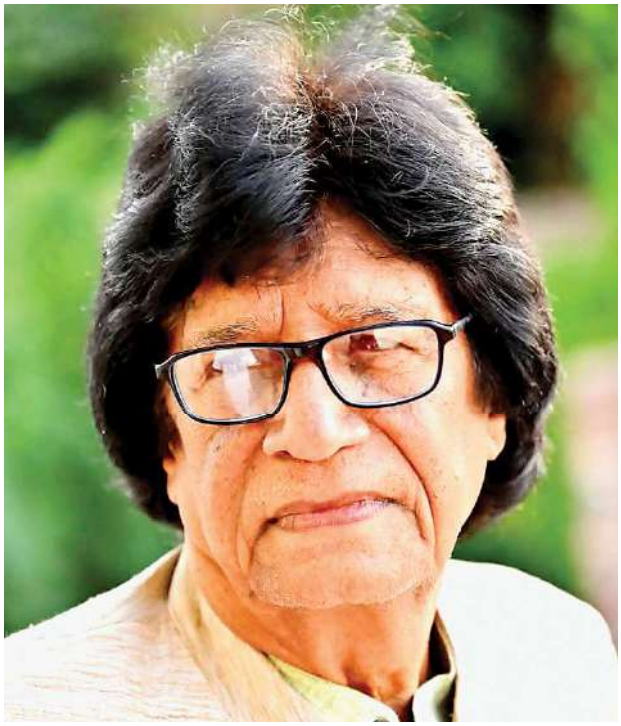

इकलौती संतान और मेधावी छात्र रहे शीन काफ़ निज़ाम इंजिनीयरिंग की पढ़ाई छोड़ कर साहित्यिक सफ़र की शुरूआत ही से 'ट्रेंडसेटर' रहे हैं, उनकी अध्ययन प्रवृत्ति की वज्ह से जोधपुर में ऐसी किताबें पढ़ने सुनने में आने लगीं जिनसे जोधपुर का साहित्य जगत अनभिज्ञ था। फिर जब उनकी शाइरी,काव्य दृष्टि और साहित्यिक चिंतन देश की साहित्यिक राजधानियों में अपना असर दिखाने लगी तो जोधपुर में ऐसे साहित्यिकारों का आना शुरू हुआ जिनके बारे में शायद ही कोई नगरवासी जानता हो, इस की एक मिसाल ये है कि जब उर्दू के नामवर नाक़िद मुहम्मद हसन स्करी का निधन हुआ तो निज़ाम शहर में ऐसे एक शख़्स को ढूंढते रह गये जो मुहम्मद हसन अस्करी को जानता हो।

उसी प्रकार निज़ाम की प्रतिभा,स्वभाव और प्रसिद्धि की वज्ह से अन्य ललित कलाओं के जो भी नेशनल लेवल के कलाकार जोधपुर आते रहे वह भी निज़ाम से अपने निकट संबंधों की चर्चा या मिलने की इच्छा को सार्वजनिक तौर पर प्रकट करते रहे।

पिछले दो-ढाई दशकों में जोधपुर शहर में शीन काफ़ निज़ाम ही के कारण ऐसे पुरस्कार या सम्मान आने लगे जिन में से कई के नाम पहली बार सुने। 'इकबाल सम्मान' 'भाषा-भारती सम्मान' आदि के अलावा और भी कई सम्मान इस श्रेणी में आते हैं।

उनका कृतित्व हो या व्यक्तिव दोनों ही एक त्रिवेणी से जुड़े हैं यानी उनका अध्ययन, चिंतन और सर्जन आपस में गुंधा हुआ है, अध्ययन के साथ चिंतन चलता रहता है और चिंतन के साथ सर्जन होता रहता है। उनकी शाइरी में भाषाई अनुशासन, अद्वितीय मनःस्थितियां और मौलिक चिंतन है इसीलिये उनकी ग़ज़लें ग़ज़ल की पारंपरिक परिभाषा से अलग परिभाषा गढ़ती नज़र आती हैं तो नज़्में भाषा को तोड़ते हुए अछूती भाषा घड़ती हैं, और अगर समग्रता में देखा जाये तो उनका कलाम प्राचीन भारतीय मूल्यों का नया आईना है, शाइरी के साथ-साथ यही त्रिवेणी उनकी आलोचना में

प्रशंसकों एवं हितैषियों के अनुसार निज़ाम को पद्मश्री कम से कम दस बरस देर से मिला है फिर भी पद्मश्री मिलने की खुशी इसलिये बड़ी है कि ***जोधपुर के इतिहास में शीन काफ़ निज़ाम जोधपुर शहर में किसी भी भाषा के पहले लेखक हैं जिनको पद्मश्री पेश किया जा रहा है।***

नज़र आती है, वह हमेशा किसी भी साहित्यिक रचना के कलात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर नज़र डालते हैं, यही बात उनके व्यक्तित्व में भी पाई जाती है उनके आस-पास ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके बारे में वह बहुत कुछ नकारात्मक जानते हैं फिर भी उनसे मिलते वक़्त उन पर उन चीजों को ज़रा भी ज़ाहिर नहीं होने देते बल्कि सामने वाले के गुणों और संभावनाओं को उजागर करके उसको आत्म-साक्षात्कार का अवसर देते हैं और हर नव परिचित या नवागांतुक की उपस्थिति को भी सादर दर्ज करते हैं।

जोधपुर में उनके शागिर्दों की बड़ी तादाद जगज़ाहिर है लेकिन जोधपुर के बाहर भी कई नामचीन, समकालीन और उम्र में बड़े शाइर भी निज़ाम से अपनी रचनाओं पर इस्लाह (काव्य परामर्श) लेते रहे हैं, मौजूदा दौर में गुलज़ार सामने की मिसाल है जो सार्वजनिक कार्यक्रम में इस बात को अलग अलग शहरों में दोहरा चुके हैं। इसी तरह निदा फ़ाज़ली की हर ग़ज़ल या नज़्म के पहले श्रोता निज़ाम होते थे।

शाइरी और आलोचना की 12 किताबें लिखने, लगभग 12 मुल्कों की यात्रा और 12 से अधिक पुरस्कार या सम्मान प्राप्ति के बाद भी उनके स्वभाव की सहजता और विनम्रता वही है जो पहली मुलाकात के वक़्त होती है।

प्रशंसकों एवं हितैषियों के अनुसार निज़ाम को पद्मश्री कम से कम दस बरस देर से मिला है फिर भी पद्मश्री मिलने की खुशी इसलिये बड़ी है कि जोधपुर के इतिहास में शीन काफ़ निज़ाम जोधपुर शहर में किसी भी भाषा के पहले लेखक हैं जिनको पद्मश्री पेश किया जा रहा है। 'पहले' के ताल्लुक़ से दो और पुरस्कार याद आ गये जो कि सबसे पहले शीन काफ़ निज़ाम को पेश किये गये, एक तो मेहरानगढ़ ट्रस्ट, जोधपुर का 'मारवाड़ रत्न सम्मान' दूसरा राजस्थान उर्दू अकादमी, जयपुर का 'महमूद शीरानी अवार्ड'। जोधपुर के 500 साल से अधिक के इतिहास में इतने लब्ध प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले वे एक मात्र लेखक हैं।

अभी पिछले दिनों पाकिस्तान में 'चहारसू' और भारत में 'आलमी ज़बान' नामी अदबी रिसालों ने निज़ाम पर विशेषांक निकाले जो बताते हैं कि उनकी मक़बूलियत सरहदों के पार भी है, शायद इसीलिये पिछले वर्ष खाड़ी देश क़तर में निज़ाम को 'लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड' भी पेश किया गया।

शाइरी में किसी को उस्ताद ना रखने वाले शीन काफ़ निज़ाम 'अज्ञेय' 'फ़िराक़ गोरखपुरी', 'मौलाना माहिरुल क़ादरी','वज़ीर आग़ा', 'वारिस अल्वी' और 'कालिदास गुप्ता रिज़ा' वग़ैरह की हौसला अफ़ज़ाई को अपनी ख़ुश क़िस्मती समझते हैं। निज़ाम की उर्दू के अलावा अन्य भाषाओं के साहित्य पर गहरी समझ ही का नतीजा है कि राजस्थानी के विजयदान देथा 'बिज्जी', हिंदी के नंदकिशोर आचार्य तो उर्दू के कालिदास गुप्ता रिज़ा, मख़्मूर सईदी और जयंत परमार सरीखे साहित्यिकारों ने अपनी किताबें उन को समर्पित की हैं।

पद्मश्री का समाचार अगर पच्चीस दिन पहले आ जाता तो असीम धैर्य वाली उस आत्मा को दिली ख़ुशी होती जिसने शीन काफ़ निज़ाम के संघर्ष को साथ साथ जिया है। अपने दुख को अपनी निजी जायदाद मानने वाले निज़ाम शोक के बावजूद हर बधाई देने वाले से 'अशोक' की तरह मिल कर सब के प्रेम और भावनाओं का सम्मान कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तित्व के लिये पद्मश्री आख़िरी पड़ाव नहीं हो सकता।

आख़िर में शाइर 'खुश्तर मकरान्वी' के दोहे पर अपनी बात को रोकता हूं..

वो शब्दों का देवता जीवन जोत `निज़ाम'
ज़िन्दा सुन्दर रास्ते रखवता हर हर गाम

ग्रहों की चाल

ज्योतिषी : विपुल दोभाल
ईमेल : vipravaani@gmail.com
मोबाइल : 9928424374

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना कार्य क्षेत्र में लाभ देने वाला है। साथ ही साथ व्यापार में भी लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ खर्च भी होंगे किंतु यह शुभ कार्यों पर होंगे इसलिए आपका मन प्रसन्न रहेगा। जो लोग भूमि भवन और वाहन की खरीद का प्लान बना रहे हैं उन्हें पूर्णतया सफलता प्राप्त होगी। भाइयों के साथ विवाद की स्थिति बन सकती है और भाग्य कुछ रुक-रुक कर साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। यह समय कर्म प्रधान समय है इसलिए आप कर्म करते रहें तो फल निश्चित रूप से अच्छा प्राप्त होगा।

वृषभ राशि

आपके लिए समय थोड़ा तनावपूर्ण दिखाई दे रहा है। मान सम्मान और प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है। किसी भी कोर्ट कचहरी मुकदमे बाजी से अपना बचाव रखें। दो लोगों के झगड़े में बीच बचाव ना करें, अन्यथा आपके सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। क्रोध पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक रहेगा। प्रॉपर्टी संबंधी किसी भी विवाद को इस महीने टाल दें। आय के साधनों में गिरावट दिखाई पड़ रही है। शान शौकत और फैशन पर अपनी हैसियत से अधिक खर्च कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में स्थितियां अनुकूल दिखाई दे रही हैं। थोड़े से सर दर्द को छोड़कर बाकी शरीर स्वस्थ दिखाई दे रहा है।

मिथुन राशि

मिथुन राशि - अपने अहम और जिद के कारण कोई भारी नुकसान उठा सकते हैं। मन को नियंत्रित रखते हुए शांत रूप से जीवन यापन करना लाभप्रद रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय अच्छा नहीं है। आपको चेस्ट संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही नेत्र दोष भी रहेगा। कार्य क्षेत्र में विभिन्न बाधाएं दिखाई दे रही हैं, किंतु अंततः विजय आपको ही प्राप्त होगी क्योंकि भाग्य इस माह आपके साथ दिखाई दे रहा है। किसी शुभ कार्य पर धन खर्च होता दिख रहा है। खाद्य सामग्री, शराब रसायन और वस्त्र इत्यादि के व्यापारियों को लाभ प्राप्त होगा।

कर्क राशि

कर्क राशि - भाग्य इस माह बिल्कुल साथ देता नहीं दिखाई दे रहा है अपने कर्म के बल पर ही आप सफलता अर्जित कर पाएंगे। गुप्त शत्रु और धूर्त व्यक्तियों से अपना बचाव रखें। श्वास संबंधित रोगों की संभावना बनी रहेगी। जल दुर्घटना से भी आपको बचाव की आवश्यकता है। पति-पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद संभव है। जिन लोगों के तलाक संबंधी कैसे चल रहे हैं उनमें तेजी आएगी। सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत छात्रों को सफलता प्राप्त होगी। भाई बहन से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। क्रोध में कोई भी निर्णय न लें, भविष्य में हानि उठानी पड़ सकती है। व्यापार और आय के साधन इस माह धीमे पड़ते नजर आ रहे हैं। नाभि और निचले हिस्सों से संबंधित रोग रह सकते हैं।

सिंह राशि

सिंह राशि - पिता के स्वास्थ्य या उनके साथ वैचारिक मतभेद की स्थिति बन सकती है। इसके अतिरिक्त कुटुंबिय तनाव या पैतृक संपत्ति को लेकर कोई चिंता बनी हुई दिखाई दे रही है। नौकरी पेशा लोग कोई भी हस्ताक्षर बहुत सोच समझकर करें अन्यथा किसी प्रकार का आक्षेप आ सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय काफी अच्छा है। पिता और संतान के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंतित अवश्य दिखाई दे रहे हैं। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं।

कन्या राशि

कन्या राशि - ज्ञान और बुद्धि बल से आप ख्याति अर्जित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। छात्रों को भी विद्या का लाभ होता दिखाई दे रहा है। सरकारी नौकरी के लिए अगर कोई परीक्षा इस बीच है तो उसमें सफलता की संभावनाएं काफी बेहतर हैं। विवाहित लोगों के लिए यह समय तनावपूर्ण रह सकता है। भाग्य बिल्कुल भी साथ देता नहीं दिखाई दे रहा है। कर्म क्षेत्र में इस महीने मेहनत करने से लाभ प्राप्त होगा। कुछ सूक्ष्म यात्राएं हो सकती हैं। स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है।

तुला राशि

तुला राशि - तुला राशि के जातकों के लिए यह समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। किंतु आय के साधनों में कमी होती हुई दिखाई दे रही है और व्यर्थ के खर्च बढ़ रहे हैं भूमि भवन और वाहन से संबंधित खरीदारी का विचार अगर आप कर रहे हैं तो उसमें सफलता प्राप्त होगी। कोर्ट कचहरी या अन्य विवादों से दूर रहें। मान सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा में ऊर्जा व्यय होती दिखाई दे रही है। किंतु संतान की ओर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे।

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए फरवरी महीना काफी राहत देता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 2 साल से जो कार्य रुके हुए थे या बढ़ाओ के साथ आगे बढ़ रहे थे उनमें लाभ प्राप्त होगा। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता बनी रह सकती है। आपका राशि स्वामी मंगल है जो कि कर्म प्रधान ग्रह है अतः कर्म करते रहें आने वाले समय में आपको निश्चित रूप से शुभ फल प्राप्त होगा।

धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक रूप से कष्ट देने वाला है। आय से कहीं ज्यादा व्यय होता दिखाई दे रही है। कार्यों में बाधा रहेगी। अगर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो इस महीने रुक जाएं। थायराइड और डायबिटीज के पेशेंट अपना ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में खटास आ सकती है। नेत्र दोष रहेगा। भाग्य भी साथ देता नहीं दिखाई दे रहा है।

मकर राशि

यह माह बहुत ही अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। आपका मन प्रसन्न रहेगा। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता प्राप्त होती दिखाई दे रही है। आय के साधनों में वृद्धि होगी। भाग्य आपका साथ देता दिखाई दे रहा है। धनागमन के योग बन रहे हैं। यह समय सुख वृद्धि कारक है। कुटुंब में भाइयों से विवाद की स्थिति से बचाव करें।

कुंभ राशि

समय अनुकूल है। आप सामाजिक, कार्मिक और अन्य स्तरों पर अपने साथ न्याय होता महसूस करेंगे कुटुंब से दूर की यात्रा संभव है। भूमि, भवन या वाहन संबंधी कोई भी नया कार्य अभी ना करें। नेत्र दोष से बचाव रखें। संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं।

मीन राशि

अत्यधिक दुविधा और वैचारिक उधेड़बुन का समय है। कोई महत्वपूर्ण निर्णय दुविधा के कारण नहीं ले पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में बेहतर होगा कि उस निर्णय को टाल दें। भाई बहनों के साथ संबंधों में खिंचाव आ सकता है। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं। आय के साधनों में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। संतान सुख योग उत्तम दिखाई दे रहा है। पत्नी के साथ संबंधों में तल्खी आ सकती है। महिलाओं के साथ व्यवहार करते हुए सतर्क रहें।

राजस्थान की सगुण भक्ति परम्परा में

एक अनमोल धरोहर

मीराँबाई

भक्तिकाल की अद्वितीय काव्य साधिका

कृष्ण भक्ति की प्रतीक और ऐतिहासिक तथ्य

बलवंत राज मेहता
वरिष्ठ पत्रकार

मीराँबाई, भारतीय भक्ति साहित्य की अमर विभूति, इतिहास, भक्ति और समाज के अनेक पहलुओं की प्रतीक हैं। राजपरिवार में जन्मी इस कवयित्री के जीवन को लेकर इतिहासकारों और विद्वानों के बीच कई मत-मतांतर हैं।मीराँ के जन्मस्थान, नाम की व्युत्पत्ति और भक्ति परंपरा जैसे विषयों पर आज भी गहन शोध की आवश्यकता है। प्रोफेसर डॉ. कल्याण सिंह शेखावत द्वारा किए गए शोध और उनकी वार्ता के आधार पर प्रस्तुत यह आलेख मीराँबाई के जीवन के पहलुओं को उजागर करने का प्रयास करता है।

मीरा बाई का मंदिर चित्तौड़गढ़

जन्म और परिवार का विवाद

मीराँबाई का जन्म विक्रमी संवत 1555 में वैशाख सुद तीज को मूल नक्षत्र में बाजोली गाँव (वर्तमान नागौर, राजस्थान) में हुआ था। उनके पिता रतन सिंह जी मेड़ता के शासक राव दूदा के चौथे पुत्र थे। राव दूदा को कुड़की और बाजोली सहित 12 गाँवों की जागीर मिली थी। मीराँ के जन्म के समय उनकी माता का देहांत हो गया, जिसका कारण मूल नक्षत्र में जन्म होना था। उनके दादा राव दूदा, मेड़ता रियासत के संस्थापक तथा विष्णु के चारभुजा नाथ के परम भक्त थे, जिन्होंने मीराँबाई को भी कृष्ण भक्ति की शिक्षा दी।

नाम और लोक धारणाएं

कुछ विद्वानों के अनुसार, मीराँबाई का नाम 'मीराँ' अरबी-फारसी भाषा से लिया गया शब्द है, जबकि अन्य इसे 'मिहिर' (सूर्य) से जोड़ते हैं। लोकधारणाओं के अनुसार, उनका नाम मूल नक्षत्र में जन्म के कारण पड़ा। मीराँबाई का जीवन और नाम, दोनों ही हिंदू भक्ति परंपरा और वैष्णव धर्म के गहरे प्रभाव को दर्शाते हैं।

मीरा बाई का मंदिर मेड़तासिटी

विवाह और वैराग्य का प्रारंभ... मीराँबाई का विवाह मेवाड़ के ज्येष्ठ राजकुमार भोजराज से हुआ, जो महाराणा सांगा के पुत्र थे। विवाह के करीब आठ वर्षों बाद ही भोजराज का निधन हो गया। उन्होंने गिरिधर गोपाल को अपना आराध्य और पति माना। इस वैराग्य ने उन्हें राजपरिवार की परंपराओं और समाज की रूढ़ियों से ऊपर उठकर एक नई पहचान दी। मीराँ बाल्यकाल से ही गिरधर नागर की उपासिका थी। भोजराज के असामयिक निधन से मीराँ सम्पूर्ण रूप से अपने उपास्य देव की साधिका बन गई। गिरधर नागर अलौकिक है और मीराँ देहधारी नारी है। अतः यह भावभक्ति मानी गई।

सगुण भक्ति की अनुरागी

मीराँबाई को प्रायः निर्गुण संतों की श्रेणी में रखा जाता है, परंतु उनका जीवन और रचनाएँ सगुण भक्ति की प्रतीक हैं। उनकी उपासना का आधार मूर्ति पूजा, नृत्य, गायन और स्मरण था। उनकी प्रसिद्ध पंक्ति, "म्हारे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिरमोर मुकुट म्हारो पति सोई" सगुण भक्ति के विश्वास को प्रमाणित करती है।

विषपान और भक्ति का चमत्कार

मीराँबाई की भक्ति को लेकर उनके देवर मेवाड़ के शासक विक्रमादित्य ने अनेक अवसरों पर आपत्ति जताई। उन्होंने पंडितों से विष देकर मीराँबाई को समाप्त करने का प्रयास किया। विष को चरणामृत बताकर मीराँबाई को दिया गया, परंतु उनकी कृष्ण भक्ति के कारण विष का प्रभाव निष्फल हो गया। यह घटना उनकी भक्ति की शक्ति और चमत्कारिक प्रभाव को दर्शाती है।

वृंदावन और द्वारका : जीवन का अंतिम चरण

चित्तौड़ में 17 वर्षों तक रहने के बाद मीराँबाई अपने उपास्य के निजधाम वृंदावन और फिर द्वारका चली गईं। द्वारका में रणछोड़ राय मंदिर में उनकी भक्ति चरम पर थी। कहा जाता है कि उनके परिजनों ने उन्हें वापस लाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर मूर्ति में विलीन हो गई। ऐसी भक्तों की मान्यता है। मीराँबाई का स्वर्गवास विक्रमी संवत 1604 में हुआ और उनका दाह संस्कार द्वारका के गोमती घाट पर किया गया।

वृंदावन

मीराँबाई की पदावली : साहित्यिक धरोहर

मीराँबाई की पदावली भक्ति साहित्य की अनमोल धरोहर है। गुजरात के "डाकोर" की हस्तलिखित प्रति में 110 पद उपलब्ध हैं ।उनके पदों में सहजता, भक्ति, और कृष्ण प्रेम का अनुपम समावेश है। विद्वानों का मानना है कि इन पदों का पुनः संपादन और शोध आवश्यक है, ताकि यह साहित्यिक धरोहर और अधिक उपयोगी बन सके।

मीराँबाई की कालजयी प्रेरणा : मीराँबाई का जीवन त्याग, भक्ति और साहस का अद्भुत संगम है। उन्होंने सामाजिक बंधनों और राजपरिवार की मर्यादाओं से ऊपर उठकर कृष्ण भक्ति को जीवन का उद्देश्य बनाया। उनकी रचनाएँ आज भी भक्ति साहित्य और भारतीय संस्कृति की पहचान हैं।

***विशेष उल्लेख:** यह आलेख प्रोफेसर डॉ. कल्याण सिंह शेखावत से हुई बातचीत और उनके शोध प्रबंध पर आधारित है। मीराँबाई के जीवन और साहित्य के पहलुओं को उजागर करने में प्रोफेसर शेखावत का योगदान अद्वितीय है। उनके शोध ने मीराँबाई की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता को नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है।

सदी का खलनायक
प्राण

सुधांशु टाक ✍ लेखक, समीक्षक

साल था 1940 । लाहौर की हीरा मंडी में राम लुभाया की पान की दुकान पर एक युवा पहुंचा। वह युवा प्रतिदिन रात्रि को भोजन के पश्चात पान खाने व सिगरेट पीने उसी दुकान पर जाता था। उस दिन भी वह युवा अपने विशेष अंदाज में पान चबाते हुए सिगरेट के धुएं के छल्ले बना रहा था। वह नहीं जानता था कि एक जोड़ी नज़रें उसके इस अंदाज को ध्यान से देख रही हैं और यह उनकी जिंदगी को बदलने वाला है । देखने वाले वह शख्स थे वली मोहम्मद , हिंदी फिल्मों के लेखक व निर्देशक। उन्होंने इस बांके नौजवान को देखा और उन्हें अपनी फिल्म "यमला जट्ट" के लिये खलनायक की छवि स्पष्ट दिखाई दी। उन्होंने उस युवा को 50 रुपये महावार की फिल्म में अभिनय की नौकरी का प्रस्ताव दिया, अपना कार्ड दिया और अगले दिन स्टूडियो में आने के लिये कहा। 50 रुपए उस जमाने में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। अतः उस युवा ने समझा कि यह एक मजाक है। वह नहीं गया। अगले सप्ताह वह युवा एक फिल्म देखने प्लाजा सिनेमा हाल में गया तो वहाँ उन्हें वली महोम्मद मिल गये। उन्होंने युवा को बहुत डांटा कि वह उनका दिन भर इंतजार करते रहे और वह युवा आया नहीं। उन्होंने उस युवा से उसके घर का पता लिया और अगले दिन वह कार लेकर सुबह 9 बजे युवा के घर पहुँच गए और उसको घर से लेकर अपने कार्यालय आ गये। कागज़ी कार्यवाही पूरी की। युवा ने शर्त रखी दी कि जिस दिन उनकी शूटिंग न होगी वह अपना फोटोग्राफी का काम करेंगे जिस पर हामी भर दी गयी। लेकिन वह दिन न आया। इस प्रकार 1940 में युवा की पहली पंजाबी फिल्म "यमला जट्ट" बन कर रिलीज हुई। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। वह युवा हिंदी फिल्मी इंडस्ट्री के सबसे खतरनाक और दिलदहलाऊ विलन के रूप में सामने आया । **उस विलन का नाम था प्राण**।

1960 के दशक में जब फिल्म रिलीज होती थी तो पार्श्व में बजते संगीत के साथ ही शुरु होता था फिल्म के नायक, नायिका, सहयोगी कलाकारों के नाम सिने पट पर आने का क्रम, और फिर एक धमाके की ध्वनि के साथ एक बिंदू रूप से अचानक उभर कर एक नाम आता था और "एंड प्राण" या "अबोव आल प्राण!" यह नाम जो किसी भी फिल्म की सफलता की निश्चितता का पर्याय बन गया था इसका इस प्रकार से विशेष उल्लेख होता था । रजतपट पर दशकों तक अपना साम्राज्य कायम करने वाले नायक, खलनायक, चरित्र अभिनेता, हास्य कलाकार जैसे अनेक पात्रों का रजतपट पर सशक्त अभिनय, प्रभावशाली स्वर से युक्त संवाद कला के साथ ही कुछ विशेष हाव भाव व किसी शारीरिक अंग से कुछ विशेष अदा, वेषभूषा द्वारा हर पात्र को सदाबहार व अविस्मरणीय बना देने वाले व्यक्ति को लोग प्राण के नाम से जानने लगे।

"यमला जट" प्राण की पहली फिल्म बनी और सुपरहिट रही। लाहौर फिल्म इंडस्ट्री में एक खलनायक के तौर पर उभरने वाले प्राण को हिंदी फिल्मों में पहला ब्रेक 1942 में फिल्म 'खानदान' से मिला। दलसुख पंचोली की इस फिल्म में उनकी एक्ट्रेस नूरजहां थीं। बंटवारे से पहले प्राण ने 22 फिल्मों में नेगेटिव रोल किया। वे उस समय के काफी चर्चित विलेन बन चुके थे। आजादी के बाद उन्होंने लाहौर छोड़ दिया और मुंबई आ गए। यह उनके लिये संघर्ष का समय था।

मुंबई आने के बाद प्राण को फिल्म 'जिद्दी' में रोल मिला था। इस फिल्म के लीड रोल में देवआनंद और कामिनी कौशल थे। 'जिद्दी' के बाद इस दशक की सभी फिल्मों में प्राण खलनायक के रोल में नजर आए। 1955 में दिलीप कुमार के साथ 'आजाद', 'मधुमती', 'देवदास', 'दिल दिया दर्द लिया', 'राम और श्याम' और 'आदमी' नामक फिल्मों के किरदार महत्वपूर्ण रहे तो देव आनंद के साथ 'मुनीमजी' (1955), 'अमरदीप' (1958) जैसी फिल्में पसंद की गई।

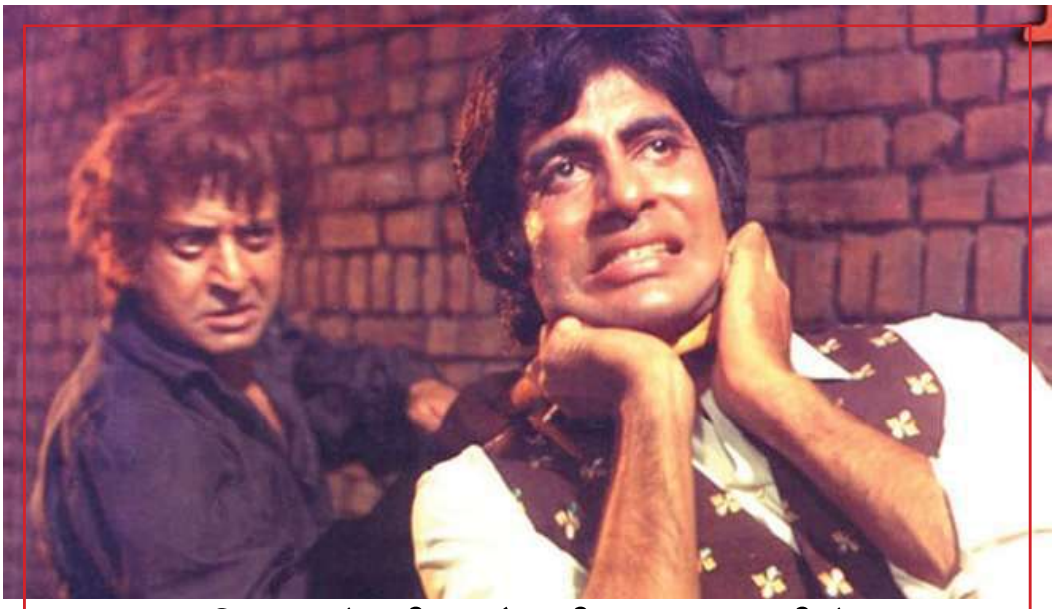

अमिताभ को एंग्री यंगमैन की उपमा प्राण की देन

अमिताभ बच्चन के करियर को संवारने वाली फिल्म जंजीर पहले धर्मेंद्र, देव आनंद और राजकुमार को ऑफर हुई थी, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर-डायरेक्टर प्रकाश मेहरा इस फिल्म को इन तीनों में से किसी के साथ भी फ्लोर पर नहीं ला पाए। जब तीनों ने 'जंजीर' को ठुकरा दिया तो एक दिन प्राण ने प्रकाश मेहरा को अमिताभ बच्चन को फिल्म में लेने की सलाह दी। मेहरा के मुताबिक,
"प्राण ने मुझसे कहा था कि अमिताभ को 'बॉम्बे टू गोवा' में देखने के बाद मुझे लगता है कि वह फ्यूचर स्टार है।"

प्राण का परिवार... प्राण का जन्म दिल्ली बल्लीमारान के एक खानदानी रईस परिवार में हुआ था। प्राण के पिता लाला केवल कृष्ण सिकंद पेशे से सिविल इंजीनियर थे। वो ब्रिटिश सरकार के दौरान सरकारी निर्माण का ठेका लिया करते थे। केवल कृष्ण सरकारी इमारतों, सड़कों और पुल निर्माण में महारत रखते थे। प्राण ने 1945 में शुक्ला अहलूवालिया से शादी की थी। उनके 3 बच्चे हैं। दो बेटे अरविंद और सुनील सिकंद और एक बेटी पिंकी है।

पसंदीदा फिल्म-पसंदीदा डायलॉग

प्राण की स्वयं की सबसे पसंदीदा फिल्म "हलाकू" थी । अपने एक साक्षात्कार में प्राण ने कहा था " "मेरी सबसे पसंदीदा फिल्म 'हलाकू' है। इसके एक सीन में मुझे हीरोइन को खंजर से मारना था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और मैं खंजर फेंककर वजीर से कहता हूं 'नीलोफर ने बदतमीजी की और हम सजा भी न दे सके'। वहीं, सबसे यादगार डायलॉग फिल्म 'कश्मीर की कली' का है। इस फिल्म में मैं 'श' को 'स' और 'स' को 'श' बोलता हूं। फिल्म में मैं हीरोइन से बोलता हूं, 'शताले-शताले चंपा, कभी तो अपना भी शमय आएगा' ये पसंदीदा डायलॉग है।"

शिद्दत से निभाते किरदार

प्राण साहब एक बार दिल्ली में अपने दोस्त के घर चाय पीने गए। उस वक्त उनके दोस्त की छोटी बहन कॉलेज से वापस आई तो दोस्त ने उसे प्राण से मिलवाया। जब प्राण होटल लौटे तब दोस्त का फोन आया। उसने बताया कि उसकी बहन कह रही थी कि ऐसे बदमाश और गुंडे आदमी को घर क्यों लाते हो? दरअसल प्राण अपने किरदार को इतनी शिद्दत से निभाते थे कि लोग उन्हें रियल लाइफ में भी बुरा आदमी ही समझते थे। प्राण कहते थे कि उन्हें हीरो बनकर पेड़ के पीछे हीरोइन के साथ गाना गाना अच्छा नहीं लगता।

प्राण को 'सदी के खलनायक' की उपाधि से नवाजा गया। प्राण की कुटिल मुस्कान और आंखों से घूरना दर्शकों में खौफ पैदा कर देता था। करीब 3 दशक तक लोगों ने उनके नाम यानी 'प्राण' नाम से अपने बच्चों के नाम रखने तक बंद कर दिए थे।उनका तकिया कलाम 'बरखुरदार.....' हिंदी सिनेमा में आज भी उनकी याद दिला देता है।

प्राण को तीन बार फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला। 1997 में उन्हें फिल्मफेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट खिताब से नवाजा गया। प्राण को हिन्दी सिनेमा में उनके योगदान के लिए 2001 में भारत सरकार के पद्म भूषण और इसी साल दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था। प्राण ने तकरीबन 350 से अधिक फिल्मों में काम किया। कांपते पैरों की वजह से उन्होंने 1997 से लेकर अपने निधन तक जीवन व्हील चेयर पर गुजरा था ।

1967 में जब मनोज कुमार ने उन्हें फिल्म 'उपकार' में मलंग चाचा का चरित्र अभिनेता का रोल दिया तो प्रारम्भ में प्राण साहब भी घबरा रहे थे। फिर इस फिल्म में उन पर फिल्माया गया इंदीवर द्वारा रचित एक गीत भी था "कस्में वादे प्यार वफा सब, वादे हैं वादों का क्या"। इस फिल्म और गीत ने प्राण को परंपरागत विलन की इमेज से बाहर निकालकर बतौर चरित्र अभिनेता स्थापित कर दिया। इस गीत का भी रोचक किस्सा है। फिल्म के संगीतकार कल्याण जी आनंद जी थे। पर यह संगीतकार जोड़ी इस खूबसूरत गीत को प्राण साहब पर फिल्माने के विरुद्द थे। उनका विचार था कि प्राण साहब जो उस वक्त सबसे अधिक प्रसिद्द खलनायक थे उन पर यह गीत फिल्माने से यह गीत ही फ्लॉप हो जायेगा। इधर गायक किशोर कुमार को जब पता चला कि यह गीत प्राण साहब पर फिल्माया जायेगा तो उन्होंने कहा कि इससे मेरा कैरियर ही चौपट हो जायेगा। पर अभिनेता निर्माता निर्देशक मनोज कुमार अड़े रहे । किशोर दा ने मना किया तो मनोज कुमार ने यह गीत मन्नाडे जी से गवा दिया। मनोज कुमार का यह कदम एकदम सही साबित हुआ। मन्ना डे ने भी यह गीत क्या खूब गाया। यह गीत सुपर डुपर हिट रहा । फिल्म की सफलता में इसका भी बहुत योगदान रहा । आज भी यह गीत संगीत प्रेमियों को बहुत पसंद आता है और आज भी यह कानों में गूंजता है।

प्राण ने 12 जुलाई 2013 को मुम्बई के लीलावती अस्पताल में अन्तिम सांस ली। गौर करने वाली बात यह रही कि उनके जन्म और निधन की तारीख एक रही। प्राण का जन्म 12 फरवरी 1920 को पुरानी दिल्ली के बल्लीमारां के बेहद प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम प्राण कृष्ण सिकंद था। तो अभी 12 फरवरी को उनकी जयंती भी होगी और पुण्यतिथि भी। **'राजस्थान टुडे' परिवार की ओर से उनकी पुनीत आत्मा को विनम्र श्रद्धांजलि... शत शत नमन।**

सादगी व अनुशासन की मिसाल

तनसिंह

राजस्थान टुडे ब्यूरो

बीते पांच वर्षों में श्री क्षत्रिय युवक संघ की ओर से आयोजित तीन कार्यक्रमों की बड़ी चर्चा रही। श्री क्षत्रिय युवक संघ की हीरक जयंती पर जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में लाखों लोग शरीक हुए। इस कार्यक्रम का अनुशासन पूरे देश व दुनिया में चर्चा का विषय रहा। वर्ष 2024 में दिल्ली में संघ के संस्थापक तन सिंह की 100 वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अनुशासन व सद्भावना के मामले में इस कार्यक्रम की भी मिसाल दी गई। इसी तरह 25 जनवरी 2025 को तन सिंह स्मारक का लोकार्पण बाड़मेर में हुआ। इस कार्यक्रम में भी हजारों लोग शामिल हुए। अनुशासन के मामले में यह कार्यक्रम भी मिसाल रहा। महान शख्सियत तन सिंह के देश भर में लाखों अनुयायी है। हाल ही में आयोजित उनकी 101 में जयंती के उपलक्ष में हम उनके व्यक्तित्व से आपको रूबरू करवा रहे हैं

''आंधियां आएं और जो झुके नहीं, तूफान आवें पर जो टूटें नहीं, कांटे चुभे और जो रूके नहीं, आंहें और आंसू जो निकले तो उन्हें पीकर मुस्करा दे, नफरत के प्याले पीकर जो उन्हीं प्यालों में प्रेम का जल भर कर मनुहार करते हों, संसार उन्हीं के अप्रत्याशित व्यवहार को देखने के लिए रूका करता है। सुख और समृद्धि के संदेश लाने वालों को अपने दुख और द्वारिद्रय की कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए।'' तनसिंह द्वारा लिखित उक्त पंक्तियां उनके जीवन दर्शन को बखूबी बयां करती है।

तनसिंह - जीवन परिचय

तनसिंह का जन्म उनके ननिहाल बैरसियाला गांव (जैसलमेर) में माघ कृष्णा चतुर्थी संवत् 1924 में हुआ। 4 वर्ष की अल्पायु में पिता का साया सिर से उठ गया। माता मोतीकंवर ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद प्राथमिक शिक्षा पूरी करवाई। इसके पश्चात 1942 में चौपासनी स्कूल जोधपुर में प्रवेश लिया। कठिन परिश्रम से चौपासनी के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी बने। हाईस्कूल पास करने के लिए पिलानी पहुंचे। विषम परिस्थितियों के चलते तनसिंह ने स्वयं के हाथो से बर्तन साफ करना, सब्जियां उगाकर बेचना, बबूल के दातुन सहपाठियों को पहुंचाने का कार्य करने के साथ अध्ययन जारी रखा।

पिलानी से स्नातक शिक्षा में बाद 1949 में नागपुर से एलएलबी उत्तीर्ण की। इस साल बाड़मेर में वकालत का कार्य शुरू किया। इसी साल हुए नगरपालिका अध्यक्ष के चुनाव में तनसिंह निर्वाचित हुए। यहीं से उनके राजनीतिक जीवन की शुरूआत हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाने के विरोध में हुए आंदोलन में शरीक हुए। इस दौरान वे जेल भी गए। चौपासनी स्कूल अधिग्रहण के विरूद्ध आंदोलन में विशिष्ट भूमिका निभाई। 1955 व 1956 में भूस्वामी आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। पिलानी में अध्ययन के दौरान क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना की। एक अनूठी सामाजिक संस्कारमयी मनोवैज्ञानिक प्रणाली के द्वारा अनुशासित, सुसंस्कारित, देशभक्त व समर्पित कार्यकर्त्ता के निर्माण का दायित्व निभाया। तनसिंह ने राजस्थान में ही नहीं गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश हरियाणा में भी अलख जगाई। इसी का नतीजा है कि आज देश में लाखों क्षत्रिय युवक संघ के कार्यकर्त्ता संघ की विभिन्न गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। तनसिंह के सफल व्यक्तित्व के पीछे उनकी माता मोतीकंवर का हाथ रहा। विद्वान, लेखक, वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार, प्रखर राजनेता के साथ-साथ तनसिंह सच्चे देशभक्त भी थे। उनकी पहचान तरूण तपस्वी के रूप में थी। अपने जीवनकाल में तनसिंह ने एक दर्जन से अधिक पुस्तकें लिखीं, जो कर्त्तव्य पथ की ओर अग्रसर होने वालों के लिए पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाती है। अपने साथियों व सहपाठियों को आत्म साक्षात्कार के लिए आठ सूत्री संपूर्ण योग मार्ग का पाठ पढ़ाया। संगठन की उलझनों का बारीकी से विश्लेषण व समाधान कर बेजोड़ संगठन निर्माण की भूमिका तैयार की। पौष कृष्णा तीज संवत् 2035 तनदुसार 7 दिसम्बर, 1979 को 55 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। उनके जीवन का हर पहलू प्रेरणादायक रहा है।

नगरपालिका अध्यक्ष से सांसद तक का सफर

तनसिंह का राजनीतिक जीवन विविधतापूर्ण रहा। वे वर्ष 1949 से 1952 तक बाड़मेर नगरपालिका के अध्यक्ष रहे। इसी प्रकार 1952 से 1957 व 1957 से 1962 तक विधायक रहे। इस दौरान 1956 से 1957 तक वे राजस्थान विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता रहे। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट का उन्होंने 1962 से 1967 व 1977 से 1979 तक प्रतिनिधित्व किया। सांसद के रूप में उन्होंने अलग पहचान कायम की। सादा जीवन उच्च विचार के धनी तनसिंह ने जीवन भर समाज और मानवता की सेवा की। जीवन के 55 वर्षों में राजनैतिक, सामाजिक, साहित्यिक क्षेत्र में एक अनूठी मिसाल कायम की जिसे लोग सदियों तक याद रखेंगे। समाज की नई पौध में संगठन और जागरण ही नहीं बल्कि समाज के प्रति तड़पन और पीड़ा के भाव हृदय में पैदा किए। समाज को घने अंधकार से प्रकाश की ओर लाने का अनुकरणीय उदाहरण पेश किया।

धोती पहने सीमांत सांसद दिल्ली पहुंचे ....

बीबीसी ने तनसिंह के पहली बार संसद आगमन पर टिप्पणी की कि पांव में देश पगरखी, सिर पर साफा व धोती पहने सीमांत सांसद दिल्ली पहुंचे। तनसिंह की सादगी को लेकर राष्ट्रीय दैनिक ने ऐन एमपी इन पीओन डे स शीर्षक आलेख में उनकी सादगी का बखान किया। संसद में रहते इस युवा सांसद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू को प्रभावित किया। चीन ने जब भारत पर आक्रमण किया तब संसद में पण्डित नेहरू को जवाब देना भारी पड़ गया। समूचा विपक्ष उनके खिलाफ खड़ा था। यहां तक कि सत्ताधारी सदस्य भी उन्हें घेरने में लगे हुए थे। पण्डित नेहरू भावविह्वल हो गए। उस वक्त तनसिंह ने कहा कि आज देश को एकजुटता दिखाने की जरूरत है न कि पण्डित नहेरू की नुक्ताचीनी करने की। तनसिंह की इस बात से पण्डित नेहरू इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने संसद में उन्हें थैंक यू यंग मैन ... कह कर धन्यवाद ज्ञापित किया।

जीवन की ठोकरों को माना अपना सौभाग्य...

तनसिंह को किसी भौतिक पदार्थ की आकांक्षा नहीं रही। वे अपना जीवन देकर सबके लिए जीवन खरीदते रहे। पूर्ण गौरव के साथ आश्वस्त होकर वे जीवन तथा विश्वास प्राप्त करने के आकांक्षी रहें। उन्होंने अपने कर्त्तव्य को ही जीवन की सार्थकता और गहन उत्तरदायित्व समझा और पूर्ण रूप से तथा सदैव के लिए अपने आपको लक्ष्य से बांध लिया। समाज में अनुशासन की भावना जागृत करने के लिए वे जीवन पर्यन्त स्वयं आत्मानुशासन में बंधे रहे। वे कर्म को ही जीवन और अकर्मण्यता को मृत्यु मानते थे। उथल-पुथल और निराशा की घड़ियों को अपनी परीक्षा तथा जीवन की ठोकरों को अपना सौभाग्य माना। राजमहल की अपेक्षा झौंपड़ी में वे अधिक प्रसन्न रहते। साधना के क्षेत्र में उन्होंने भय, घृणा और लज्जा को तिलांजलि दे रखी थी। कठिनाईयों-विपत्तियों में, सुख में और दुख में भी वे अपने बंधुओं के बीच प्रसन्न रहते। अपने सहयोगियों के दोषों की अपेक्षा तनसिंह ने उनके गुणों का ही चिंतन किया तथा कभी किसी को बुरा नहीं बताया। बुरे की बुराई भी स्वयं ओढ़कर कहा कि हम सब एक से हैं। अपने साधना कुटुम्ब के हित के लिए अगर स्वयं को अपमान भी सहन करना पड़ा हो सहर्ष आगे बढ़कर ओढ़ लिया। उन्हें आवश्यकता भी थी तो ऐसे पात्रों की, जो समाज में जीवन जुटा सकें, गौरव जुटा सकें और सम्मान को जन साधारण में बांट सके। जिसका कुटुम्ब भी श्री क्षत्रिय युवक संघ के रूप में अनुठी रचना है। जिसकी एकता में पिता का वात्साल्य, मां की ममता, गुरू की कृपा, भगिनी का स्नहे, बंधु का बंधुत्व, पत्नी की परायणता, पुत्र की भक्ति और जीवन के समस्त कर्त्तव्याधिकारों की अनेक धाराएं समाई हुई थी। इस कौटुम्बीय जीवन में अलग उनकी कोई महत्वकांक्षा नहीं रही।

तनसिंह ने कौम की, भारत माँ की, गौरवमय उज्ज्वल संस्कृति की जैसे करवट बदल दी। वे किसी लकीर पर चलने वाले परंपरा पुरूष नहीं थे बल्कि स्वयं लकीर बनाते, विचारों के बीहड़ को काटकर साफ कर देते और अबाध गति से चलते रहते। वे कहीं नहीं ठहरें..... चलते रहे, क्योंकि उन्होंने सत्य को बाहर से नहीं भीतर से पकड़ा। उन्होंने व्यक्ति को महत्व नहीं दिया, गुणात्मक शक्ति को ही महत्व दिया। उनकी प्रस्तुति शब्दों और लेखों का विषय नहीं, अनुभूति का विषय है। उनका दर्शन त्याग, श्रम और भक्ति का ही दर्शन नहीं, क्रांति का ही दर्शन है। वस्तुतः वे सबल और सामर्थ्यवान थे पर सदा अकिंचन और साधारण ही बने रहे। वे संपन्नता का जीवन जी सकते थे पर ऐसे सुखों का त्याग कर एक साधारण व्यक्ति की तरह उम्र भर सादे वस्त्र, सादे भोजन और सादे रहन-सहन को ही उन्होंने अपनाया। इसी से समाज में एक सबल नेतृत्व का उदय हुआ। लोगों को आगे लाकर और स्वयं पीछे रहकर वे भावी नेतृत्व की संभावनाएं खोजते रहते थे। ऐसे सबल नेतृत्व का प्रभाव समाज के दीघकालीन हित में होता है, जिसकी भाषा में जीवन के स्थायी मूल्यों सहित व्यापक दृष्टिकोण चमकता है। उनके जैसे दुर्लभ व्यक्तित्व का निर्माण युग संधियों के काल में होता है। जिनके चुम्बकीय आकर्षण से देश, काल, पात्र की भिन्नताएं खो जाती है। भले ही आज तनसिंह का शरीर नहीं रहा, पर सत्य यह भी है कि वे गए भी नहीं है। एक नहीं, अनेकों स्वरूपों में सशरीर वे आज भी हमारे बीच हैं। उनका विचार यत्र-तत्र-सर्वत्र पनपता नजर आ रहा है। लोगों ने उन्हें चाहे अपने पूज्य, प्रणेता और मार्गदर्शक के रूप में देखा और वे भी उसे मार्ग पर चले पड़े, चल रहे हैं।

बाड़मेर-बालोतरा-जैसलमेर में बीजेपी का स्पष्ट संदेश

पार्टी बड़ी, व्यक्ति गौण

राजस्थान टुडे ब्यूरो

विपक्षी और विरोधी चीखते चिल्लाते रहे कि पर्ची से सरकार बनी , पर्ची से संगठन बना। लेकिन , बीजेपी के इन आवाज़ों को दरकिनार कर दिया।

बीजेपी ने संसदीय क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा में ऐतिहासिक संगठनात्मक निर्णय लेकर सभी को पार्टी के निर्णय पर सहमत कर दिया।

यह वो निर्णय था जिसने बड़ी बड़ी जातियों को जिनका वोट बैंक अकूत हो उनको ही प्रतिनिधित्व देने की बात की ध्वस्त कर दिया।

तीन जिलों से बनने वाली लोकसभा बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा जिसमें प्रमुख वोट बैंक जाट, मुसलमान एसटी-एससी वर्ग हैं।

यहां इस बार भी मुसलमानों को छोड़कर दो जातियों पर ज्यादा महत्व देने के कयास लगाए जा रहे थे।

जाट और मेघवाल जाति।

साथ में कुछ नाम रावणा राजपूत और राजपूत समाज से थे।

बाड़मेर की जिलाध्यक्ष सीट बीते विधानसभा चुनावों के बाद से कार्यवाहक और निष्क्रिय माने जाने वाले नेता के भरोसे थी।

दिल्ली और जयपुर में सरकार होने के बावजूद कार्यकर्ता हताश निराश थे। ऊपर से कार्यवाहक जिलाध्यक्ष का दायरा ऐसा जिसमें जिलाध्यक्ष और उनके कुछ लोगों के अलावा कोई कार्यकर्ता फिट नहीं बैठता। पार्टी ने इसे बेहद गंभीरता से लिया और अग्रवाल पंचायत में मदन दिलावर ने कार्यवाहक जिलाध्यक्ष को 1990 की मित्रता का उपहार विदाई के रूप में दे दिया। दिलीप पालीवाल विदाई का साफा सजाए हुए साफ़गोई से मानो कह रहे हो कि अपना काम अब 2014 के बाद इतना ही था।

बाड़मेर में संघ के चेहरे के रूप में जाने पहचाने अनंत बिश्नोई को बीजेपी का नया जिलाध्यक्ष बनाया गया हैं।

जिला अध्यक्ष बनाए जाने से पहले ही अनंत बिश्नोई के नाम की चर्चा बाड़मेर ही नहीं बल्कि राज्य भर में चल रही थी कि संभवतः बाड़मेर के नए जिला अध्यक्ष के रूप में उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप दी जाए।

हुआ भी कुछ ऐसा ही।

पार्टी की तरफ से कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर जिला अध्यक्ष के नाम की घोषणा करने के लिए बाड़मेर पहुंचे और उन्होंने बाड़मेर के सर्किट हाउस में पहले कुछ नेताओं के साथ औपचारिक कही जा रही बैठक में हिस्सा लिया और उसके बाद वह अग्रवाल पंचायत भवन पहुंचे।

कुछ देर के बाद कुर्ते की जेब से नाम निकला और इसकी घोषणा कर दी गई। वहां काफी चेहरे उदास और फ़क्क पड़े नजर आए। जो बीते कई महीनों से जिला अध्यक्ष बनाए जाने के आश्वासन के कारण खिले हुए थे। एकाएक कईयों का चेहरे का ग्लो सफेद पड़ता दिखा।

असल में बाड़मेर की राजनीति जातियों के आधार पर बीते कई वर्षों से राजनीति के परिणाम दे रही है।

ऐसे में कयास इस बात को लेकर लगाए जा रहे थे कि कोई ऐसा बड़ा वोट बैंक जो चुनाव में एकमुश्त पार्टी से जुड़कर फायदा पहुंचाए ऐसे ही निर्णय होंगे।

लेकिन हुआ थोड़ा अलग और उलट। 40 वर्ष के युवा को पार्टी की अनंत उम्मीदों का जिला सारथी बनाया हैं। यह बड़ी परीक्षा भी हैं।

इधर जैसलमेर में भी लॉबिंग करने वाले दरकिनार

बाड़मेर बालोतरा जैसलमेर 3 जिलों से बनी लोकसभा हैं। यहां राजनीतिक उठापटक भी देश की सुर्खियां बनती हैं। सीमावर्ती जैसलमेर जिले में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को नया अध्यक्ष पार्टी ने दे दिया है। पोकरण विधानसभा क्षेत्र के राजमथाई क्षेत्र निवासी दलपतराम मेघवाल को प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।
बीते मंगलवार को भाजपा के ट्रांसपोर्ट चौराहा स्थित कार्यालय में अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए आयोजित हुई विशेष बैठक में प्रदेश सरकार में कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रदेश नेतृत्व से आए नाम को मोबाइल में दिखाया और चुनाव अधिकारी बिहारीलाल विश्नोई ने दलपतराम के नाम की घोषणा कर दी। इस पर वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने तालियां बजा कर इस निर्णय का स्वागत किया। जैसलमेर में चुने गए अध्यक्ष सामान्य परिवार से संबंध रखते हैं।

बालोतरा में भी बहुत बड़ा फैसला

बड़े नाम एक तरफ भाजपा को रास आया भरत मोदी का नाम

ऐसा नहीं हैं कि आश्चर्य मिश्रित आवाजें बाड़मेर से ही आई हो। संसदीय क्षेत्र के बालोतरा जिले से भी भरत मोदी का नाम जिलाध्यक्ष के लिए घोषित हुआ तब भी लोग आश्चर्य चकित थे।भरत मोदी के बारे में कहा जाता हैं कि संगठन की खिंची लकीर के दायरे में रहकर वो काम करने वाले नेता हैं।

यहां निवर्तमान जिलाध्यक्ष बाबू सिंह राजपुरोहित के स्थान पर इन्हें पद पर बिठाया गया हैं।

मोदी के अलावा यहां कई नाम थे जो जिलाध्यक्ष की दौड़ में दौड़े जा रहे थे बिना किसी उम्मीद के। जबकि , शुरुआत से ऐसा लग रहा था कि बालोतरा में पार्टी का फैसला बहुत गंभीरता से होगा। हुआ भी ऐसा ही।

वैसे तो भरत मोदी की पहचान एक कपड़ा व्यवसायी की रही हैं। जिनका संगठनात्मक अनुभव , संघ एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों में सक्रियता ने उन्हें अलग पहचान दी।

भरत मोदी एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता और संगठन के प्रति निष्ठावान व्यक्तित्व माने जाते हैं । इन्होंने वर्ष 1990 से 2003 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) में स्वयंसेवक के रूप में कार्य किया और विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया। इसके बाद, 2003 में वे सीमा जनकल्याण समिति के जिला संयोजक बने।

भरत मोदी स्वदेशी जागरण मंच में जिला सहसंयोजक के रूप में कार्यरत रहे, साथ ही वे लघु उद्योग भारती की कार्यकारिणी में भी शामिल रहे। शिक्षा के क्षेत्र में भी उनकी सक्रियता रही, वे विद्या भारती के व्यवस्थापक पद पर कार्यरत रहे।

राजनीतिक और संगठनात्मक अनुभव की बात करें तो भरत मोदी ने 2015 में नगर महामंत्री का पद संभाला। इसके बाद 2019 से 2021 तक वे जिला मंत्री रहे और 2021 से 2023 तक जिला महामंत्री के पद पर कार्य किया। संगठन में उनकी कर्मठता और समर्पण को देखते हुए उन्हें आहोर विधानसभा प्रभारी बनाया गया।

उनकी निष्ठा और संगठन के प्रति समर्पण को देखते हुए प्रदेश नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताते हुए बालोतरा जिले का जिला अध्यक्ष घोषित किया। इस पद के लिए 5-6 अन्य दावेदार भी थे,जिसमें गोविंद सिंह राजपुरोहित कालूडी,अमराराम सुन्देशा, खेताराम प्रजापत, डुंगरराम देवासी सहित लोगो के नाम थे। लेकिन उनके संगठनात्मक कौशल और ईमानदारी के कारण प्रदेश नेतृत्व ने उन्हें इस महत्वपूर्ण दायित्व के लिए चुना।

भरत मोदी ने अपने पूरे कार्यकाल में संगठन के प्रति पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और एकाग्रचित्त होकर कार्य किया, जिसका परिणाम यह रहा कि उन्हें जिले के शीर्ष पद पर आसीन किया गया।

पीढ़ियों को प्रेरित करने वाली विरासत

सुभाष चंद्र बोस

गजेन्द्र सिंह शेखावत ✍ केंद्रीय संस्कृति मंत्री

> पराक्रम दिवस के अवसर पर, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती को रेखांकित करता है, हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके अपार योगदान और उनकी अदम्य भावना का सम्मान करते हैं, जो आज भी युवाओं को प्रेरित करती है।

सुभाष चंद्र बोस के जीवन और आदर्शों का उत्सव मनाने के लिए स्थापित, पराक्रम दिवस इस बात पर विचार करने का एक अवसर है कि हम उनके सिद्धांतों को अपनी व्यक्तिगत और राष्ट्रीय आकांक्षाओं के साथ कैसे एकीकृत कर सकते हैं। यह दिन, न केवल उनके बलिदान की याद दिलाता है, बल्कि कार्रवाई का आह्वान भी करता है तथा हमें साहस, निष्ठा और नेतृत्व के उनके सिद्धांतों को अपनाने का आग्रह करता है, ताकि एक समृद्ध, आत्मनिर्भर राष्ट्र का निर्माण किया जा सके।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, नेताजी के योगदान को संस्थागत रूप दिया गया है तथा इसे पहले से कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। वर्ष 2021 में, सरकार ने 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में नामित किया, जिससे नेताजी की विरासत का सम्मान करने के लिए वार्षिक राष्ट्रव्यापी समारोह सुनिश्चित हुआ। कर्त्तव्य पथ पुनर्विकास परियोजना के तहत इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा का अनावरण, उनके विजन के प्रति एक ऐतिहासिक श्रद्धांजलि थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे "भारतीय गौरव और संस्कृति के पुनरुत्थान" का प्रतीक घोषित किया, जो बोस के राष्ट्रवाद के आदर्शों के अनुरूप है।

इसके अलावा, नेताजी से जुड़ी 304 फाइलों को सार्वजनिक करना एक ऐतिहासिक कदम था, जिसने दशकों से चल रही अटकलों को खत्म कर दिया और जनता को उनके जीवन और कार्य से जुड़े महत्वपूर्ण रिकॉर्ड तक पहुंच प्रदान की। इसके अतिरिक्त, मणिपुर के मोइरंग में आईएनए मेमोरियल का पुनरुद्धार, जहां इंडियन नेशनल आर्मी ने पहली बार तिरंगा फहराया था, नेताजी की विरासत को संरक्षित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है।

माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने बोस के वैश्विक प्रभाव पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "नेताजी का जीवन स्वतंत्रता के लिए समर्पित था और उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी, जो आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से भरा हो।"

सुभाष बोस का जन्म कटक में एक सम्मानित परिवार में हुआ था। वे एक प्रतिभाशाली छात्र थे। कटक के रेवेनशॉ कॉलेजिएट स्कूल, कलकत्ता के प्रेसीडेंसी कॉलेज और भारतीय सिविल सेवा (आईसीएस) परीक्षा में उन्होंने अपने अध्ययन का बेहतरीन प्रदर्शन किया। देशभक्ति की गहरी भावना और अपने देश की सेवा करने की इच्छा से प्रेरित होकर, उन्होंने एक सम्मानजनक करियर की सुख-सुविधाओं को ठुकराते हुए आईसीएस से इस्तीफा देने का फैसला किया।

बाद में, उन्होंने देशभक्ति की भावना जगाने और देशवासियों के बीच स्वतंत्रता का संदेश फैलाने के लिए 1921 में 'स्वराज' नामक एक समाचार पत्र शुरू किया। नेताजी का स्वतंत्र भारत का सपना सिर्फ़ एक सपना नहीं था, बल्कि कार्रवाई का आह्वान था। जब वे 1941 में नज़रबंदी से भाग निकले और अंतरराष्ट्रीय समर्थन मांगा, तो यह सिर्फ़ एक रणनीतिक कदम नहीं था - यह दृढ़ संकल्प, सहनशीलता और जरूरत पड़ने पर अपरंपरागत रास्ते अपनाने की इच्छाशक्ति का एक साहसिक दावा था।

उन्होंने घोषणा की, "मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा," यह उनके इस विश्वास को दर्शाता है कि सच्ची आज़ादी के लिए सिर्फ़ शब्दों की नहीं, बल्कि कार्यों की भी जरूरत होती है। चाहे वह इंडियन नेशनल आर्मी (आईएनए) के निर्माण के ज़रिए हो या आज़ाद हिंद रेडियो पर उनके भाषणों के ज़रिए, बोस ने दिखाया कि आज़ादी हासिल करने के लिए सामूहिक प्रयास, बलिदान और प्रगति के व्यापक दृष्टिकोण में योगदान देने की इच्छा की ज़रूरत होती है। पूर्व ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली ने एक बयान में अंग्रेजों के भारत छोड़ने के कई कारण बताए, "उनमें से सबसे प्रमुख कारण था - नेताजी की सैन्य गतिविधियों के परिणामस्वरूप भारतीय सेना और नौसेना कर्मियों के बीच ब्रिटिश राज के प्रति वफादारी का कम होना।"

यद्यपि महात्मा गांधी के साथ उनके वैचारिक मतभेद जगजाहिर थे, लेकिन गांधी के सिद्धांतों के प्रति बोस का सम्मान अटल रहा और उनके विपरीत रास्ते उनके पृथक दृष्टिकोणों को उजागर करते थे। नेताजी ने 1939 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, लेकिन भारत की स्वतंत्रता की उनकी प्रतिबद्धता कभी कम नहीं हुई। आज के युवाओं के लिए, यह हमें अपने आदर्शों के प्रति सच्चे रहने का महत्व सिखाता है, भले ही आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा हो।

नेताजी ने आईएनए के भीतर "झांसी की रानी रेजिमेंट" का गठन करके "नारी शक्ति" के महत्व को मान्यता दी, एक पूरी तरह से महिला रेजिमेंट जिसने महिला सशक्तिकरण के प्रति उनके विश्वास को सुदृढ़ किया।

ये आदर्श माननीय प्रधानमंत्री के भारत के विज़न में अच्छी तरह से परिलक्षित होते हैं, जहाँ महिलाएँ देश के भविष्य को आकार देने में एक अभिन्न भूमिका निभाती हैं।

पराक्रम दिवस, नेताजी की अमर विरासत का एक वार्षिक अनुस्मारक आयोजन बन गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों से युक्त समारोहों के पिछले आयोजनों ने उनके योगदान को प्रतिष्ठा दी है, जिसमें कोलकाता और दिल्ली प्रमुख आयोजन स्थल हैं, जहाँ उनकी एकता और देशभक्ति की भावना सड़कों पर गूंजती थी। इस वर्ष, कटक में, इस कार्यक्रम का विशेष महत्व है, क्योंकि यह उनके मूल स्थान का सम्मान करता है।

एक ऐसी दुनिया में जो सुदृढ़ता और नवाचार की मांग करती है, उनकी जीवन गाथा युवाओं को एक विकसित भारत - एक आत्मनिर्भर, विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने और कार्य करने के लिए एक शक्तिशाली प्रेरणा के रूप में कार्य करती है। जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था, "सुभाष चंद्र बोस का नाम देशभक्ति की भावना जगाता है और राष्ट्र को साहस और निस्वार्थ भाव से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है।"

...आइए हम एक उज्ज्वल, मजबूत भविष्य के लिए मिलकर काम करके उनकी विरासत को आगे बढ़ाएं।

राजस्थान पत्रिका जोधपुर संस्करण के 46 वें स्थापना पर हार्दिक शुभकामनाएँ।

नव शिक्षा समाज द्वारा संचालित

SIR PRATAP VIDHI MAHAVIDYALAYA

A LEADING LAW COLLEGE IN WESTERN RAJASTHAN

Affiliated to Dr. Bhimrao Ambedkar Law University, Jaipur
Approved by bar council of India

LL.B

3 Years Programme
Eligibility- Graduation in Any Stream

B.A. LL.B

5 Years Programme
Eligibility- 12th in Any Stream

WHY CHOOSE US ?

- Affordable free Structure.
- Online Support Resources.
- Centrally Located.
- Rich Library with Law Journals, E-Journals and Research Facilities.
- Dedicated and Experienced Faculties.
- Attractive Scholarship Schemes for Meritorious and Needy Students.
- Interaction with Judges, Lawyers and Academicians.
- Active Legal Aid Cell.
- Moot Court Debates and Workshops.
- Interactive & Integrated Teaching Methodology with Regular Case Studies.
- Internship with Experienced and Senior Advocates and Law Firms

डॉ. शंभूसिंह राठौड़
प्रिंसिपल/
डायरेक्टर

MGH ROAD, JODHPUR- 342001 (Raj)

0291-2959866, 6378800229, 9414145735, 9460155558

info.spmjodh@gmail.com Facebook.com/sirpratapjod

For Online Registration Logon to : www.spvm.co.in

सर प्रताप कॉलेज

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त

- न्यूनतम फीस
- योग्य एवं अनुभवी व्याख्याताओं द्वारा अध्यापन
- ऑनलाईन शिक्षण व्यवस्था
- अंग्रेजी माध्यम की छात्राओं हेतु अलग व्यवस्था
- अत्याधुनिक पुस्तकालय
- ई-लाईब्रेरी की सुविधा
- सी.सी.टी.वी कैमरा युक्त कॉलेज परिसर

B.A.

नई शिक्षा नीति 2020
सेमेस्टर प्रणाली
के अनुरूप

इतिहास, राजनीति विज्ञान
समाज शास्त्र, भूगोल,
हिन्दी साहित्य, अर्थशास्त्र
लोक प्रशासन

MGH ROAD, JODHPUR- 342001 (Raj)

spcjodh@gmail.com 6378399366

गिरीश माथुर
अध्यक्ष

डी डी माथुर
सचिव

निर्मल माथुर
कोषाध्यक्ष

एवं समस्त कार्यकारिणी
सदस्य, नव शिक्षा समाज

SIR PRATAP SR. SEC. SCHOOL

Play Group To XII Hindi & English Medium

MGH ROAD, JODHPUR- 342001 (Raj) 0291-2632070

SIR PRATAP ENGLISH PRIMARY EDUCATION BRAIN SCHOOL

(An English Medium School)

Class Prep to 8th

Scan Me

LOCATION

कैंसर का ईलाज, हम हैं आपके साथ...

PET CT स्कैन मशीन

रेडियोथेरेपी मशीन

एक ही छत के नीचे कैंसर का निःशुल्क* सम्पूर्ण ईलाज

निःशुल्क रहने की व्यवस्था, आने जाने की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध

- कैंसर PET CT SCAN प्रतिदिन उपलब्ध
- कैंसर रेडियोथेरेपी (सिकाई) प्रतिदिन उपलब्ध
- कैंसर सर्जरी एवं दूरबीन ऑपरेशन
- कैंसर कीमोथेरेपी कैंसर इम्युनोथेरेपी
- CT Guided Biopsy/ FNAC IHC Mammography

डॉ. अभिषेक शर्मा
MD, DM (Medical Oncology)
कैंसर रोग विशेषज्ञ
पूर्व - टाटा मेमोरियल हॉस्पीटल, मुम्बई

डॉ. मोहित भारद्वाज
MBBS, MS, FMAS, CCEPS
M Ch Surgical Oncology (AIIMS)
कैंसर सर्जरी एवं दूरबीन कैंसर सर्जन

डॉ. मुकुल चोबीसा
MD AIIMS Jodhpur
रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट

डॉ. गौरव गहलोत
MBBS, MD
रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट

जोड़-घुटना, कूल्हा प्रत्यारोपण

डॉ. अमित शर्मा
MBBS, MS (Orthopedics)
Consultant Joint Replacement & Orthopedics Surgeon
Ex-Consultant Shalby Hospital, Ahmedabad

पश्चिमी राजस्थान में पहली बार 3D Augmented घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना MAA-YOJANA

RGHS राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनर्स एवं उनके आश्रितों के लिए

न्यूरो स्पाईन सर्जरी

दिमाग व रीढ़ की हड्डी के निःशुल्क ऑपरेशन

डॉ.राकेश कुमार सिहाग
MS Mch - न्यूरो एवम् स्पाइन सर्जरी
पूर्व चिकित्सक PGI Chandigarh
पूर्व चिकित्सक AIIMS Rishikesh

- एंडोस्कोपिक व माइक्रोस्कोपिक न्यूरो व स्पाइन सर्जरी
- ब्रेन ट्यूमर सर्जरी • लकवा • नसों की कमजोरी • स्ट्रोक यूनिट

ECHS, RGHS, CGHS, Indian Oil, Railways, ESIC, Oil India, ONGC, HPCL, EIL व सभी इंश्योरेन्स कम्पनी, TPA योजना में निःशुल्क कैंसर ईलाज उपलब्ध

गोयल हॉस्पीटल

रेजीडेंसी रोड़, जोधपुर (राज.)
www.goyalhospital.org

एस के जी कैंसर हॉस्पीटल

झालामण्ड, जोधपुर (झालामण्ड चौराहे से सिर्फ 3 कि.मी. दूरी पर)
www.skgcancerhospital.com

अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें - 7412025320, 8769707913